हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

02.03.2016/1100/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2668

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूं, शायद आपको याद होगा कि 2014 के पार्लियामैंट के चुनाव की आचार संहिता घोषित होने से कुछ मिनट या घंटे पहले 5 मार्च, 2014 को भारत सरकार के श्रम मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बतौर मुख्य अतिथि और आप सभी माननीय मंत्रिगण तथा उस समय की तत्कालीन लोक सभा की सांसद ने इस ई0एस0आई0सी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया था। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जिस दिन यह उद्घाटन किया,

जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1105/av/as/2

प्रश्न संख्या : 2668 क्रमागत

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : क्रमागत

जिस वक्त यह उद्‌घाटन किया उसके दूसरे दिन अखबारों में यह छपा कि मैडिकल कॉलेज और अस्पताल हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिला के लिए समर्पित तथा चालू हुआ। दिनांक 5 मार्च, 2014 को जब इसका विधिवत उद्‌घाटन हुआ क्या उस वक्त यह अस्पताल और कॉलेज फंक्शनल अवस्था में था? क्या इसके कोई दस्तावेज हैं? यदि है, तो क्या आप उससे इस हाउस को अवगत करवायेंगे? अब दो वर्ष होने जा रहे हैं। यह इतना प्रैसटीजियस कॉलेज किस आशा के साथ शुरू हुआ था और आपने उद्‌घाटन भी किया था। हिमाचल में ई0एस0आई0 मैडिकल कॉलेज व अस्पताल भी फंक्शनल हो और आगे चले उसमें आपने तथा आपकी सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं; मैं यह जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ माननीय सदस्य जी ने मण्डी के नेरचौक में बने ई0एस0आई0सी0 मैडिकल कॉलेज और अस्पताल के बारे में जानना चाहा है। यह ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2006-07 में जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी मण्डी में सैंट्रल जोन में मैडिकल कॉलेज देने का फैसला किया था। उसकी नोटिफिकेशन हो गई थी और वहां पर प्रींसिपल भी बैठ गया था। मगर with the change of government, then government decided to withdraw the notification और कहा कि हम इस मैडिकल कॉलेज को नहीं चला सकते हैं। इसके पीछे मण्डी में चार महीने चेन हंगर स्ट्राईक हुई। एजिटेशन हुआ और लोगों ने रास्ते रोके तथा उनके केस बने। मैं आपको बैक्ग्राउंड की बात बता रहा हूं। फिर हम दिल्ली गये, मेरे साथ विद्या स्टोक्स जी थी और वीरभद्र जी दिल्ली में मंत्री थे। वहां लेबर मिनिस्ट्री ने फैसला किया कि हम अपने हिन्दुस्तान में 12 ई0एस0आई0सी0 मैडिकल

कॉलेज चलायेंगे। उस वक्त स्टेट मिनिस्टर श्री ऑास्कर फर्नाडिंस जी थे। उन्होंने मण्डी को एक ई0एस0आई0सी0 मैडिकल

2.3.2016/1105/av/as/3

कॉलेज दिया जिसमें प्रिवियस गवर्नमैंट का और उस वक्त रहे मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी का भी योगदान था और उन्होंने कहा कि मण्डी को यह कॉलेज मिलना चाहिए। उसका शिलान्यास भी ऑस्कर फर्नाडिंस ने किया। उस वक्त के माननीय मुख्य प्रेम कुमार धूमल जी भी वहां मौजूद थे और मैं भी था तथा विद्या स्टोक्स जी भी थी। उसका शिलान्यास हुआ। यह ठीक है कि जब यह मैडिकल कॉलेज तैयार हो गया तो 5 मार्च, 2014 को ऑस्कर फर्नाडिंस उस वक्त केबिनैट मिनिस्टर थे तब उसका उद्‌घाटन करने आए। वे मण्डी में 5 मार्च को ठीक पौने दस पहुंचे, दस बजे इसका उद्‌घाटन हुआ, 11 बजे मीटिंग भी खत्म हो गई और वे वापिस चंडीगढ़ चले गये। उस वक्त केवल मैडिकल कॉलेज का उद्‌घाटन हुआ था, अस्पताल का उद्‌घाटन नहीं हुआ था। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के नाते यह मांग की कि यह मैडिकल कॉलेज इसी साल चलना चाहिए। उसके बाद पार्लियामैंट के इलैक्शन हुए, सरकार बदली और केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने। उस वक्त तोमर साहब लेबर मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने पॉलिसी बदल दी है। एन.डी.ए. सरकार आई और उन्होने कहा कि हम ई0एस0आई0सी0 मैडिकल कॉलेज नहीं चलायेंगे। उन्होंने एक चिट्ठी युनियन गवर्नमैंट के मिनिस्टर को लिखी और एक हिमाचल सरकार को लिखी कि क्या आप इस मैडिकल कॉलेज को चलाना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं, and we responded positively.

Contd. By TCV----

02.03.2016/1110/TCV/DC/1

प्रश्न संख्याः 2668-- क्रमागत
मा0 स्वास्थ्य मंत्री--- जारी

हमने कहा कि हम इसको चलाना चाहते हैं, लेकिन अब आप बताईये कि इसके लिए आपकी टर्म एण्ड कंडीशन्ज़ क्या होगी? फिर इसमें यह फैसला हो गया कि जब इस कॉलेज का शिलान्यास किया गया था तो इसके लिए 730 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट था। अभी तक इसमें 765 करोड़ रूपये खर्च हो चुकें है। फिर सरकार ने कहा है कि इसमें 285 करोड़ रूपये फर्निशिंग, इक्यूपमैंट और मशीनरी के लिए और खर्च होना हैं। उसको आप 10 किस्तों में 10 परसेंट इन्ट्रस्ट के साथ हमें वापिस करो। जहां तक इंट्रस्ट की बात थी, मैं तीन-चार बार व्यक्तिगत तौर पर श्री तोमर साहब को मिला और उसके बाद श्री दतात्रे जो तेलगाना के स्टेट मिनिस्टर है, उनको मैं तीन बार व्यक्तिगत तौर पर मिला। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैल्थ ने सेक्रेटरी लेबर के साथ भी मीटिंग की और 2 फरवरी, 2016 को ये लॉस्ट मीटिंग हुई। उसमें हमने श्री दतात्रे को चिट्ठी भी लिखी कि "as is where is" जैसे हैं, जहां है उस बेसिज़ पर हम उसको लेने के लिए तैयार है और इसमें पैसा जितना भी लगेगा, हम अपने आप खर्च कर देंगे या फिर इंट्रस्ट आप मत लीजिए। अब सिर्फ इंट्रस्ट का झगड़ा है, बाकी सब कुछ हो चुका है। हमने मैडिकल कॉसिंल ऑफ इण्डिया को भी चिट्ठी लिख दी है कि अगस्त से हम इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब हम लॉस्ट स्टे्ज़ ऑफ नेगोशिएशन में हैं। अगर भारत सरकार इंट्रस्ट नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर हम इस कॉलेज को चलाएंगे और भारत सरकार काफी हद तक मान गई है। उनका लॉस्ट रिस्पोंस क्या होगा ? उसका हम इंतजार कर रहे हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसकी बैकग्राउंड बताई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन आपने 2006-07 को की थी उसकी डेट क्या थी? क्या यह सही नहीं है कि 10 अक्तूबर को इलैक्शन कमीशन ने प्रदेश में विधान सभा का चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी और 16 अक्तूबर को हैलीकॉप्टर से

आप बार-बार दिल्ली जाते रहे। जिस पर इलैक्शन कमीशन ने कहा कि यह खर्चा भी पार्टी को पड़ना चाहिए। जब इलैक्शन कमीशन नहीं माना तो 20 अक्तूबर को आपने बैक डेट में नोटिफिकेशन की

02.03.2016/1110/TCV/DC/2

समय की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैल्थ थी, उन पर कार्रवाई करने के लिए इलैक्शन कमीशन ने आर्डर किया। जैसे आज दिल्ली में अधिकारी कह रहे हैं कि इस केस में हमारे ऊपर दबाव डालकर करवाया गया था, ठीक उसी प्रकार से वह अधिकारी मेरे पास आकर रोई थीं। वह कह रही थी कि नोटिफिकेशन हो चुकी थी, कोड ऑफ कंडैक्ट लग चुका था और मेरे से बैकडेट में 22 अक्तूबर को अपलोड करवाया गया। क्या ये फैक्टस हैं, इनको आप आपनी फाईल से वेरिफाई करिए।

दूसरा, आपने आस्कर फर्नाडिस के बारे में कहा। मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने तो यहां तक किया कि मुख्य मंत्री का नाम नीचे होना चाहिए और आस्कर फर्नाडिस जो केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री थे, उनका नाम फाउंडेशन स्टोन पर ऊपर होना चाहिए। ये आज भी चैक किया जा सकता है। मैंने कहा मेरे प्रदेश को 800 करोड़ मिल रहा है। मेरा नाम लिखो न लिखो, जहां मर्जी लिख दो, लेकिन प्रोजैक्ट मिलना चाहिए। ऑस्कर फर्नाडिस ने आपके सामने अपने भाषण में कहा कि अगर आपको यह कॉलेज मिला है तो इसका सारा श्रेय धूमल साहब को जाता है। जिन्होंने एक रूपये की लीज़ पर ज़मीन हमको दी है। ये इनके भाषण का पार्ट था।

आर0के0एस0 द्वारा----- जारी

02.03.2016/1115/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2668..... क्रमागत

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल....क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, हम एक ही सोफे पर बैठ थे। ऑस्कर फर्नांडिज मेरे पार्लियामेंट के पुराने मित्र हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह कार्य इनके कारण हुआ। तीसरा प्वाईंट यह है कि आप उस प्रिंसिपल का नाम बताइए जिसको आपने उस कॉलेज का नोटिफिकेशन करके वहां बैठा दिया और वह किस तारीख को वहां बैठा था।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बात तो मानी की नोटिफिकेशन हुई थी और यह भी माना कि जब इलैक्शन की घोषणा हुई थी उसके बाद हुई है। लेकिन इसकी नोटिफिकेशन हो चुकी थी। जो प्रिंसिपल लगे थे मेरे पास उस वक्त सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लॉ, अर्बन डवेलपमैंट और पार्लियामेंट अफेयरज विभाग थे। I was not Health Minister at that time so I am not aware of the date of the notification when it was notified.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मैं यह मानता हूं। लेकिन आज तो आप हैल्थ मिनिस्टर है। रिकॉर्ड यहीं है और उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलैक्शन कमीशन ने कहा था। ये सारी बातें कलैरिफाई की जानी चाहिए। क्या आप इस बात के लिए सदन को आश्वस्त करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर इन बातों में आए तो बात बहुत लम्बी जाएगी। मेरे पास वह कैसट मौजूद है, जब नवम्बर, 2007 में विधान सभा के चुनाव हो रहे थे और धूमल साहिब ने सेरी मंच पर भाषण दिया कि मेरी सरकार आई तो मैं इसी वर्ष से इस कॉलेज को आरम्भ कर दूगां। हमने तो सिर्फ नॉटिफिकेशन की, प्रिंसिपल लगाया है। अगर ये इनकार करते हैं तो मैं उस कैसट को सदन के अंदर सुनाने को तैयार हूं। जहां तक नॉटिफिकेशन की बात है, हम वैरिफाई करेंगे कि कब नॉटिफिकेशन हुई थी

02.03.2016/1115/RKS/DC/2

और किस ऑफिसर पर इलैक्शन कमीशन ने कार्रवाई की थी। This is fact आप कह रहें हैं कि, आपका (धूमल जी का)नाम लिया। आप इतना तो कह देते कि श्रीमती विद्या स्टोक्स और मेरा(स्वयं मंत्री जी का) नाम भी उन्होंने लिया। ये बार-बार मेरे पास आते रहे कि एजिटेशन हुआ है। कैसट हम ला सकते हैं, उसका रिकॉर्ड भाषण मेरे पास है। जो आपने सेरी मंच पर भाषण दिया था क्या वह कैसेट आपको चाहिए? कौन सी कैसेट चाहिये आपको? मै कैसेट दे दूंगा कोई बात नहीं आपके भाषण की कैसेट भी दे दूंगा और उनके भाषण की कैसेट भी स्पीकर साहब को दे दूंगा। प्रश्न यह है कि ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज हमने चलाना है। इस बिल्डिंग के लिए यू0पी0ए0 सरकार ने पैसा दिया है। आप इस बात से क्यों इन्कार करते हैं? उन्होनें उस वक्त कहा था कि इस कॉलेज के लिए 730 करोड़ रुपये हमने सेंक्शन कर दिया है और यह यू0पी0ए0 सरकार की देने है। परन्तु जब आपकी एन0डी0ए0 सरकार आई तो मुखर गए कि हम इस मैडिकल कॉलेज को नहीं चलाएंगे। इस कॉलेज को केंद्र सरकार चलाएं। हमने अपनी जिम्मेदारी ऑन की है। हम इस कॉलेज को हिमाचल प्रदेश का एक मॉडल मैडिकल कॉलेज के रूप में चलाएंगे। एन0डी0ए0 सरकार से नैगोशिएशन हो रही है। हम इस कॉलेज को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक मैडिकल कॉलेज की बात है, एम0सी0आई0 की टीम वहां पर विजिट कर गई है और वह टीम मुझे सर्किट हाऊस में विजिट करने के बाद मिली थी। जो कमियां उन्होंने मुझे बताई, वे कमियां हमनें केंद्र सरकार के लेबर मिनिस्टर को बता दी है। Medical college can be functional only with approval of MCI. अगर एम0सी0 आई0 अगस्त में ही इसकी परमिशन देती है तो अगस्त में हम इस मैडिकल कॉलेज को चला देंगे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हम इसको चलाएंगे। And we take the responsibility. मैंने कई बार केंद्र के मंत्री से इस कॉलेज को चलाने के बारे में नेगोशिएशन की है। एडिस्नल

चीफ सैक्रेट्री हैल्थ, केंद्र के लेबर मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए 2-3 बार गए हैं। जो मैंने लेटैस्ट लैटर लिखा है कि अगर आप 285 करोड़ रुपया खर्च नहीं करना चाहते then on "as is where is" bases our government is ready to spend that

02.03.2016/1115/RKS/DC/3

money for the purchase of the equipment for the furnishing of the left out buildings.

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1120/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 2668 ... जारी

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ... जारी

इसलिए इसके लिए हम तैयार हैं। धूमल साहब, ऐसा है, हम स्टेट के इंट्रस्ट की बात करते हैं, जो एक्चुअल एंड फैक्चुअल पोजिशन है। इसमें गुलाब सिंह जी ने बड़ी लंबी भूमिका बनाई कि इलैक्शन होने थे। इलैक्शन 5 मार्च को 11.30 बजे अनाऊंस हुए; तब तक आस्कर फर्नाडीश जी हैलिकॉप्टर से चण्डीगढ़ पहुंच चुके थे। **इसलिए हम इस मैडिकल कॉलेज को चलाने के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं। आपको आश्वासन देते हैं कि जल्दी-से-जल्दी इस मैडिकल कॉलेज को चलाएंगे।**

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस प्रश्न के ऊपर पूरी राजनीति करने का प्रयास किया है। यह आज की ही बात नहीं है बल्कि ये लगातार ऐसा कर रहे हैं। निसंदेह उस समय सरकार UPA की थी लेकिन प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल जी के 100% प्रयासों के कारण यह ESI Medical College स्वीकृत हुआ।

माननीय कौल सिंह जी को तब रात के 11.00 बजे पता लगा जब मण्डी में प्रैस कांफ्रैस हो चुकी थी। अध्यक्ष जी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। वर्ष 2014 में जिस दिन यह उद्घाटन हुआ उस दिन कितने प्रोफ़ेसर, कितने असिस्टैंट प्रोफ़ेसर, कितने लैक्चरर्ज़ और कितना स्टॉफ वहां पर भर्ती किया जा चुका था? क्या आप उसकी लिस्ट हाऊस के टेबल पर रखेंगे। नंबर-2, क्या उस दिन तक आपके पास MCI की परमिशन या सैंक्शन आ चुकी थी या नहीं? अगर आपने स्टॉफ की भर्ती नहीं की थी और MCI की परमिशन नहीं आई थी तो आपने गलत तरीके से उस दिन इलैक्शन घोषणा के दौरान इसका उद्घाटन क्यों करवाया, यह बताएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कब कहा कि धूमल जी का योगदान नहीं था। आप क्यों बार-बार इस बात को उठा रहे हैं? मैंने कहा कि

02.03.2016/1120/SLS-AG-2

इनकी सरकार थी और धूमल साहब चीफ मीनिस्टर थे। उस समय मण्डी में ऐजिटेशन चला हुआ था और हम UPA सरकार के दौरान दिल्ली में मिलने गए। राजा साहब उस समय केंद्रीय मंत्री थे, विद्या स्टोक्स जी CLP Leader थी और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। इसलिए यह सबके प्रयासों से हुआ। मैं यह नहीं कहता कि इनका कोई प्रयास नहीं था। ऐजिटेशन मण्डी में चला था और 4 महीनों से ज्यादा समय से चेन हंगर स्ट्राइक हो रही थी। इसलिए मैंने कहा कि बिल्डिंग का उद्घाटन आस्कर फर्नाडीश जी ने किया जिसमें माननीय मुख्य मंत्री चीफ गैस्ट थे और मैं भी वहां था। आपने कहा कि चीफ मीनिस्टर के रूप में मेरा नाम ऊपर होना चाहिए। यह हमने नहीं किया था। जहां तक स्टॉफ की बात है, यह स्टॉफ हमने नहीं लगाना था, स्टॉफ की कुछ पोस्टें ESI Corporation Medical College ने भरी हैं। अभी तक यह कॉलेज ESI Corporation के पास ही है; अभी तक उन्होंने हमें यह विधिवत तौर पर हैंडओवर नहीं किया है। मैंने कहा कि MCI Team

आई थी और उन्होंने इंस्पैक्शन की। MCI Team सर्किट हाऊस में थी और मैं भी वहां था और वह लोग मुझे मिले। जो कमियां उन्होंने बताई थीं वह व्यक्तिगत तौर पर मैंने केंद्र के लेबर मीनिस्टर से कहा कि MCI Team ने यह कमियां बताई हैं, आप स्टॉफ भरिए। UPA Government ने यह फ़ैसला किया था कि हम मैडिकल कॉलेज चलाएंगे और NDA Government ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम मैडिकल कॉलेज नहीं चलाएंगे। उन्होंने हमको पत्र लिखा, हमने माना कि हम यह कॉलेज चलाने के लिए तैयार हैं और हम चलाएंगे। जैसे ही यह कॉलेज विधिवत तौर पर हैंड ओवर हो जाएगा, हम इसके लिए स्टॉफ देंगे और इसको विधिवत चलाएंगे। इसके अलावा मैडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है और बिल्डिंग का भी किया गया है। उस वक्त MCI ने इसकी कोई अप्रूवल नहीं दी थी। MCI Team तो उसके बाद मण्डी में आई। इसलिए इसमें राजनीति करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं धूमल साहब से चाहूंगा कि वह केंद्र के लेबर मीनिस्टर से कहें कि जो 10% ब्याज आप 285 करोड़ रुपये पर ले रहे हैं, उस ब्याज को माफ कर दिया जाए। यह कोई बनिये की दुकान नहीं है, यह स्टेट टू स्टेट गवनमैंट की बात है। हमारा झगड़ा केवल 10% को लेकर है जो वह मांग रहे

02.03.2016/1120/SLS-AG-3

हैं। हम कह रहे हैं कि 10% इंट्रस्ट नहीं देंगे। 285 करोड़ रुपया 10 सालों कि किश्त में हम देने के लिए तैयार हैं।

जारी ...गर्ग जी

02/03/2016/1125/RG/AG/1

प्रश्न सं. 2668--- क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी बातों में उलझ करके रह गए हैं। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसमें सिर्फ राजनीति करने के सिवाय

इनका मकसद कुछ और दिख नहीं रहा है और मैं मूल प्रश्न के उत्तर का अभी तक इन्तजार कर रहा हूं। मुझे आधा घण्टा हो गया। यह तो सच्चाई है कि इस कॉलेज का शिलान्यास भी बहुत ही कन्ट्रोवर्सी के साथ श्रेय लेने की दृष्टि से हुआ था और इसका उद्‌घाटन भी उसी तरीके से बहुत कन्ट्रोवर्सी के साथ हुआ था। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो आदरणीय ठाकुर गुलाब सिंह जी ने पहली बात पूछी कि जिस दिन इसका उद्‌घाटन किया गया, क्या यह कॉलेज उस दिन फंक्शनल होने की स्थिति में था? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि इसका उत्तर टेढ़ामेढ़ा आएगा।

अध्यक्ष : यह इसका उत्तर तो दे चुके हैं, वह तो ये पहले ही बोल चुके हैं।

श्री जय राम ठाकुर : उस वक्त तक न इसमें खिड़कियां व दरवाजे लगे थे, उसमें सिर्फ शटरिंग लगी हुई थी। दो साल होने को जा रहे हैं, उसका भवन का उद्‌घाटन दो साल पहले कर दिया, लेकिन आज की तारीख में हम स्वयं वहां जाकर आए हैं और आज भी वह बिल्डिंग फंक्शनल नहीं है। अभी तक वहां सैनेट्री की फिटिंग नहीं है, वहां पर अभी तक दरवाजे व खिड़कियां नहीं लगाई गईं, लेकिन उसके बावजूद उसका उद्‌घाटन किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या मन्शा रही? क्या यह भवन उस दिन तैयार था? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसका उद्‌घाटन करने के बाद आप लोगों ने कहा कि अगले साल, अभी कहा था कि आप अप्रैल के महीने से यहां पर कक्षाएं शुरू कर देंगे। एम.सी.आई. की टीम का ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या वहां आज की तारीख में, आज आप अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं, तो क्या अगस्त के महीने में भी वह बिल्डिंग अगर आपको एम.सी.आई. की अनुमति मिल जाती है, तो उस स्थिति में भी क्या आप कॉलेज शुरू करने की स्थिति में हैं?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका श्रेय लेने की बात आती है, तो आदरणीय धूमल जी मुख्य मंत्री के तौर पर थे, ये वहां थे, ये अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे, इन्होंने भी वहां भाषण दिया। जब इनका भाषण हुआ, उस समय मैं भी अपनी पार्टी का

02/03/2016/1125/RG/AG/2

अध्यक्ष था। उसके बाद मुझे भी वहां भाषण देने का मौका मिला। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाषण देंगे, तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी भाषण देंगे। हमने भी वहां भाषण दिया। लेकिन श्री ऑस्कर फर्नाडिस ने बड़े दो टूक शब्दों में बात कही, उन्होंने साफ बात कही कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं इन्होंने जमीन दी और पैसे लिए, लेकिन कितने पैसे लिए, एक रुपया लिया और एक रुपये की लीज पर इन्होंने जमीन दी। इसके लिए उन्होंने इनका धन्यवाद किया। इस बात को कहने में आपको क्या परेशानी हो रही है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि इस मैडिकल कॉलेज को राजनीति से बाहर निकालने की कोशिश करिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि अगस्त के महीने में यहां कक्षाएं शुरू हो जाएंगी? चाहे वह ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है उस कॉरपोरेशन के माध्यम से इसका करना है, तो उस तरह से इसको करें या फिर प्रदेश सरकार इसको अपने अधीन लेकर शुरू करे? तो क्या यह काम आप पूरा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो राजनीति की बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ एक बैक ग्रॉउन्ड बताई कि किस हालत में यह कॉलेज हुआ। मैंने कब कहा, मैंने तो कहा कि मुख्य मंत्री महोदय थे, इनकी सरकार थी और ये मुख्य मंत्री थे। पशु-पालन का एक फॉर्म था, यह 139 बीघा जमीन थी, एक रुपये की दर पर 99 साल के लिए सरकार ने यह जमीन भारत सरकार को दी। यह ठीक है कि जब उन्होंने इसका शिलान्यास किया, तो कन्ट्रोवर्सी कोई नहीं हुई। यह ठीक है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग वहां नारे लगा रहे थे, सरकार आपकी थी और ज्यादा नारे हमारी पार्टी के लग रहे थे, हम यहां विपक्ष में थे। धूमल साहब को इस बात का पता है फिर हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत किया और कहा कि नारे मत लगाओ। हमारे मुख्य मंत्री जी और केन्द्रीय मंत्री जी आए हैं। हमने उस समय मैडिकल कॉलेज के भवन का उद्घाटन किया। वह भवन पूरी तरह तैयार था और मुख्य मंत्री महोदय ने और हमने पूरे भवन का निरीक्षण किया। वह बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जहां तक दूसरी बिल्डिंग हैं जैसे मैं बता देना चाहता हूं और जहां तक हॉस्पीटल की बिल्डिंग है, स्टाफ क्वार्टर्ज हैं, वहां थियेटर

बनना है और एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनना है उस वक्त तक वह तैयार नहीं था। उन्होंने सिर्फ जो

02/03/2016/1125/RG/AG/3

मैडिकल कॉलेज के भवन का उद्‌घाटन किया।----(व्यवधान)---जय राम जी, आप चुप रहिए। आप यह बताइए कि आप मेरी चट्टिहर पंचायत में गए हैं। अभी तक भी वह स्कीम तैयार नहीं हुई है। आपको 250 लोगों ने रोका कि टैंक नहीं बने हैं, तो आप वहां उद्‌घाटन करने के लिए कैसे जा रहे हैं? आपको यह याद है कि नहीं?

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

02/03/2016/1130/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2668 क्रमागत-----स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

जयराम जी आप चुप रहिए। आप यह बताइए आप मेरी चैतीगढ़ पंचायत में गए थे। अभी तक वह स्कीम तैयार नहीं हुई है। आपको 250 लोगों ने रोका कि टैंक नहीं बने हुए हैं आप कैसे उद्‌घाटन करने जा रहे हैं। आपको याद है या नहीं? वह फोटो भी मौजूद है। -(व्यवधान)- नहीं, नहीं, आपने कहा कि कर देंगे। आपको लोगों ने खाना भी नहीं दिया। अधूरे कामों का उद्‌घाटन तो आप करते रहे हैं। मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं।। वह कॉलेज की बिल्डिंग बनकर पूरी तरह तैयार हुई तब हम लोग अंदर गए और सारा इन्सपैक्शन किया। अभी तक भी ई0एस0आई0 कारपोरेशन ने इस कॉलेज को हमें हैंडओवर नहीं किया है। इसलिए मैंने विपक्ष के नेता माननीय धूमल जी से अनुरोध किया है कि वे भी केन्द्र में बात करे क्योंकि सिर्फ 10 प्रतिशत इंट्रस्ट की बात है। 285 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत इंट्रस्ट यदि 10 साल के लिए देंगे तो कितना होगा। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि नेगोशिएसन फाइनल स्टेज पर है। इसमें हम आपसे भी मदद चाहते हैं। जब हम विपक्ष में होते थे तो आप हमारी मदद मांगते थे। हम भी मदद करने

को तैयार होते थे। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। आप यह बताइए, आपने एक दिन एक काम के लिए मुझे टेलीफोन किया कि जो 65 सीटें आई0जी0एम0सी0 की हैं और 50 सीटें डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की हैं, उसके बारे में आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद जी के पास फाइल है, आप उनसे बात कीजिए। मैंने उनसे बात की और आपको कन्वे भी किया। इस बात को आप शायद भूल गए होंगे तो पता नहीं है लेकिन ऐसा होता है। जब केन्द्र में हमारी पार्टी की सरकार होती है तो हम बात कर सकते हैं। अब केन्द्र में आपकी पार्टी की सरकार है तो हम कहते हैं कि 10 प्रतिशत इंट्रस्ट माफ करवा दो। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे। प्रदेश सरकार इस कॉलेज को टेकओवर करने के लिए तैयार है और नेगोशिएसन फाइनल स्टेज पर है। इसके लिए ई0एस0आई0 कारपोरेशन ने एम0सी0आई0 को एप्लाई कर दिया है और उसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी ही इसका फाइनल हो जाए और इस

02/03/2016/1130/MS/AS/2

मेडिकल कॉलेज को हम चलाएं। प्रदेश को तीन मेडिकल कॉलेज यू0पी0ए0 सरकार ने दिए। हमीरपुर में डॉ0 राधा कृष्णनन मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, चम्बा में पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और नाहन में डॉ0 यशवन्त सिंह परमार मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसलिए जिस सरकार ने जो दिया, हम उसका आभार मानते हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है। हम एहसान मानते हैं। आई0आई0टी0 मण्डी में कमांद में खुला। आप आए थे और श्री आनन्द शर्मा जी भी आए थे। वह भी हमारी यू0पी0ए0 सरकार की देन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कांगड़ा-धर्मशाला में खुलनी है वह भी यू0पी0ए0 सरकार की देन थी। माननीय चितम्बरम जी 2 अक्तूबर को यहां आए और उन्होंने यहां घोषणा की इसलिए अध्यक्ष जी I assure this House that we are ready to take over this college and make it functional at the earliest.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया है कि 10 प्रतिशत जो ब्याज लगना है वह न लगे, इसके लिए बात की जाए। प्रदेशहित में जो भी बात होगी

उसके लिए हमने सदन में भी और सदन के बाहर भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए अगर कुछ मिलता है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम उसका समर्थन करेंगे। आपने बहुत लम्बा भाषण दिया। लेकिन आपको याद दिलाऊं कि औद्योगिक पैकेज को 10 साल और बढ़ाने के लिए हमने विधान सभा में प्रस्ताव लाया था और आपके नेतृत्व में सभी वॉकआउट कर गए थे। मैंने इसी औद्योगिक पैकेज को बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी से समय लिया था। आदरणीय आडवाणी जी, सुषमा जी, जेटली जी और निशंक जी जो उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री हैं हम वहां जा रहे थे। मैंने वीरभद्र सिंह जी को फोन किया। ये उस समय केन्द्रीय मंत्री थे। इन्होंने कहा कि मेरा मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है। फिर मैंने विद्या स्टोक्स जी को फोन किया। इन्होंने कहा कि मैं व्यस्त हूं। आपने कहा कि आनन्द शर्मा जी आ रहे हैं तो आपका सहयोग कितना रहा है। जहां तक गुलाम नबी आजाद जी की बात है हम पार्लियामैंट में इकट्ठे थे। वे मेरे मित्र हैं। अगर आपने कहा होगा तो आपका भी धन्यवाद। लेकिन

02/03/2016/1130/MS/AS/3

प्रदेश को उसका लाभ हुआ था और सीटें बढ़ी थीं। इसलिए प्रदेशहित में जो भी होगा हम करेंगे। आपकी तरह वॉकआउट भी उस इशू पर नहीं करेंगे और बाईकॉट भी नहीं करेंगे।

अगला प्रश्न एस0एस0 द्वारा---

02.03.2016/1135/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2669

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और साथ में अब यह सूचना ठीक है या गलत है इस पर संशय है। लेकिन बधाई इसलिए दे रहा हूं कि बंदरों की संख्या जो 2005-06 में 3,17,112/- थी, आपने जो 2013 में गणना की उसमें आपने दर्शाया कि अब बंदरों की संख्या घट करके 2,26,086/- रह गई है। आपने इसके बाद जुलाई, 2015 में दोबारा

बंदरों की गणना की और इसमें आपने अपने उत्तर में कहा कि अब बंदरों की संख्या 2,07,614/- रह गई है। माननीय मंत्री जी हम इस हाउस में सभी विधायक बैठे हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में छाती पर हाथ रख कर कहो कि क्या हमारे चुनाव क्षेत्रों में बंदरों की संख्या घटी है या बढ़ी है।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने आज तक कितने वानरों की नसबंदी की और इन वानरों को जिन-जिन स्थानों से पकड़ा गया, आपने इस उत्तर में काफी डिटेल में लिखा है कि फलांनी-फलांनी जगह से पकड़े गये। आपने इसमें लिखा है कि कुछ रामपुर क्षेत्र से पकड़े गये। कुछ शिमला क्षेत्र से पकड़े गये। कुछ सुन्नी क्षेत्र से पकड़े गये। कुछ डलहौजी-चम्बा क्षेत्र से पकड़े गये। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जिन वानरों को आपने पकड़ा, उन वानरों को पकड़ करके जो आठ केन्द्र आपने यहां पर दर्शाये हैं उन केन्द्रों तक वानरों को किनकी गाड़ियों में ले गये? क्या फॉरैस्ट की गाड़ियों में ले गये या कोई प्राइवेट गाड़ियां कीं उनके अंदर ले गये? फिर एक वानर की नसबंदी करने के लिए कितना समय लगता है और कितना खर्चा वहां पर आता है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, लम्बा प्रश्न न कीजिये। Please be short. ब्रीफ में प्रश्न करिये। आपने प्रश्न लम्बा कर दिया। ब्रीफ में बोला जा सकता है।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, बहुत संगीन, संवेदनशील मामला है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र तथा सब जगह से संबंधित प्रश्न लगाया हुआ है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यह प्रश्न शुरू में लगाया है।

02.03.2016/1135/SS-AS/2

उसके बाद जब उन नसबंदी केन्द्रों से इन वानरों को आप वहां से उठा करके ले गये, आपने अपने उत्तर में कहा है कि जहां से हमने वानर पकड़े थे उनको वहीं पर छोड़ा है। क्या यह सत्य है? मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कितने वानरों की नसबंदी की और उस पर कितना खर्चा आया? खर्चे के साथ-साथ उन वानरों को कहां-कहां से उठाया और कहां-कहां ले गये?

जो 2005 की वानरों की संख्या है उससे 2015 की संख्या में लगभग कोई 40 परसैंट की कमी हुई है। हमारा मानना यह है, हम जो आपको आदरणीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि वानरों की संख्या लगभग 3 से 4 गुणा 2005 की गणना के बाद बढ़ी है। क्या आपकी सूचना सही है या हम हाउस के बीच में जो सदस्य बैठे हैं उनकी सूचना सही है, यह माननीय मंत्री जी बतलाएं।

वन मंत्री जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1140/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 2669 क्रमागत

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल याद है। इन्होंने यह जानना चाहा है कि वानरों की कुल संख्या कितनी है और उसमें से कितनों की वर्ष 2004 से 2015 तक नसबंदी की गई है। आज दिन तक 52404 बंदरों की नसबंदी की गई है और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त आठ मंकी स्टरलाईजेशन सैंटर काम कर रहे हैं। उनकी डिटेल दी हुई है, जहां-जहां से पकड़े वह डिटेल भी दी है और जो डिटेल दी है यह बिल्कुल ठीक है। माननीय महेन्द्र सिंह जी इस हाउस के सदस्य हैं तो मैं भी इसी हाउस का सदस्य हूं। मैं बहुत इंटीरियर से हूं जबकि माननीय सदस्य मेन रोड से हैं। यह काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे सौंपा है इसलिए जो भी असैसमैंट है, जो हमने पेपर ले डाउन किए हैं ये बिल्कुल ठीक है। एक-दो नीचे-ऊपर हो सकते हैं क्योंकि बढ़ोतरी होती रहती है और कमी भी होती रहती है। वर्ष 2014-15 में 18472 बंदर कम हुए हैं और वानरों की संख्या जैसे मैंने डिटेल दी है कि नसबंदी के बाद कम हुई है; यह भी एक अल्टरनेटिव है। दूसरा, इन्होंने फरमाया कि जहां से पकड़ कर ले जाते हैं। इस बारे में माननीय धूमल साहब ने भी मुझे टेलीफोन पर बताया था कि जहां से वानर ले जाते हैं उनको वहां नहीं छोड़ा जाता बल्कि उनको दूसरी जगह छोड़ा जाता है। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ मगर जब मैं दौरे पर जाता हूं तो ऐसी शिकायत लोग जरूर करते हैं। अभी मैं नूरपुर में एक जगह

दौरे पर गया था। वहां लोगों ने बताया कि प्रीवियस सरकार के समय ट्रकों-के-ट्रक बंदरों के भरकर आते थे और यहां छोड़ जाते थे। हमारे यहां निचली बैल्ट में वानरों का नामोनिशान नहीं था। ऐसा उस वक्त हुआ है। ये वानर प्रदेश की लोअर बैल्ट में ज्यादातर है, ऊपर की बैल्ट में नहीं है। हमने शिमला के वर्मिन हॉट-स्पॉट घोषित किए हैं। जुलाई, 2015 की गणना के मुताबिक केंद्र सरकार को वर्मिन घोषित करने के लिए उसका केस भेजा है। हमने हाई कोर्ट में वानरों की कलिंग की परमिशन के लिए केस किया हुआ है। उसमें हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है कि कलिंग की परमिशन नहीं दी जायेगी मगर इसके लिए दूसरे मीन्ज एण्ड मैयर्ज अपनाए जाएं। हम उसके लिए कोर्ट में दोबारा

2.3.2016/1140/av/dc/2

जा रहे हैं और मैंने अपने विभाग को कहा है कि दोबारा जाइए और हाई कोर्ट से रिक्वैस्ट कीजिए। यह समस्या स्कूल के बच्चों की, किसानों की तथा हम सबकी है। इसको सोल्व करने के लिए यही एक तरीका है। पहले जो वानर बाहर भेजे जाते थे वह एन.डी.ए. सरकार ने बंद किए। उसके लिए भी हम दोबारा से रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि जो भी जानवर इन्सान को खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको पहले की तरह बाहर भेजा जाए ताकि यह समस्या खत्म हो। जैसे आपकी चिन्ता है वैसे ही हमारी भी चिन्ता है। सारे हाउस की चिन्ता है और हमारी सरकार की भी चिन्ता है। हम यह चाहते हैं कि इनका ऐसा उपाय किया जाए जिससे किसानों / बागवानों सहित सबको रिलीफ मिले। उसके लिए अब हमने वानर वाटिकाओं की परमिशन ली है। पहले वानर वाटिकाओं के लिए सी.ए.जैड ए. परमिशन नहीं देता था, अब परमिशन मिल गई है। हमें चार जगह के लिए पैसा मिल गया है तथा उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 जगह क लिए और पैसा दिया है। हम जंगल में ही वानर वाटिकाएं/ नेचुरल हैबिटेट बनायेंगे। उसी में उनको खाना देंगे और उसी में फ्रूट प्लांट लगायेंगे तथा बंदरों को

उसमें डाल देंगे ताकि

टी सी द्वारा जारी

02.03.2016/1145/TCV/DC/1
प्रश्न संख्याः 2669 - क्रमागत
वन मंत्री----- जारी

लोगों/जमींदारों की समस्या खत्म हो जाये।

श्री महेन्द्र सिंहः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो आंकड़ा दिया कि आज तक 52,404 बन्दरों की नसबन्दी की गई। माननीय मंत्री जी इसी हाऊस के अन्दर 25 फरवरी, 2016 को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा गया और उस अभिभाषण में कहा गया है कि आपकी सरकार ने 1,02,870 बानरों की नसबंदी की है। क्या आपकी सूचना सही है? या जो महामहिम राज्यपाल महोदय को आपने लिखकर दिया, वह सूचना सही है।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं , आपने कहा कि इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया हुआ है। यदि माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे दिया हुआ है तो आपकी सरकार/ विभाग ने कितनी बार माननीय उच्च न्यायालय में जाकर प्रयास किया कि इन वानरों और जंगली जानवरों की वज़ह से कृषि का क्षेत्र, बागवानी का क्षेत्र टोटली तबाह हो चुका है। आपने तीसरी बात कही कि हम वाटिकायें बना रहें हैं। सवा तीन साल का समय आपका बीत चुका है अब जो बाकी समय आपका बचा है, वह माला जपने का समय है। यह समस्या अभी कोई तीन साल में पैदा नहीं हुई। बन्दरों की संख्या आपने 2005 में 3,17,212 बताई है। आप घटने की बात कह रहे हैं, हम कह रहें कि समस्या बढ़ी है। आप कह रहें है कि जहां से बन्दर पकड़े गये हैं, उनकी नसबन्दी/नलबन्दी की गई और उसके बाद उनको वहां छोड़ा है। हमारा आरोप आपके ऊपर है और आपने अपने जवाब में लिखा। हम कहते हैं कि जितने वानर पहले शिमला में हुआ करते थे, इस विधान सभा के चारों तरफ सैंकड़ों

बन्दर हुआ करते थे, आज यहां पर गिनती के बन्दर रह गये हैं। आपने यहां से जो बन्दर पकड़े उनको नसबन्दी करने के बाद नीचले क्षेत्रों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र हैं, वहां पर आपने उनको छोड़ा। यह हमारा आपके ऊपर आरोप है। माननीय अध्यक्ष जी हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आप बतायें आपने इस सूचना में लिखा है। आपने मेरे चुनाव क्षेत्र के बारे में कहा है कि हमने

02.03.2016/1145/TCV/DC/2

फलां-फलां क्षेत्रों/जगहों से वानर पकड़े हैं। मेरा आरोप है कि वहां कौन-सी वानर पकड़ने की टीमें गई थी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, वानरों को कोई रोक नहीं है कि वे एक विधान सभा क्षेत्र से दूसरे विधान सभा क्षेत्र में न जाये। आप रैलीवेंट बोलिए।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर एक ट्रक वानरों को पकड़ करके लाया और सड़क पर जो मज़दूर थे, उनसे पूछा गया कि आपके विधायक का घर कहां जैसे है? उन्होंने कहा कि चार किलोमीटर दूर है।

मुख्य मंत्रीः यह सरासर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय यह झूठ बोल रहे हैं।

Speaker: This is wrong. Not to be recorded. Don't say such things.

वन मंत्रीः सर, ये यहां भाषण देने आये हैं। भाषण हम भी देना जानते हैं। ये अपने आपको ज्यादा पाटेखां न समझें । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये झूठें हैं और आज दिन तक इन्होंने झूठ की राजनीति की है। ये क्वैश्चन को पॉलिटीसाईज्ड कर रहे हैं। They are politicizing the question. They are meant for this purpose? क्या ये लोगों के वैलफेयर की बात कर रहे है?

श्री आर0के0एस0 द्वारा----- जारी

02.03.2016/1150/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2669 क्रमागत

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, ये बात कोई पवाईंट स्कोर करने की नहीं है। समस्या बहुत गंभीर है। वास्तविक में जो आंकड़े हैं, वे मंत्री महोदय गलत हैं। आप छोड़ने की बात कह रहे हैं। आपने कहा कि नूरपुर में ट्रकों के ट्रक छोड़ दिए गए। यह कह कर आप अपने आप को पाटेखां मान रहे थे। इस बात के लिए मैंने आपको लिखकर भी दिया और फोन पर भी कहा। अध्यक्ष महोदय, जहां से बंदर पकड़े जा रहे हैं, उनकी नसबंदी करने के बाद जहां जाना चाहिए, वे वहां नहीं जा रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी आपको जांच करवाना चाहिए। बंदरों को छोड़ने का ठेका प्राईवेट कैरियर को दिया जाता है। मंत्री जी का आर्शिवाद और डिपार्टमेंट की मिलीभगत उसमें होती है। बंदर आसपास ही छोड़ दिए जाते हैं। आज हालत यह है कि प्रदेश में आप जहां भी नसबंदी केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। बजाय इसका स्वागत करने से कि इस समस्या से छूटकारा मिलेगा। लोगों का कहना है कि जहां बंदरों की नसबंदी होती है, वहीं उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस सदन में, मैं यह मांग कर रहा हूं कि यह फिगर रखी जाए कि कितने बंदर पकड़े गए, कितने बंदरों की नसबंदी की गई,और प्राईवेट कैरियरर्ज को छोड़ने के लिए कितना पैसा दिया गया?यह समस्या बहुत गंभीर है। आपके आर्शिवाद से आपके कर्मचारी इन बंदरो को हर कहीं छोड़ने का काम करवा रहे हैं। जो आपने वर्मिन डिक्लेयर करने की बात कही थी । मैंने परसों भी निवेदन किया था कि उसे सभा पटल पर ने करिए। कि आपको किन-किन स्थानों में इनको वर्मिन डिकलेयर करने के बारे में कहा है। दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी आपने एश्योर किया था, क्योंकि वन मंत्री जी तो गुस्से में है इसलिए मैं इनसे नहीं पूछंगा। वह है, हाई कोर्ट में जो मामला लम्बित पड़ा है। एक्ट में इन बंदरों को

02.03.2016/1150/RKS/AG/2

किल करने का प्रोविजन है। जो एज पर लॉ किए जा रहे थे, उनको रोकने के लिए हाई कॉर्ट ने स्टे दिया था। हर स्तर में आश्वासन दिया जाता है। सरकार सिरियसली फॉलोअप करके हाई कोर्ट से उस स्टे को वैकेट करवाए। मैं मानता हूं कि वास्तव में इतने बंदर मारने नहीं पडेंगे। जब फायर होता है तो वे बंदर डर के कारण अपने सुरक्षित क्षेत्रों में भाग जाते हैं। आपके हैबिटैट्स, आपके खेतों को छोड़ देते हैं। यह बात आप हाई कोर्ट में बताएं कि एक्चयूल में इतने बंदरों की किलिंग नहीं होगी। क्योंकि वे फायर से डर कर भाग जाते हैं। इस मामले को आप कब तक हाई कोर्ट के समक्ष उठाएंगे, ताकी समस्या का समाधान हो?

अध्यक्षः काफी हो गया।

वन मंत्रीः बहुत जल्दी हम इस मामले को हाई कोर्ट में उठाएंगे। जहां तक माननीय धूमल साहिब ने इलजाम लगाया है कि इसमें मंत्री की मिलीभगत है। It is not there. राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में ऐसा काम नहीं होता। न मिलीभगत होती है, न ऐसा काम होता है । इतनी घटीया राजनीति हम नहीं करते।

अध्यक्षः अब काफी हो गया। This is enough of this Question. The purpose of this Question is to get rid of the moneys.

मुख्य मंत्रीः यह समस्या बहुत गंभीर है। इसलिए सोचा गया है कि इसका क्या किया जाए? एक तो इनको मार दिया जाए, दूसरा यह है कि बिना मारे इनकी जो उत्पत्ति होती है उसको कम किया जाए। उत्पत्ति कम करने के भी दो तरीके हैं। एक तो यह है कि इनको इस प्रकार का खाना दिया जाए जिसे खाकर मादा बंदर के गर्भधारण करने के हार्मोंस बनना बंद हो जाए। इस पद्धति के द्वारा ट्रफालगर स्कयोर, लंदन में जहां बहुत कबूतर हुआ करते थे, वहां यह समस्या पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि कबूतरों को

मारना नहीं है। उन्होंने उनके दाने में वह दवाई मिलाई जिससे कबूतरों की संख्यां कंट्रोल हो गई। यह रास्ता भी ठीक है कि अगर इन्हें फायर करके मार दिया जाए तो यह भाग जाते हैं।

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1155/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 2669 ... जारी

माननीय मुख्यमंत्री ... जारी

इनको मारने पर कोई पाबंदी भी नहीं है। It is not protected that way. लेकिन रिलीजियस सैंटिमैंट है जिसके कारण ऐसा नहीं किया जाता। दूसरी तरीका यह है कि इनको पकड़ कर इनकी नशबंदी की जाए और फिर जहां से ऐसे बंदर पकड़े गए थे, वहीं पर उनको वापिस छोड़ा जाए। बंदर एक टोले में रहते हैं और ये सामाजिक होते हैं, इनकी एक hierarchy होती है। अगर वह वापिस आएगा तो उसी टोली में रहेगा। अगर आप बंदर को पूर्व से पकड़कर पश्चिम में छोड़ेंगे तो वह बंदर खुश नहीं रहता और उनकी social hierarchy टूट जाती है। यह नियमों के भी ख़िलाफ़ है। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि नशबंदी हुई है और हो रही है मगर उनको यह भी आदेश था कि जहां से बंदर पकड़े गए हैं, वहीं उनको वापिस छोड़ा जाए ताकि बंदर वापिस आकर अपने कबीले में रह सकें। सरकार का यह हरगिज आदेश नहीं है कि बंदर शिमला से पकड़ें और किसी दूसरी जगह छोड़ दिए जाएं या बंदर पकड़ा किसी और जगह से और छोड़ शिमला में दिया। लेकिन जिनको पकड़ने और वापिस छोड़ने का ठेका दिया जाता है, मैं मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कि वह गड़बड़ भी कर रहे हों। वजाये उसी जगह पर पहुंचाने के जहां से उन्होंने लाए थे, वह रास्ते में भी छोड़ते होंगे। This can be there. This can be stopped. इस बात के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। आज तक मैंने इसके ऊपर कई बार चर्चा की है। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैंने बातचीत की है

और पत्राचार भी किया है। उनका कहना यही है कि एक ही तरीका है, either you cull them or sterilize them and after sterilization the monkey concern should be sent back to his own place from where it has been taken. यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ऐसे कानूनी तौर पर मारने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन रिलीजियश सैंटिमैंट के कारण लोग इनको नहीं मारते। Otherwise it is not protected animal.

02.03.2016/1155/SLS-AG-2

Speaker: Next Question. (Interruption) इस प्रश्न पर बहुत चर्चा हो चुकी है। (Interruption) Don't make a political arena in this Question? This is a very serious Question which has been discussed. The Government is taking care to stop the monkey menace. काफी हो गया, अब आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)... Next Question, Shri Ram Kumar. (Interruption) Enough of this Question. No, I won't allow you. बहुत हो गया और इसी प्रश्न पर एक घंटा हो गया है। एक घंटे से यही प्रश्न हुआ है। We have dealt with one Question only in one hour. ...(व्यवधान)... कालिया जी, आप एक घंटे में तो बोल नहीं सके, अब लॉस्ट में बोल रहे हैं। You should have raised hand earlier. ...(व्यवधान)... You sit down. Sit down please. I will not allow you. You sit down. I will not allow you. For one hour you have not been speaking.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कालिया जी कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक कह रह हैं। One Member cannot monopolize the time of the House. He cannot monopolize. (विपक्ष के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) आप हर बात में खड़े हो जाते हैं और झूठ बोलते हैं। (Interruption)

Question Hour ends

Paper Laid by RG . .

02/03/2016/1200/RG/AS/1

सदन की समिति का प्रतिवेदन :

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **24वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

02/03/2016/1200/RG/AS/2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं अगला आईटम लूं, मैं सभी सदस्यगण से निवेदन करुंगा कि प्रश्नकाल को आप गंभीरता से लें और ब्रीफ में प्रश्न पूछें। उसका समाधान सरकार करेगी। लेकिन एक ही प्रश्न पर इतना समय न लगाएं। I will not allow. अब एक घण्टे में सिर्फ दो ही प्रश्न हुए हैं। I will order everybody to sit. अब कोई नाराज हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप मुझे ब्लेम नहीं करना। I will not give one hour for one question.

अब नियम-62 के अन्तर्गत श्री सतपाल सिंह सत्ती जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्तुत करेंगे और माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो दिनांक 24 फरवरी को जिला ऊना में गांव सानन में घटना घटित हुई है जिसमें अनेक लोग घायल हुए और दो लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर मैं सरकार का ध्यानार्षण करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 फरवरी को विधान सभा क्षेत्र ऊना के गांव सानन में गुरू रविदास जी के प्रकाशोत्सव के मौके के तीन दिन के पश्चात एक बड़ा सा कार्यक्रम मंदिर में रखा गया था। उस कार्यक्रम में सैंकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे थे। वह कार्यक्रम जिस मंदिर में था उसमें मंदिर के साथ ही हाई टेंशन वायर वहां से गुजरती है। अनेकों स्थान हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं यदि सरकार ध्यान देगी, तो लोगों के घरों के पास से, सामुदायिक केन्द्रों के पास से या ऐसे मंदिर, गुरूद्वारे जैसे धार्मिक स्थान जितने भी हैं वहां से इस तरह की तारें गुजरती हैं। अनेकों बार सरकार से लोग आग्रह भी करते हैं कि उनको बदला जाए। लेकिन विभाग की उदासीनता के रवैये के कारण या जैसे कई बार हमें उत्तर मिलता है, कोई भी लाईन चेंज करने के लिए विभाग के पास ऐसा कोई फण्ड नहीं होता है जिससे पोल चेंज किया जाए, शिफ्ट किया जाए या तारें शिफ्ट की जाएं। इसके लिए वे संबंधित लोगों से पैसे मांगते हैं जिसके कारण ऐसी खतरनाक तारें पब्लिक

02/03/2016/1200/RG/AS/3

प्लेसिज पर हैं। हम सब लोग गांवों में जाते हैं शहरों में घूमते हैं, तो अनेकों स्थान ऐसे हैं। उस मंदिर के बीच मे से प्रांगण में से ये तारें गुजरती हैं। जैसा आप जानते हैं कि मंदिर में झण्डा रस्म अदा करने के समय सुबह 11.00 बजे यह हादसा हुआ। इत्तिफाक से मैं भी उसी सानन गांव में एक शादी के कार्यक्रम में गया था। उधर से अभी गुजरे ही थे कि उसके 15-20 मिनट के बाद शोर पड़ गया कि तारें टूट गईं और लोगों को करेंट लग

गया। जब तक हम वहां वापस आए, तो ध्यान में आया कि 28-29 नौजवान साथी इसकी चपेट में आए हैं जिन्होंने उस लोहे के पोल को पकड़ा था। पोल टेढ़ा होकर तारों के ऊपर आ गया और दो नौजवान साथियों सुरजीत कुमार और संजीव कुमार की लगभग मौके पर ही मौत हो गई थी । क्योंकि वे छत के ऊपर चढ़े थे जहां से उन्होंने उस पोल को ऊपर से पकड़ करके वहां रखना था। वे तारों के पास थे, तारों में पोल लग गया जिसके कारण उन्हें पोल पकड़ते-पकड़ते करेंट लग गया। वह 11,000 वोलटेज की तार थी जिसके कारण मौके पर ही वे दम तोड़ गए और उसके साथ-साथ जिन्होंने नीचे पोल को पकड़ रखा था जब पोल तार के बीच में लगा, तो मुझे लगता है कि लोगो ने झटके से खींचा जिसके कारण तार ही टूटकर नीचे पड़ गया। उसमें अनेकों लोगों को करेंट लगा। भगवान का शुक्र है कि जब तार टूटी, तो पीछे से बिजली अपने आप ही बंद हो गई और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, नहीं तो तार गिरने के बाद शायद और भी ज्यादा कैजुल्टी वहां हो सकती थीं।

एस. द्वारा जारी

02/03/2016/1205/MS/AS/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी----------
मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो वहां पर लोगों की मौत हुई है, वैसे उनको सरकार ने सहयोग भी दिया है परन्तु उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उसके साथ-साथ जो 27 लोग घायल हुए हैं उनके ईलाज का सारा खर्च सरकार वहन करे। एक व्यक्ति को पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ भेजा था उसका भी अभी मुझे बताया गया कि वह ठीक है और उसको राहत मिली है। यह जो घटना घटी है जिसमें काफी

लोगों की मृत्यु हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार को सरकार सहयोग करे ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि विभाग द्वारा इसके लिए सर्वे करवाकर कोई योजना बनाई जाए क्योंकि अनेकों स्थानों पर इस तरह की तारें हैं और उन तारों को किनारे किया जाना जरूरी है। अध्यक्ष जी, आने वाले समय में एक और दुविधा इस विभाग के लिए आने वाली है क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोल और तारें लगाने नहीं देता है। वास्तव में अब जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है इसलिए सरकार को इस पर गहन चिन्तन करके कोई पॉलिसी लानी चाहिए। इसके अलावा एक और बात हो रही है कि जो पुराने समय से तारें जा रही हैं उन तारों के नीचे कई लोग मकान, मंदिर या गुरूद्धारा बना रहे हैं और ऐसा यदि होता है तो ऐसी घटनाएं होने के ज्यादा चांसिज रहते हैं। इसलिए सरकार इस तरह का कोई निर्णय ले कि जहां से हमारा यह सारा सिस्टम जाता है क्योंकि बिजली तो लोगों को मिलनी है तो बिजली के खम्भों के पास से कोई इस तरह की बिल्डिंग्ज का निर्माण न हो। इससे आने वाले समय में तारें उठाने का भी झंझट नहीं होगा और अगर तारें नहीं हटाई जाती हैं तो ऐसे हादसों से बचने की भी कोशिश की जाए। इसलिए कुछ विस्तार से जनता के हित में पॉलिसी बनाई जाए या उसके लिए सरकार लोगों को कोई मुआवजा दे क्योंकि इससे पहले तो सारी तारें और खम्भे वगैरह बिना किसी कम्पनसेशन के लोगों के खेतों में से गए हैं। इसलिए एक तो हम यह ध्यान में रखें और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अध्यक्ष जी यह भी रही है

02/03/2016/1205/MS/AS/2

कि कुछ व्यक्तियों ने इस घटना के ऊपर जातिवाद फैलाने की कोशिश की है। जब इस बात का पता चला कि तारें गिर गई हैं तो पूरा जिला एकदम इकट्ठा हो गया। वहां 40-50 लोग घायल हो गए। सब लोग बिना किसी भेदभाव और बिना राजनीतिक सीमाओं के वहां पहुंचे। जैसा मैंने बताया कि मैं भी उस गांव में था लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा,

तब तक मैक्सिमम लोगों को ले जा चुके थे। दो-तीन लोग वहां पर मंदिर में थे उनको हमने गाड़ी में बैठाकर पहुंचाया और तब तक पूरा प्रशासन, विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग और आम जनता सब सहयोग कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की। वहां पर लोगों ने नेशनल हाइवे बंद कर दिया और सरकारों के विरोध में जातिवाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस तरह की वहां घिनौनी हरकतें हुई हैं। जो इस तरह भाईचारे का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं ऐसे तत्वों को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की घटना किसी के भी परिवार में भी हो सकती है। अगर घटना मंदिर में हुई है तो उसमें वर्ष 1971 से वे तारें जा रही हैं। आज तक भी वहां फंक्शन होते थे लेकिन लोगों का वह बुरा दिन था। उस दिन जो लिखा था वह घटित हो गया। लेकिन उसको भी इस तरह से घुमा-फिराकर फिर समाज को परेशान करना सही नहीं है। वहां पर चार घण्टे का जाम लगा दिया। जिनकी मौतें हुईं या जो दाखिल हैं उनको दवाई मिले और ईलाज ठीक चले, उसकी ओर प्रशासन का ध्यान जा रहा था लेकिन बीच में प्रशासन को डिस्टर्ब किया गया क्योंकि प्रशासन तो जाम खुलवाने में लग गया। इस तरह सब लोग परेशान हो गए। तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज किसी का भी मन करता है तो वह बीच रास्ते/चौराहे में आकर बैठ जाता है और नेशनल हाइवे बंद कर देता है। इस तरह की घटना आपने हरियाणा में भी देखी होगी। वहां क्या-क्या हुआ है, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। ऐसे जो जैन्युअन आंदोलन हैं वे होने चाहिए। वैसे कई बार सरकार की भी गलती होती है लेकिन इसका जो राजनीति लाभ लेने की कोशिश की गई है उसकी भी मैं निन्दा करता हूं। जो लोग इसमें मरे हैं और घायल हुए हैं, मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह रहेगा कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए।

02/03/2016/1205/MS/AS/3

इसके साथ-साथ इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों और इनसे बचा जा सके, इस पर प्रशासन और प्रदेश का विभाग कोई रणनीति बनाकर लाए। इस पर मेरा इतना ही

आग्रह है। धन्यवाद।

मंत्री जी का जवाब एस0एस0 द्वारा-----

02.03.2016/1210/SS-AS/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार है-

यह दुःखद घटना 24 फरवरी, 2016 को प्रातः लगभग 11:00 बजे घटित हुई, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार दो लोग विद्युत प्रवाह के कारण मारे गए तथा लगभग 25 से 28 लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना गुरू रविदास मन्दिर परिसर में जमा भीड़ में से इन लोगों द्वारा धार्मिक झण्डा स्थापित करने के प्रयास में हुई। झण्डा एक पाईप में बांधा गया था जो पाईप लोगों से अनियन्त्रित होने के कारण मन्दिर परिसर के पास से गुजरती 11 के0 वी0 रायपुर लाईन के ऊपर गिर गई। मामले पर पुलिस स्टेशन, ऊना में एक एफ. आई. आर. पंजीकृत की गई है तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा कानून एवं नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 का सम्बन्ध है, यह 11 के0 वी0 विद्युत लाईन, विद्युत नियम, 1956 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बिछाई गई है। इस लाईन की ऊंचाई 7 मीटर है जो अपेक्षित ऊंचाई 4.57 मीटर से ज्यादा है। इसी प्रकार समस्तरीय/आड़ी दूरी 4 मीटर है जोकि विद्युत नियमों के अनुसार 1.33 मीटर अपेक्षित है। 11 के0 वी0 की यह लाईन झण्डा स्थापित करने के स्थान से लगभग 15 से 20 फुट की दूरी पर है। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगा कि यह 50 वर्ष पुरानी लाईन है जबकि मन्दिर का निर्माण केवल 10 से 15 वर्ष पहले ही हुआ है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 द्वारा इस प्रकार की दुर्घटना के खतरे के दृष्टिगत स्थानीय ग्राम पंचायत के आवेदन पर इस लाईन को बदलने का कार्य भी आरम्भ किया गया था परन्तु स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण उस कार्य को पूरा

नहीं किया जा सका। जून, 2014 में इस लाईन को बदलने का कार्य फिर से शुरू किया गया था जब दो खम्भों तथा स्टे सैट भी लगा दिए गए थे। लेकिन इस बार भी ग्रामीणों द्वारा इन खम्भों और स्टे सैट को उखाड़ दिया गया जिस कारण कार्य को पुनः बन्द करवाना प़डा।

02.03.2016/1210/SS-AS/2

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 द्वारा सम्बन्धित पंचायत से इस विषय को परस्पर बातचीत द्वारा हल करने का निवेदन किया गया है ताकि लाईन बदलने का कार्य फिर से आरम्भ किया जा सके। अभी तक इस मामले का हल नहीं निकल पाया है फिर भी प्रयास जारी हैं।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि यह दुर्घटना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 की लापरवाही के कारण घटित नहीं हुई है। फिर भी प्रकरण की उपयुक्त जाँच के लिए अधीक्षण अभियन्ता कांग़डा की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 द्वारा विभागीय समिति का गठन किया गया है जोकि दुर्घटना के सही कारणों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। **जांच रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 के यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको मैं अपनी ऐच्छिक निधि से 15-15 हजार रुपया दूंगा और 15-15 हजार रुपये आपने कर देना ताकि उनका ज़रा कुछ हो जाए।**

समाप्त

02.03.2016/1210/SS-AS/3

अध्यक्षः श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, दो लोगों की मौतें हुई हैं। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा जैसा आपने बोला है कि जो घायल हुए हैं उनको पैसा देंगे। मेरा यह कहना है कि उनके इलाज का जो खर्च है उसको सरकार वहन करे। उसके साथ-साथ जिनकी मौत हुई है उनके आश्रितों को सरकार उचित मुआवजा दे।

तीसरा, आपने ठीक बोला कि उस तार को बदलने की कोशिश दो बार हुई है। मैं उन दोनों स्पॉर्टस को जानता हूं। बैक वाला खम्भा कहीं दूसरी जगह जायेगा और जो बिल्कुल गेट पर पोल है वह कहीं दूसरी जगह जायेगा। लेकिन जिसका आगे खेत है वह नहीं होने देते हैं। कम-से-कम अगर पोल चेंज नहीं होते हैं तो हम उन तारों को केबल के रूप में चेंज कर सकते हैं ताकि उस मंदिर के ऊपर से केबल के रूप में तारें डाली जाएं और आने वाले समय में दोबारा से ऐसी घटना से बचा जा सके।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः **अध्यक्ष महोदय, इस सम्भावना के ऊपर काम किया जायेगा। जहां तक मुआवजे का संबंध है वह तो सी0एम0 साहब ने देना है। मैं इसके बारे में सी0एम0 साहब से बात करूंगा।**

मुख्य मंत्री जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1215/av/dc/1

मुख्य मंत्री : गवर्नमैंट से जो ऐसी घटना में मुआवजा मिलता है वह तो मिलेगा ही मगर एक बात जरूर है कि जो लोग मंदिर बनाते हैं या दूसरे धार्मिक स्थान बनाते हैं तो उनको ये सारी चीजें पहले देखनी चाहिए। उनको मंदिर ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां पर हाई टैंशन वायर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहां मर्जी है मंदिर बना दो और फिर तारों को सरकार बदलती रहे। कोई अनुशासन तो होना चाहिए। जहां मर्जी आए,

वहीं झंडा गाड़ दो और मंदिर बना दो। It is wrong thing. There should be social awareness. (---व्यवधान---) नहीं, यह आपने (श्री सतपाल सिंह सत्ती) कहा। जैसे मंत्री जी ने कहा कि तारें तो 30-40 साल पहले की है और मंदिर अभी हाल में दस साल पहले बना है। क्या वे कहीं और जगह मंदिर नहीं बना सकते थे? यह क्या बात हुई कि हमने मकान बना दिया, हमने मंदिर बना दिया, हमने मस्जिद बना दी और अब तारों को हटा दो; यह नहीं हो सकता।

2.3.2016/1215/av/dc/2

नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

अध्यक्ष : अब नियम 61 के तहत चर्चा होगी। जिसमें श्रीमती आशा कुमारी जी दिनांक 29 फरवरी, 2016 को उद्धरित प्रश्न संख्या 2165 के ऊपर चर्चा करेगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 61 के तहत दिनांक 29 फरवरी, 2016 को उतरित तारांकित प्रश्न संख्या 2615 के उत्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा उठाती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के लिए एक प्रश्न लगा था जो कि सिवरेज लाइन को लेकर के हैं। यह बड़े खेद की बात है कि 20 साल पहले जिस सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट और सिवरेज लाइन का ए0ए0 एण्ड ई0एस0 हो चुका है। बीस साल में उसकी एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस नहीं हुई और 20 साल में पैसा देने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ। अभी भी मुझे जो प्रश्न का उत्तर मिला उसमें वर्ष 1996 में तब भी यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय तब भी मुख्य मंत्री थे। इन्होंने उसके लिए बजट का प्रोविजन भी किया था, अभी भी है। अभी भी डिपोजिट में ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा तभी का दिया हुआ है जो कि आई.पी.एच. डिपार्टमैंट के पास मौजूद है। कोई भी शहर हो; अभी शिमला में जोडिंस

का आउट-ब्रेक हुआ। अन्य जगह भी फैला जिस पर इस सदन में भी चर्चा हुई। अगर हमारे शहरों में सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट ही नहीं लगेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल किस तरीके से रखा जायेगा। 20 साल से उसकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं हुई। यह जो सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगना है उसकी जहां तक मेरी जानकारी है उसका एक हैक्टेयर का एरिया वन भूमि के अंतर्गत आता है। एक हैक्टेयर के लिए एफ.सी.ए. क्लीयरैंस अगर 20 साल में आई.पी.एच. डिपार्टमैंट नहीं करवा पायेगी तो यह चिन्ता विषय है। जो स्कीम बीस साल पहले 8.50 करोड़ रुपये की थी मेरी जानकारी के मुताबिक वह

2.3.2016/1215/av/dc/3

अब 17 करोड़ रुपये की हो गई है यानि दोगुणा हो गई है। अगर इसका कार्य उस समय हो गया होता जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए 5.50 करोड़ रुपये दिए थे तो आज स्टेट को डबल पैसे देकर वह स्कीम न बनानी पड़ती। पाइपें खरीद ली गई और उसके लिए धूमल साहब के कार्यकाल में भी पैसे दे दिए गए। पैसे दिए गए मगर क्लीयरैंसिज नहीं ली गई। टैंडर लगाये गये। इसका दो बार टैंडर लगा और दोनों बार टैक्निकल रीजन के कारण कैंसिल हो गया। अभी फिर लगा हुआ है, टैंडर की प्रक्रिया जारी है। मगर वह फिर कैंसिल हो जायेगा क्योंकि इसकी एफ.सी.ए. क्लीयरैंस नहीं है। एक हैक्टेयर से नीचे की एफ.सी.ए. क्लीयरैंस लेने के लिए मैं नहीं समझती कि इतना समय लग सकता है। There is something wrong with the way the department is going about it. Either they are not serious or they don't know how to go about it. I think it is simply 0.98 hectares. आपने पाइपें खरीद ली। मेरी जानकारी के मुताबिक आपने 15 किलोमीटर तक की पाइपें खरीद कर रखी हुई है।

टीसी द्वारा जारी

02.03.2016/1220/TCV/AG/1

श्रीमती आशा कुमारी --- जारी

बीस साल पहले आपने मुख्य मंत्री महोदय जब पैसे दिए थे, तभी पाईपें ले ली गई थी। क्योंकि एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस नहीं हो सकी । इसके कारण दो बार इसका टेंडर रद्द हो चुका है, तीसरी बार अभी फिर लगा है। यह टेंडर कैसे थ्रू होगा, जब एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस ही नहीं हुई है। So, there is something wrong in it. इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति ये यहां पर यह इश्यू उठाया कि क्या आई0एण्डपी0एच0 और अर्बन डिवैल्पमेंट विभाग बैठ करके इसको सॉर्ट-आऊट करेंगे? क्योंकि यदि शहरी विकास मंत्री को हम इस प्रश्न को लगाते हैं तो इसमें शहरी विकास मंत्री क्या करेंगे? ये काम तो आई0एण्डपी0एच0 विभाग को करना है। जवाब ये देंगे और करना किसी और ने है। क्या दोनों विभाग आपस में बैठकर इसका हल नहीं निकाल सकते? इसका जो AA&ES बहुत पुराना था लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इसका 10 करोड़ का रिवाईज्ड AA&ES भी हुआ है। 8 से 10 और अब आपको एक और 17 करोड़ का रिवाइज्ड AA&ES देना पड़ेगा। आप रिवाइज्ड AA&ES दिए जा रहे है, लेकिन फॉरेस्ट क्लीयरेंस करवाते नहीं हैं। फॉरेस्ट क्लीयरेंस करवाने के लिए मेरा मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप कोई कमेटी बनायें। आप कुछ जांच करवाएं कि क्या कारण है कि आई0एण्डपी0एच0 डिर्पाटमैंट 0.98 हैक्टेयर वन भूमि को स्थानांतरित करवाने में असफल हैं? उसमें पेड़ कोई नहीं है। पेड़ हो भी तो 75 पेड़ तक डी0एफ0ओ0 की कम्पीटेंसी है। यदि यह केस डी0एफ0ओ0 के पास प्रोपर जाएगा तो यह डी0एफ0ओ0 ही कर देगा। मुझे उम्मीद है, अध्यक्ष महोदय कि डलहौजी शहर लगभग 164 वर्ष पुराना टाऊन है। बहुत खूबसूरत शहर है। इसका सीवरेज़ सिस्टम, जिसके लिए 20 साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी (श्री वीरभद्र सिंह जी) मुख्य मंत्री थे और ठाकुर कौल सिंह जी आईएण्डपी0एच0 मंत्री थे। इसका काम शुरू करवाने के लिए टोटल 8 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट था। 5 करोड़ रूपये आपने डिपॉजिट किए हुए हैं जिसमें 2.50 करोड़ रूपये अभी भी पड़े हुए हैं। यदि इसकी एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस हो जाती तो यह अभी तक स्कीम बनकर तैयार हो गई होती। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप इसको आई0एण्डपी0एच0 डिर्पाटमैंट के साथ मीटिंग करके इस काम को जल्दी चालू करवांये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

02.03.2016/1220/TCV/AG/2

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-61 के अन्तर्गत दिनांक 29 फरवरी, 2016 को उतरित तारांकित प्रश्न संख्याः 2615 के उत्तर के संदर्भ में जो चर्चा माननीय सदस्या लाई है। इन्होंने यहां पर जिन बातों का उल्लेख किया है, उनमें यह सही है कि 1996 में सीवरेज स्कीम डलहौजी की अप्रूव्ल भी गई और शिलान्यास भी हुआ। लेकिन तब से अब तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया, क्योंकि एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस नहीं हो पाई। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शहरी विकास विभाग का सवाल है, 2008-09 के बाद ये जो सीवरेज स्कीम्ज़ की फंडिंग है, यह शहरी विकास विभाग द्वारा आई0एण्डपी0एच0 विभाग को सीवरेज स्कीम एग्जिक्यूट करने के लिए की जाती है। जहां तक डलहौजी का सवाल है, 47 किलोमीटर लम्बी इसकी सीवरेज लाईन ले होनी थी और जब पैसा गया तो आईएण्डपी0एच0 विभाग ने वहां 12 किलोमीटर तक की पाईप खरीद कर रख दी। लेकिन पहले 4 ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित थे, उसके बाद फिर से आईएण्डपी0एच0 ने रिविज़िट किया और यह निर्णय लिया कि एक ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। लेकिन जहां यह ट्रीटमेंट प्लांट बनाना प्रस्तावित किया गया, वह वन भूमि होने के कारण जो उसकी क्लीयरेंस थी, वह भी आईएण्डपी0एच0 विभाग द्वारा ही ली जानी थी। तीन बार उन्होंने आवेदन किया। तीनों बार ऑब्जरवेशन्ज़ के साथ वह वापिस आ गया। जो टेंडरिंग ट्रीटमेंट प्लांट की होनी थी उसके लिए भी उसी दौरान टेंडर कॉल किए गये। दो बार तकनीकी कारणों के चलते वह भी कैंसल हुए। अब तीसरी बार टेंडर किए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इन्हीं सारी बातों को देखते हुए न केवल डलहौजी की सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट, बल्कि प्रदेश में जहां-जहां भी अर्बन डवैल्पमेंट से पैसा गया है, काफी जगह एफ0सी0ए0 के कारण काम नहीं हो पा रहा है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा----- जारी

02.03.2016/1225/RKS/AG/1

शहरी विकास मंत्री द्वारा... जारी

इसके लिए मेरी अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2015 को एक मिटिंग की गई थी, जिसमें सैक्रेट्री आई.पी.एच. सैक्रेट्री यू.डी., ई.एन. सी. आई. पी.एच. और अन्य अधिकारियों को मैंने बुलाया था। मैंने उनको कहा कि आई.पी.एच. विभाग से किन्ह कारणों से काम नहीं हो रहे हैं। कितना पैसा आपके पास लम्बित पड़ा है? लगभग 51 करोड़ रुयपा इनके पास अर्बन डवेलपमेंट का पेंडिग पड़ा हुआ है। यह पैसा किन कारणों से खर्च नहीं हो रहा है? हमने आई.पी.एच विभाग को यह भी कहा कि आप प्रायोरटाइज कर लीजिए, हम फंडिंग वापस लेकर के वहां दे देंगे, जो स्कीमें बनने वाली हैं। जब बाकी जगह की क्लीयरेंसिज आ जाएगी तो उनको हम प्रायोरटी में ले लेंगे। लेकिन यह पैसा आई.पी.एच. विभाग के पास जा चुका है और वहां से अभी तक वापिस नहीं आया है। इसके साथ ही हमने उसी मिटिंग में यह निर्णय लिया कि इन सभी स्कीमों को मोनिटर करने के लिए हर जिले में डिप्टी कमीशनर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह निर्णय दिनांक 9.10.2015 का है। इस निर्णय में संबंधित डिप्टी कमीशनर सारी सीवरेज की स्कीमों को अडंटिफाई करें और इनमें जो एफ.सी.ए. के कारण देरी हो रही है उसके लिए स्पीड अप करके आई.पी.एच. विभाग से टेक अप करें। माननीय सदस्य ने जो अभी कहा उसके बारे मे, मैं विस्तार में बताना चाहूंगा। आपने कहा कि जांच का विषय है। यह बात सही है। लेकिन इसमें सरकार के दो विभाग, शहरी विकास और आई.पी.एच. संलिप्त है। परन्तु जहां तक जांच का सवाल है।उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ही आदेश करेंगे। यह बात सही है कि जांच होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की वजह से देरी हुई है, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम आई.पी.एच. से बार-बार टेक अप कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द एफ.सी.ए. क्लीयरेंस लें और इसका टैण्डरिंग प्रोसैस पूरा करके इसका काम शुरू करें।

अध्यक्षः आप(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री) इसमें बोलना चाहेंगी।

02.03.2016/1225/RKS/AG/2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः हमारी विधायिका जी ने बहुत सही बात कही है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि काश ये बात मुझ तक भी कभी पहुंची होती, तो मेरे ख्याल में वह काम कहीं-न-कहीं हो जाता। कई बार हमारे अफसर भी काम में ढील बरतते हैं। मुझे यह मालूम नहीं कि वह अफसर कौन सा है। हमारे पास सारा हिमाचल प्रदेश पड़ा हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं, कमियां तो जरूर है। मैं आपको पूरा विश्वास देती हूं जैसा कि माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने भी कहा कि हम अफसरों को थोड़ा ढील दें तो वे काम में ढील बरतते हैं। अगर हमें काम के बारे में बताया नहीं जाएगा तो हमें सपना थोड़ा नहीं आएगा। आपने मुझे एक साल पहले ही बोल दिया होता तो मैं खुद ही इस बात को अपने तौर पर कर सकती थी। आपकी बात सही है कि जरूरत है और जरूरत होनी चाहिए। आप मुझे आज ही इत्तलाह भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए कौन सी लैंथ हैं, हम सब कर देंगे। आप हमारा विश्वास कीजिए। यह हमारा काम है, यह हमारी ड्यूटी है। आप चिंता मत कीजिए।

मुख्य मंत्रीः हम उनकी एक्पलेनेशन मांगेंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः जो वहां पर आपके ऑफिसर हैं, वे तो कुछ करें। आपके ऑफिसर वहां दूएं की तरह बैठे रहते हैं, यह क्या बात है?उनकी एक्पलेनेशन हम कॉल करा देंगे। आप कर सकते हैं तो आप करिए नहीं तो मैं करुंगी। मैं उनकी जरूर एक्पलेनेशन करूंगी।

अध्यक्षः आशा कुमारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अफसर मेरे नहीं है, सरकार के है। मैं माननीय मंत्री जी को इनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूं कि मुख्य मंत्री महोदय खुद डलहौजी आए थे। मुख्य मंत्री महोदय ने खुद अफसरों को भी हिदायत दी। उसके वाबजूद भी क्लीयरेंस नहीं हुई है।

मुख्य मंत्रीः जब मेरा नाम आ गया है, I will order inquiry into it.

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1230/SLS-AS-1

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्ष : अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी।

अब मैं श्री नन्द लाल (माननीय मुख्य संसदीय सचिव) को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी चर्चा शुरू करें।

02.03.2016/1230/SLS-AS-2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रविन्द्र सिंह : प्वायंट ऑफ ऑर्डर। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी जिसका समापन शाम को हुआ, उस समय अंतिम वक्ता सत्तापक्ष की ओर से श्री किशोरी लाल जी थे। जब वह अंतिम वक्ता थे तो आज शुरुआत हमारे पक्ष के माननीय सदस्य से होनी थी। कल भी हमारे दो वक्ता बोलने के लिए शेष थे।

अध्यक्ष : उनसे बुलवाएंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : श्री किशोरी लाल जी के बाद अगर वह कल ही बोल लेते तो ठीक थी।

आज जब आपके पास पिछले कल की लिस्ट पड़ी हुई है तो उनको पहले बुलवाइए। आज पक्ष की ओर से नहीं बल्कि हमारे वक्ता को पहले अवसर मिलना चाहिए था।

अध्यक्षः इसके बाद तो विपक्ष के सदस्य ने ही बोलना है।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास कल की सूची लंबित पड़ी हुई है।

अध्यक्षः कल की सूची समाप्त है। आज नई सूची बनी है। सूची रोज-की-रोज बनती है, कंटीन्यु नहीं होती।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप भी विपक्ष की बात को दबाना चाहते हैं। ये तो दबा ही रहे हैं लेकिन आप भी हमारी बात को नहीं सुनना चाहते। आप भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं।

02.03.2016/1230/SLS-AS-3

अध्यक्ष : ऐसा है, सूची कंटीन्यु नहीं करती। चर्चा के लिए सूची डे-टू-डे बेसिज पर बनती है। पिछली सूची इसमें नहीं चलती। ...(व्यवधान)... नंद लाल जी, आप बोलिए।

श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय सचिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2016 को इस माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, जिसका धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सी.पी.एस. श्री जगजीवन पाल जी ने और अनुसमर्थन श्री अजय महाजन जी माननीय विधायक ने किया, मैं भी महामहिम के धन्यवाद के लिए अपने आपको उस चर्चा में शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियां विशेष तौर पर वित्तीय वर्ष 2015-16 का ज़िक्र किया और उसको काफी सराहा है। यह बात भी सही है कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्य मंत्री महोदय

के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, यह सारा प्रदेश जानता है। समाज में सब तरह के जो लोग हैं और हर क्षेत्र के जो लोग हैं, उन सबको मालूम है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है। बावजूद इसके कि हमारी जो सैंट्रल स्पौंसर्ड स्कीम्ज हैं और स्टेट शेयर जो केंद्र सरकार से मिलना है, उसमें there is a drastic cut अध्यक्ष महोदय, जो विकास हिमाचल में हो रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल मुख्य मंत्री महोदय को जाता है, उनकी अपनी एक्सलैंट फाइनैंशियल मैनेजमैंट, लंबे राजनीतिक तजुर्बे का प्रमाण है। 6 बार मुख्य मंत्री रहते हुए इनका जो तजुर्बा है, उससे प्रदेश की छवि में बहुत बड़ा इज़ाफा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो विकास हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। इसमें चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ओल्ड एज या विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, सबके लिए यह विकास और लाभ की बात है। अध्यक्ष महोदय, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है।

जारी ...गर्ग जी

02/03/2016/1235/RG/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री नन्द लाल)-----क्रमागत

होता क्या है कि कोई प्रोजैक्ट आज शुरू हुआ, वह चार साल, तीन साल या दो साल में पूरा होगा, तो it is a continuous process आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2007 में जब सरकार बदली और वर्ष 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके बाद मैं अपने क्षेत्र की बात करुंगा in general there was complete brake on the development यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, तो जो अप्रूव्ड सड़कें थीं, स्वीकृत कार्य थे उन पर भी एक ब्रेक लग गया, nothing was done in those five years. उसमें कुछ भी इजाफा नहीं हुआ। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों ने जब मेनडेट दिया था, सरकार बनी, जो विकास करने थे वे नहीं हुए और पूरे प्रदेश का यही हाल हुआ। अब हमारा जो रामपुर का क्षेत्र था इसमें तो यह सब देखने का मिला। तो that

is the reason our friends are sitting that side today. क्योंकि विकास रुक गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद इस सदन में कुछ इस तरह के कमेन्ट्स आए कि वे अपने अभिभाषण में यह नहीं कहना चाहते थे, यह नहीं पढ़ना चाहते थे, वह नहीं पढ़ना चाहते थे और ऐसा कहा, वैसा कहा। मेरा इस मामले में यह मानना है कि Indian democracy is the oldest democracy in the world. It is based on certain conventions and traditions. This has ripened from the constitutions of the different countries of the world.

इसमें मेरा यह कहना है कि making this kind of remark, it is highly uncalled for मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सबको यह सीखना होगा, we have to be respectful for this kind of thing. It was a cherishable movement when His Excellency, the Governor addressing this august House. Therefore, I request that we have to respect this thing. Because he is above the party line. We must respect that thing. We cannot make this kind of comment.

अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने सरकार के चुनावी घोषणा-पत्र की बात की। कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा-पत्र था उसने इन पिछले तीन सालों में कितने वायदे पूरे हैं यह प्रदेश की जनता जानती है। अभी हमारे पास पौने दो साल हैं, बाकी का जो समय है, I am sure कि जो अभी काम करने को रहते हैं, कुछ और वायदे किए हैं उनको भी यह सरकार पूरा करेगी। यह भी मुझे एक विश्वास है।

02/03/2016/1235/RG/AS/2

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के विकास को हमारे विपक्ष के मित्र हजम नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए आप कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा-पत्र और कुछ समाचार-पत्रों की कटिंग लेकर ये यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। यह स्वीकार्य बात है और ईस्टाबिलिज्ड फैक्ट है कि पूरे हिमाचल में जिस तरह का काम हो रहा है, पिछले तीन सालों में यह एक अद्‌भुद विकास हुआ है। मैं कह रहा

हूं। It is their compulsion they have to oppose it, they have to criticize us. It is their right. लेकिन कुछ तथ्यों पर तो ये बोलें। they must have certain facts कि हां इस तरह का हमने यह किया था और आपने यह किया है। there has to be comparison they have got every right for comparison. लेकिन जब अपने समय में कुछ किया ही नहीं, तो कम्पेरीजन किस बात का? इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बात होती है। इनका एक अपना विज़न है। उसमें He believes in work and development. और इनका प्रायरटाइज करने का अपना तरीका है जिसकी वजह से यह हर विभाग में, हर सैक्शन में विकास का जो काम है, इसको ऊपर उठाने की जो बात है वही चलती है। यह इनकी अपनी सोच है। तो जैसा मैंने कहा कि विपक्ष को कम्पेरीजन का भी there is no right.
अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं उनके बारे में भी यहां जिक्र किया गया। इन लोगों का कहना था कि उनमें हुड़दंग हो गया। इसमें कहीं रोहड़ू एवं अन्य स्थानों का जिक्र किया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव हुए, अब आप अन्दाजा लगाइए कि 3,243 पंचायतों में चुनाव हुए। It was quite peaceful छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

02/03/2016/1240/MS/DC/1

श्री नन्द लाल जारी----------

हम मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़े शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुए और इन चुनावों में हमारी पार्टी के 70 प्रतिशत से अधिक लोग जीतकर आए। विपक्ष के लोगों का यह भी कहना था कि इन चुनावों को पार्टी टिकट पर करना चाहिए था। मगर मुझे लगता है कि अगर कहीं चुनाव पार्टी टिकट पर हुआ होता this percentage would

have gone up to 90-95%. अब हम सोशल इकॉनोमिक डवलपमैंट की बात करते हैं। इस तरह की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन, वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन या अपंग पैंशन है, ये सारी पैंशन्ज अगर बढ़ाई हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाई हैं। जिस तरह से सभी जिक्र कर रहे हैं कि 80 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए जो यह 1100/-रुपये पैंशन की है यह वास्तव में ही मील का पत्थर है। इससे इन लोगों को भी एक सहारा मिला है और इनको भी इस उम्र में आकर कुछ करने का मौका मिला है कि वे भी स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे।

अब आवास की बात करते हैं। नव निर्माण के लिए पैसा बढ़ाकर 75000/- रुपये किया है। इसी तरह से रिपेयर के लिए 25000/-रुपये का प्रोविजन किया है। इसके अलावा जो आवासहीन लोगों के लिए "राजीव आवास योजना" के तहत 1280 आवास स्वीकृत किए हैं और 2128 आवास "इंदिरा आवास योजना" के तहत लोगों को मिले हैं। उसके लिए भी हम सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं।
इसी तरह से महिला और बच्चों के विकास पर इस सरकार द्वारा बहुत ध्यान दिया जाता रहा है। इस वित्तीय वर्ष में इस हेतु मु0375.52 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। इसके अलावा जो महिला और बच्चों के लिए विभिन्न स्कीमें हैं उन पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्रा सैनानियों और उनके आश्रितों को

02/03/2016/1240/MS/DC/2

दी जाने वाली सम्मान राशि पर भी काफी खर्च किया जा रहा है। स्वतंत्रता सैनानियों की पुत्रियों एवं पौत्रियों के विवाह पर क्रमशः 51000/-रुपये और 21000/-रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

अध्यक्ष जी, शिक्षा के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी बातें कही हैं। यह

हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का प्राथमिकता का सब्जैक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बी0जे0पी0 की सरकार में रेशनेलाइजेशन के नाम पर 157 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। We talk about Right of Education, कि हर बच्चे को पढ़ने का हक है, उसको पढ़ना चाहिए लेकिन हमने स्कूल बंद कर दिए। This is something very strange. मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जैसे ही यह सरकार बनी, इन सभी स्कूलों को दुबारा से चलाया गया क्योंकि सरकार को कई बार बहुत कुछ देखना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी का शिक्षा के लिए विशेष ध्यान है। सरकार को यह देखना पड़ता है कि स्कूल खोलने के जो पैरामीटर्ज हैं चाहे वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी हो, number of students available in the school, ये सारे पैरामीटर्ज भी रिलैक्स करने पड़ते हैं और इन्होंने किए हैं। आज दूर-दराज़ का जो हमारा एरिया है वहां पर हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिला है क्योंकि जब हम एक बार बात कहते हैं कि उनको पढ़ने का हक है तो they have to give schools in the interiors, दूर-दराज के क्षेत्रों में, उसमें वह भी किया जाता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में कितने प्राइमरी स्कूल खोले गए और कितने मिडल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अपग्रेड हुए? उससे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बहुत सहुलियत हो गई है। खासकर जो दूर-दराज़ के क्षेत्रों में लड़कियां है उनको पढ़ने के लिए नजदीक सुविधा मिल गई है। जो कॉलेजिज खुले हैं वे भी दूर-दराज़ के गांव में खुले हैं जिससे लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला है और इससे साक्षरता दर भी बढ़ेगी। अब आसानी से वे अपनी पढ़ाई कर सकती हैं।

02/03/2016/1240/MS/DC/3

इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई। सब लोग कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हम यह बताना चाहेंगे, आप याद करो just before three months of assembly elections one college was announced in Nankhari; मेरे एरिया में सिर्फ तीन महीने पहले की बात है। उसमें क्या हुआ कि एक कॉलेज का लैक्चचर रामपुर से वहां डिप्यूट कर दिया। तीन बच्चे रामपुर से वहां डायरैक्ट कर दिए। No infrastructure , no system and you are talking about quality education ? आप

क्वालिटी एजूकेशन की बात कर रहे हैं? This was the arrangement.उसके बाद जब हमारी सरकार आई। कितने पीटीए टीचर्ज थे,

जारी श्री एस0एस0 द्वारा------

02.03.2016/1245/SS-DC/1

श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

जिन पर हमेशा खतरा बना रहता था क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उनके लिए कोई पॉलिसी बने। हम आज भी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जब उस वक्त अध्यापकों की कमी थी तो पी0टी0ए0 के लोग बहुत कम पैसे में दूर-दराज के क्षेत्रों जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। वे स्कूल चलते रहे। आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनके लिए पॉलिसी का इंतजाम किया है और इस तरह से स्कूल चल रहे हैं। जितनी भी रिटायरमैंटस होती है उसके लिए भी व्यवस्था की हुई है। आज हमारे यहां जो स्कूल मैनेजमैंट कमेटी है उनके द्वारा जो हमारे क्वालिफाइड नौजवान लड़के-लड़कियां घर में बैठे हैं they get chance to enroll there because they are eligible. जो उनकी क्वालिफिकेशन है वह पूरी है। उसको उन स्कूलों में भेजा जाए। वे वहां पर जा रहे हैं। जहां पर दो साल से जगह खाली पड़ी हुई है, एस0एम0सी0 के थ्रू उनको वहां नौकरी मिलती है और वे पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कई लोगों का कहना है कि यहां एक स्कूल में मास्टर नहीं हैं, दो स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, you see the number of schools we have और किस तरह से उनको एकोमोडेट किया जा रहा है। इस तरह कहना गलत होगा कि उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और उसमें टीचर्ज़ की कमी है। टीचर्ज़ की कमी पूरी की जा रही है। हज़ारों स्कूल्ज़ के लिए टीचर्ज़ के पद सृजित किये गए। हज़ारों स्कूलों में उनको भर्ती किया गया।

इसी तरह से हमारे यहां 6 आई0टी0आईज़0 खोले गए। इसी तरह से हर विधान सभा क्षेत्र के अंदर बच्चों के लिए एक आई0टी0आई0 उपलब्ध है। रामपुर में अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। उसकी बिल्डिंग का काम चल रहा है। हमें यह बताते हुए

खुशी हो रही है कि बच्चों की एडमिशन्ज़ हो चुकी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, सुन्दरनगर में सिविल और मकैनिकल इंजीनियरिंग की क्लासिज़ चल रही हैं। काम जोरों पर है उसकी बिल्डिंग जल्दी ही कम्प्लीट हो जायेगी तो उसमें क्लासिज़ रन करना शुरू कर देंगी। आई0आई0एम0 जैसी इंस्टीटियूशन का हिमाचल में होना अपने आप में एक बड़ी बात है। Free coaching facility for the weaker section यह भी एक सराहनीय काम है। जो कम्पीटिटिव एग्जाम में बच्चे जाते हैं उनको सरकार ने फ्री कोचिंग फैसिलिटी दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे।

02.03.2016/1245/SS-DC/2

हैल्थ भी हमारे लिये प्रायोरिटी की चीज़ है। गवर्नमैंट ने इसी साल 8 नये हॉस्पिटल, 16 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़, 4 हैल्थ सब-सैंटर्ज़ खोले। 266 नये डॉक्टर्ज़, 15 स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज़, 25 मेडिकल ऑफिसर्ज़ (डैंटल), 160 पोस्टस पैरा-मेडिकल स्टाफ की भरी गईं। 516 पोस्टस अभी पाइप लाइन में फिल-अप करने के लिए हैं। जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में अल्ट्रा मॉर्डन टैक्नीक का एक सिटी-स्कैन लगा है। जो मेडिकल कॉलेजिज़ तीन खुल रहे हैं इसके लिए to overcome the shortage of staff, फैकल्टी और मेडिकल कॉलेज में उसके लिए डिसाइड हुआ है कि अब उनके फैकल्टी मेम्बर्ज़ की जो ऐज़ है this would be increased from 62 years to 65 years ताकि यहां पर गैप न पड़े।

इसी तरह से आयुर्वेदा में गवर्नमैंट ने 39 पोस्टें आयुर्वेदा ऑफिसर्ज़ की भरी हैं। 39 पोस्टस पैरा-मेडिकल स्टाफ की भरी हैं। स्टाफ रिकूप हुआ है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो हैल्थ की बात चल रही है हमारे यहां in the previous regime, भारतीय जनता पार्टी के राज में रामपुर हॉस्पिटल में 31 डॉक्टर्ज़ की सैंक्शंड स्ट्रैंथ थी। 31 डॉक्टर्ज़ में से वहां कभी भी 10-11 से ऊपर डॉक्टर्ज़ नहीं गए। राउंड दी क्लॉक उनको काम करना था। जो गाइनाकोलोजिस्ट है। In good three years वहां कोई गाइनाकोलोजिस्ट नहीं थी। हमने बहुत रिक्वैस्ट की तो उसके बाद एक गाइनाकोलोजिस्ट शिमला से डिप्यूट होती थी। पहले हफ्ते में एक बार, फिर हफ्ते में दो बार, शिमला से गाइनाकोलोजिस्ट जायेगी तो हमारे यहां लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम

होती थी उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम बड़ी खुशी से बता सकते हैं कि we have hundred percent doctors available in the hospital और जितने भी हमारे प्राईमरी हैल्थ सब-सैंटर्ज़ हैं उसके अंदर डॉक्टर्ज़ उपलब्ध हैं। जहां पर मान लो एलोपैथी डॉक्टर नहीं मिल रहा तो वहां पर आयुर्वेदा डॉक्टर (ए0एम0ओ0) उपलब्ध होता है।

जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1250/av/AG/1

श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय सचिव)--------जारी

बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां नई-नई पी.एच.सीज. खुल रही है और उनमें डॉक्टर न हो। अब मैं रोड की बात करना चाहूंगा। रोड की नैटवर्किंग के लिए हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी सोच है। आज प्रदेश में 34-35 हजार किलोमीटर की रोड नैटवर्किंग है। उस पर भी टारिंग, मैटलिंग और वाइडनिंग इत्यादि के हर काम चले हुए हैं। हमारे नाबार्ड से 92 रोड्ज की डी.पी.आर. सैंक्शन होकर आ गई है तथा 15 ब्रिजिज प्रोजैक्ट्स सैंक्शन होकर आ गये हैं। हमारी कुछेक पंचायतें रोड से कनैक्ट होने को शेष रहती है बाकी तकरीबन सभी हो चुकी है। मैं यहां पर अपनी कुछेक सड़कों का जिक्र जरूर करूंगा, जो मेन-मेन सड़कें थी। हमारे यहां बड़ी मुश्किल रोड थी। रामपुर में जो काशापाट रोड, कूटक्याओ रोड, टिक्कर-खमाडी रोड, कूड़ीधार-कांगला रोड, लालसा-चिकसा रोड है; ये सारे रोड्ज सैंक्शन थे मगर पिछले पांच साल में कुछ नहीं हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इन पांचों सड़कों पर एक युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। जो काशापाट रोड है it would be the last panchayat we will have not connected with road, बाकी तो हमारी सारी पंचायतें रोड से कनैक्ट हो जायेगी।

नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के अंदर 36.82 लाख लोगों को कवर किया जा

रहा है जिसमें उनको राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। यह स्कीम वर्ष 2007 में चली थी। यह जो स्टेट स्पेशल सब्सिडी स्कीम है जिसमें दो-तीन दालों का प्रोविजन है, ऐडिबल ऑयल है, आयोडिन सॉल्ट का प्रोविजन है; इस स्टेट सिब्सडी में सबको राशन मिल रहा है।

अगर टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म में इस साल 163.14 लाख की बजाय 177.80 लाख टूरिस्ट हमारे यहां पर पहुंचे हैं यानि उसमें लगभग 9 प्रतिशत की इनक्रीज हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी जो पॉलिसी के मुताबिक न्यू होटल युनिट्स सैटअप किए गए। बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया और

2.3.2016/1250/av/dc/2

दूरदराज गांव में लग्जरी टैक्स दस साल के लिए ऐग्जैम्पटिड है। उसमें काफी लोग जा रहे हैं और लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारी रोप-वे की स्कीमें हैं। कांगड़ा में है, हमारे यहां भी हैं। मैं यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बशलकांडा की जो रोप-वे स्कीम है उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है। उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि हमारा रोप-वे का काम ठीक से चले। केंद्र सरकार के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों को बहुत बड़े-बड़े और लुभावने सपने दिए थे कि हम काला धन वापिस लायेंगे। आपके खाते में 15-15 लाख रुपये जायेंगे। बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि यू0पी0ए0 सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों को छोड़कर बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। उसको कहते हैं कि यह तो करना पड़ रहा है। यू0पी0ए0 सरकार के समय कुछेक स्कीमें जैसे सर्व शिक्षा अभियान स्कीम थी, You know, crores of rupees are being pumped into the State. इसके अलावा मिड डे मील स्कीम जो न केवल हिन्दुस्तान बल्कि उसकी तारीफ बाहर के लोगों ने भी की है। यहां पर जो मनरेगा पर डिबेट चल रही थी उसके बारे में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि there is a cut. We

are not getting funds. मैं मनरेगा के बारे में यह भी कहना चाहूंगा कि MGNREGA is not simply a scheme. It is an Act. यह ग्रांटिड सौ दिन का जो रोजगार मिलना है उसके लिए यह कानून है। मेरा इसके लिए केंद्र सरकार से भी आग्रह रहेगा कि मनरेगा जैसी स्कीम के अंतर्गत जो हिमाचल का शेयर ड्यू है वह टाइमली दिया जाए ताकि हम यहां पर मनरेगा स्कीम का ठीक से संचालन कर सके।

टीसी द्वारा जारी

02.03.2016/1255/TCV/AG/1
श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय कार्य मंत्री)--- जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हॉर्टीकल्च्चर में देखेंगे तो जो पॉली हाऊसिज़ की सबसिडी है वह 85 परसेंट दी है। हमारे जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, इनके समय में एक एंटी हेलगन का काम भी चालू हुआ था। जोकि पूरी तरह से विफल रहा और उसमें हमारा उल्टा नुकसान हुआ। आज हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी सब्सिडाईज्ड रेटस़ पर एंटी हेलनेट्स उपलब्ध करवाये है, जिससे हमारी क्राप्स का बचाव होता है और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा----- जारी

02.03.2016/1400/RKS/AS/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्षः इससे पहले की मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा को आरम्भ करवाऊं। आप सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि चाहे वह प्रश्नकाल हो, चाहे चर्चा हो, उसमें आप समय का ध्यान रखें। मुझे बहुत दुःख हुआ कि आज एक घण्टे में सिर्फ एक ही प्रश्न हुआ। चाहे दो ही प्रश्न हुए हो। परंतु बाकि लोग मुझसे शिकायत करते हैं ।I will not like कि आप प्रश्नकाल में कोई पॉलिटिकल एसपीरेशन करें। आप सवाल पूछिए, सवाल का जवाब पूछिए। पॉलिटीकली बात करने के लिए आपके पास बहुत समय होता है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1405/SLS-AS-1

अध्यक्ष महोदय ... जारी

मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)... एक मिनट आप बैठ जाइए। प्रश्न काल को राजनीतिक न होने दें। बहुत सारे सदस्य दुखी हैं कि उनके प्रश्न नहीं लगते। दूसरी बात यह है कि This one hour is to complete the question सदन में चर्चा आपने करनी है, मैं केवल इसका संचालन कर रहा हूं। आपने एक ही प्रश्न करना है तो वैसा करिए, but it is not fair और समय पर कोई नहीं बैठता। इसलिए मैं समय से बाहर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष में हैं। हमारे पास इस माननीय सदन में अपनी बात कहने के लिए प्रश्न काल से बढ़कर न तो कोई दूसरी व्यवस्था है और न ही कोई और महत्वपूर्ण नियम है। हमारे प्रश्न का जब उत्तर नहीं आता; मंत्री जब लंबी पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, ...(व्यवधान)... अगर आप मंत्रियों को नहीं रोकेंगे कि वह स्पैस्फिक होकर जवाब दें तो कैसे होगा?

अध्यक्ष : प्रश्न काल में आप जो प्रश्न पूछेंगे, आपको उनका उत्तर मिलेगा। अगर आप

उससे सहमत नहीं हैं तो आप किसी और नियम के अंतर्गत पूछिए, मैं आपको दोबारा समय दूंगा। But don't waste the time of the Question Hour. आपके ही दूसरे सदस्य हैं जिन्होंने प्रश्न किए होते हैं लेकिन उन्हें उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं; उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अभी 15 सदस्य बोलने के लिए हैं। हमारे पास 3 घंटे का समय है। इसमें सभी के हिस्से 10-12 मिनट आएंगे। मेरा सिनसियरली आपसे निवेदन है कि इस सदन का संचालन मैं कर रहा हूं, आपने केवल कौपरेट करना है। अगर 10 मिनट के बाद कोई बोलना जारी रखेगा तो मैं रोक दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। ...(व्यवधान)... मैं किसी को भी आधा घंटा बोलने नहीं दूंगा।...(व्यवधान)... फिर आप अपनी लिस्ट कम कीजिए। अगर कोई सदस्य ज्यादा बोलेगा तो उस पार्टी के दूसरे व्यक्ति को मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं समय निर्धारित कर

02.03.2016/1405/SLS-AS-2

दूंगा। 3 घंटों में से डेढ़ घंटा इस तरफ से और डेढ़ घंटा उस तरफ से बोलें।...(व्यवधान)...आप कितने सदस्यों से बुलवाना चाहते हैं? मेरी ओर से डेढ़ घंटे में चाहे आपका एक ही सदस्य बोले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। But if you all have to speak than you have to keep the time also. समय का तो ख़याल रखना ही पड़ेगा।...(व्यवधान)...

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, विधायकों के पास बोलने के लिए एक राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और दूसरा बजट का अवसर होता है। मुझे लगता है कि बजट सत्र में इन अवसरों पर बोलने देना चाहिए। जितना समय विपक्ष को मिलना चाहिए, हम आपसे निवदेन करते हैं कि वह मिलना चाहिए।

अध्यक्ष : राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा में आप सभी बोल रहे हैं, इसलिए हम सभी को समय बांट कर ही देंगे। लेकिन अगर एक ही सदस्य बोलेगा तो बाकी का समय कट

ऑफ हो जाएगा। ...(व्यवधान)...मैं आज के ही दिन की बात कर रहा हूं। अगर कल फिर इस पर बोलना चाहें तो बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप पक्ष और विपक्ष को तो बोलने का अवसर दे रहे हैं लेकिन हम लोग जो सामने बैठते हैं, आप कृपया हमारा भी ध्यान रखें और सामने भी नज़र डाली जाए।...(व्यवधान)...

Speaker :Let's not waste the time. मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन अभी 15 सदस्य बोलने के लिए हैं, इसलिए कोई भी सदस्य 10-12 मिनट से ज्यादा न बोले ताकि सबको बोलने का अवसर मिले। आप सभी बोलना चाहते हैं। आप अच्छी बातें बोलेंगे लेकिन दूसरे लोग भी वही कहना चाहेंगे। यह नहीं है कि मैं ही बोलूं और बाकी न बोलें।

अब इस अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं श्री रविन्द्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री रविन्द्र सिंह ..श्री गर्ग जी के पास

02/03/2016/1410-/RG/DC/1

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 25 फरवरी, 2016 को इस माननीय सदन में अपना अभिभाषण यहां पढ़ा जिस पर श्री जगजीवन पाल जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और श्री अजय महाजन जी ने उसका अनुसमर्थन किया। मैं उसीके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बातें यहां रखी गईं, निश्चित तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो जब राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण यहां माननीय सदन में पढ़ा, तो जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें इसको अप्रूव किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि या तो मंत्रि-परिषद के किसी भी

सदस्य ने इसको गौर से नहीं पढ़ा या इसको आंखें बंद करके जो अधिकारियों ने बनाकर दे दिया, उसको महामहिम राज्यपाल महोदय को ऐसे ही भेज दिया। मेरा इस सरकार पर सीधा आरोप है कि यदि आप देखें कि राज्यपाल महोदय ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया, उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय मंद-मंद मुस्कुराए भी थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया श्लोक के साथ अपना अभिभाषण शुरू किया। 'असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्यातिर्गमय'। उस समय यहां पर बैठकर मुख्य मंत्री महोदय मुस्करा रहे थे। इसके ऊपर हमारे प्रतिपक्ष के नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सारी बातें यहां रखीं। इसमें सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के पहले पैरे में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बारे में कहा गया है। सरकार के न तो किसी विधायक ने, न किसी मंत्री और न ही मुख्य मंत्री और न ही इस विभाग के मंत्री ने इस भाषण में पढ़ा कि प्रदेश में पंचायतें कितनी रह गई हैं। अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला नगर निगम बन गया, ज्वाली वहां नगर पंचायत बन गई, बैजनाथ नगर पंचायत बन गई और मण्डी जिले में भी नैरचौक को नगर पंचायत दर्जा देने की बात की, वहां उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की 3,243 पंचायतें थीं वे कम हो गई हैं। 12 जिला कांगड़ा की कम हुईं और 6 पंचायतें नेहरचौक की कम हुईं। इस प्रकार कुल मिलाकर 18 पंचायतें कम हुई हैं। यानि कि 3,225 पंचायतें रह गईं। इस सरकार को इस विभाग को, मंत्री जी यहां हैं नहीं, अधिकारियों को यही पता नहीं कि प्रदेश में कितनी पंचायतों में चुनाव करवाए। मेरा इस सरकार के ऊपर यह आरोप है। यही नहीं, यदि इसके आगे आप चलेंगे, मैं आगे चलने से पहले यह कहूंगा कि इन्होंने महामहिम से एक बात और कहलवा दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के सत्ता

02/03/2016/1410-/RG/DC/2

में आने के बाद 16,818 हैण्ड पम्पज स्थापित किए। यह पृष्ठ-16 और पैरा-50 है। जब यह अभिभाषण हुआ, यहां से एक साप्ताहिक पत्रिका छपती है 'प्रचण्ड हिमाचल', उसको सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर विज्ञापन दिया गया। उन्होंने जो यह विज्ञापन लगाया है यह फरवरी माह का है। उन्होंने कहा है कि जलाभाव वाले क्षेत्रों में 62 करोड़, 23 लाख रुपये व्यय करके 4,887 हैण्ड पम्प्ज

स्थापित किए। सही कौन से हैं? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहे गए सही हैं या इस पत्रिका में छापे गए सही हैं?

अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सरकार पर आरोप है कि अभी तक तीन सालों में, माननीय मंत्री महोदया यहां बैठी हैं, अभी तक पिछले तीन सालों में हैण्ड पम्प्ज लगाने के टैण्डर्ज यह सरकार नहीं कर पाई है। जलाभाव कहां है यही सरकार को पता नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय से इन्होंने कितना झूठ कहलवाया, मेरा तो यही सरकार पर आरोप है। यही नहीं, आज प्रश्न था बंदरों की नसबंदी के बारे में और बंदरों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न यहां लगा था। इस अभिभाषण के पृष्ठ-14 पर यह कहा गया कि वानरों की नसबंदी केन्द्रों में 1,2,870 बंदरों की कर दी। जबकि माननीय मंत्री महोदय ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह संख्या 53,404 है। यह सरकार को क्या हो रहा है?

एम.एस. द्वारा जारी

02/03/2016/1415/MS/dc/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी-----

इस सरकार को पता ही नहीं है कि धरातल पर क्या है। आपने अपने घोषणा पत्र में क्या वायदा किया है? मैं इस घोषणा पत्र पर ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इसमें लिखा है कि "सर्वागीण विकास होगा, स्वच्छ शासन-कुशल प्रशासन देंगे, जवाबदेह एवं पारदर्शी सरकार और पांच वर्षों में विकसित हिमाचल"। ऐसे-ऐसे अगर आप काम करेंगे तो आपके वायदे कहां जाएंगे? अध्यक्ष जी, मेरा इस सरकार पर आरोप है। जैसे यहां कोई कह रहा है कि हमारे 80 प्रतिशत, 76 प्रतिशत या 70 प्रतिशत लोग पंचायत चुनाव में जीते हैं। जो इस प्रस्ताव के मूवर श्री जगजीवन पाल जी थे, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये अपने विधान सभा क्षेत्र में नज़र दौड़ाएं। इनके विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन ब्लॉक आते हैं और तीनों ब्लॉक्स में इनका एक भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जिला परिषद का नहीं बन पाया। भेडू महादेव सुलह ब्लॉक है वहां पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बी0जे0पी0 के हैं। भवारना ब्लॉक में चेयरमैन तो आपकी पार्टी का बना लेकिन वाइस चेयरमैन सुलह चुनाव क्षेत्र से बी0जे0पी0 का बना है। लम्बागांव ब्लॉक की जो अध्यक्षा बनी, वह पुराना थुरल और वर्तमान सुलह विधान सभा क्षेत्र से

श्रीमती वीना देवी बनी हैं जोकि भाजपा समर्थित है। और तो और अध्यक्ष जी पंचायती राज चुनाव में ये कहते हैं कि हमने बहुत छलांग मार दी। मेरा इस सरकार पर आरोप है और उन अधिकारियों पर भी आरोप है। चम्बा में क्या हुआ, यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं? चम्बा में एक जिलाधीश के माध्यम से बहुमत भाजपा का और वहां पर चिट्टों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाता है और चिट भी अध्यक्ष जी कैसी डाली गई। वहां पर बराबर वोट हो गए तो दो पर्चियां डाली गईं और एक पर्ची लम्बी कर दी। पर्चियां डालने वाली भी जिलाधीश महोदया खुद और निकालने वाली भी स्वयं ही थी। जब हमारे यहां बैठे माननीय विधायक और वहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्त्ताओं ने विरोध किया तो वह चुनाव घोषणा करके वहां से भाग गईं। चिट्ट बनाई भी खुद और निकाली भी स्वयं ही, यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। यदि ऐसी स्थिति होती है तो टॉस होता है। फिर टॉस में जो होगा ठीक है। वहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव किया। वैसे भी कितने क्रप्शन

02/03/2016/1415/MS/dc/2

के चार्जिज लगे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी जिलाधीश चम्बा के पद से तीन बार बदली हुई लेकिन तीनों ही बार बदली रूकवाने की क्या साजिश थी? किसलिए उनको वहां पर रोक कर रखा गया? क्या इसीलिए कि जब जिला परिषद के चुनाव होंगे तो वहां पर वह एक तरफा काम करेंगी? अध्यक्ष जी, यही नहीं, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी जिला कांगड़ा के प्रवास पर थे। जिला कांगड़ा के साथ जो भेदभाव इनके अंदर छिपा हुआ है, वह तो लगातार चलता रहता है। इन पंचायती राज चुनावों में भी सारे प्रदेश में चुनाव का डंका बज गया लेकिन जिला कांगड़ा के चुनाव स्थगित कर दिए। जब सारे प्रदेश में चुनाव हो गए तब जिला कांगड़ा के चुनावों की घोषणा हुई। उसके बाद भी सारे चुनाव सम्पन्न होने के बाद जब जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव आया तो क्या घटना वहां पर घटी। मुख्य मंत्री जी प्रदेश के दौरे पर थे और 29 जनवरी को सुबह चुनाव था। ये 28 तारीख की सुबह सोलन से अपना सारा कार्यक्रम रद्द करके हैलीकॉप्टर से सीधे धर्मशाला पहुंच गए और धर्मशाला में सारा दिन 4.00 बजे तक जो हमारे सारे समर्थित चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको एक-एक करके बुलाया गया।

तीन लोगों को बुलाया गया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्य मंत्री जी के मुंह पर कहा कि मुझे कुछ लोग यहां लेकर आए हैं लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। आपने हमें उठाना है तो ले जाइए लेकिन हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जाएगा और अध्यक्ष जी हुआ क्या, जब 4.00 बजे तक पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है। अरे, कमाल हो गया मंत्री महोदय, चुनाव होने से पहले कुछ नोटिफिकेशन्ज की जाती हैं।

अध्यक्षः यह चुनाव पार्टी लैवल पर नहीं था।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, पार्टी लैवल पर आप भी स्पीकर नहीं हैं। आप न्यूट्रल हैं। (अपनी सीट पर बैठे-बैठे कहा)

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, पंचायत राज चुनावों पर यहां बहुत चर्चा हुई है। मैं इस बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी को 4.00 बजे दिल्ली जाना था और 4.00 बजे तक जब उनको पता चला कि यहां कोई कांग्रेस समर्थित

02/03/2016/1415/MS/dc/3

जिला परिषद का अध्यक्ष बनने वाला नहीं है तो ये ऐसे निर्देश देकर आए कि बाई हुक और क्रुक जिला कांगड़ा के जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए जो कुछ करना पड़े, कीजिए और उसके लिए कानून भी बदलना पड़े तो बदलिए। यह बड़ी शर्म की बात है कि 29 तारीख को सुबह चुनाव होते हैं

जारी एस0एस0 द्वारा------

02.03.2016/1420/SS-AG/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

और 29 तारीख को सुबह यहां से नोटिफिकेशन जिला कांगड़ा के डी0सी0 को जाती है। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको पढ़ सकता हूं। उसमें कहा

जाता है, यह एक महिला के लिए आरक्षित पद था। इससे पहले यह कभी नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ। मैं नोटिफिकेशन की अंतिम लाइनें पढ़ूंगा। वैसे आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और ओ0बी0सी0 के बड़े हितैषी बनते हैं। जब आपकी नोटिफिकेशन हुई है तो उसमें क्या लाइन आईं? यहां पर किशोरी लाल जी बैठे हैं। नोटिफिकेशन में लिखा है ". . . which is a conclusive proof of reservation of offices in the Districts, it can be safely concluded that any office reserved for a General Category women cannot be filled up from other categories of women belonging to SC, ST and OBC . . ." ये आप कहना चाहते हैं कि आप इनके बड़े हितैषी हैं। ये आपकी सुबह 29 जनवरी की चिट्ठी है। अध्यक्ष महोदय, कानून बदल दिया। इससे पहले यह कभी नहीं हुआ। हम मानते हैं कि आपने उसको जनरल श्रेणी में करना भी होगा तो चुनावों से पहले ऐसी घोषणाएं नहीं होती हैं। Nick of time, जिस दिन चुनाव हों उस दिन घोषणाएं नहीं होती हैं। मेरा इस सरकार पर आरोप है और विशेषकर मुख्य मंत्री पर आरोप है कि मुख्य मंत्री महोदय 28 जनवरी को सारा दिन वहां पर बैठे रहे। शायद आपको एक शक था। जो हमारी मीटिंग हुई तो जिला कांगड़ा के कांग्रेस के सारे नेतृत्व को शक था कि बी0जे0पी0 की सामान्य श्रेणी की कोई महिला जीत कर नहीं आई है। यह तो हमारा और उसका भाग्य है कि हमारी जीती हुई महिलाओं में से एक मधु गुप्ता निकली। देखिये, हमारे पास बहुमत था और यहां के मंत्री ठीक कहते हैं कि आपके पास बहुमत था ही नहीं। जब एक बार आए तो 16 आए और एक बार आये तो 6 आए। बाकी हमारे पास बहुमत था। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मुख्य मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं तो काली भेड़ों को पकड़ कर छोड़ूंगा। अरे भाई, काली भेड़े वे आज की नहीं हैं। अनिल जी, जब आपने राज्यसभा जाना था तो उस समय भी काली भेड़ें आई थीं। वे भी आज तक नहीं पकड़ी गईं। 1998 में जब आपने राज्यसभा में जाना था तो उस समय भी वे काली भेड़ें नहीं पकड़ी गईं। उसके बाद कृपाल परमार जी का चुनाव था। वे भेड़ें फिर नहीं पकड़ी गईं। उसके बाद जब सुरेश भारद्वाज जी ने जाना था तो उस समय भी दो भेड़ें आईं, वे भी नहीं पकड़ी गईं। आप कितनी भेड़ों को पकड़ेंगे? जब सारी की सारी भेड़ें हैं तो उसमें, अध्यक्ष महोदय, क्या हो सकता है? पंचायती राज चुनाव में ये बार-

02.03.2016/1420/SS-AG/2

बार दोहराना कि हमारा बहुमत है, यह हमें मालूम है। जनता जानती है कि वह किसके पक्ष में है। अध्यक्ष महोदय, यही ही नहीं, इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे अधिकारियों को जिनकी वहां पर डयूटियां लगीं, उनको बुला-बुला कर डयूटियां लगाई हैं। ये हमारा आरोप है। फिर भी हम जीत कर आए हैं। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय तो यहां के पीलिया रोग को छोड़ कर, यहां के अधिकारियों को छोड़ कर, पत्रकारों को छोड़कर, स्थानीय जनता को छोड़ कर कांगड़ा की ओर चल पड़े। शिमला में पीलिया फैला और मुख्य मंत्री कांगड़ा की ओर चल पड़े। या तो मुख्य मंत्री महोदय शिमला में बैठकर पीलिया की समस्या का निपटारा करते तो हम उनको मानते लेकिन वे जनता की समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद एक मंत्री से, दूसरे मंत्री से, तीसरे मंत्री से या चौथे मंत्री से कोई इनकी बदला लेने की कोशिश थी कि पीलिया खूब फैले। पानी वाले मंत्री, अर्बन डिपार्टमैंट मंत्री भी और साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी पता नहीं आप कहां थे। मुख्य मंत्री तो इन तीन सालों में दो-तीन काम करते रहे। मुख्य मंत्री महोदय ने जो दो-तीन काम किये वे ये हैं। तीन साल तो इनको अपनी सरकार को बचाने में लग गये। दिल्ली-शिमला, दिल्ली-शिमला, दिल्ली-शिमला, यही चलता रहा। वहां पर जा-जाकर दिल्ली के गुलदस्ते भी महंगे कर दिये। पहली बार गुलदस्तों का रेट 450 रुपये था। दूसरी बार 650 का हो गया। तीसरी बार 850 का हो गया। अब जायेंगे तो वह 600 रुपये का मिलेगा। ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। उसके बाद मुख्य मंत्री महोदय आपकी कैबिनेट की मीटिंग में मंत्री आपस में बहस करते हैं। खूब लड़ते-झगड़ते हैं। आप उनको मनाने में लगे रहते हैं। अरे भाई, आप काहे को लड़ते हो? इसको मैं करूंगा, इसको तुम करो, इसको ऐसे करेंगे, मुख्य मंत्री का सारा समय तो अपनी सीट को बचाने में लगता है। मंत्रियों के झगड़ों को दूर करने में ये तीन साल गुजर गये। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सरकार पर आरोप है। इसके साथ ही मैं इससे आगे चलूं तो यहां पर बड़े-बड़े वायदे करते हैं कि हमने इंवैस्टर्ज़ मीट की हैं। आपके घोषणा पत्र के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि हम पैकेज लेकर आयेंगे। पैकेज को इम्प्लीमैंट करेंगे

जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1425/av/ag/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागत

और जिला के मुख्यालयों में जाकर उद्योग स्थापित करेंगे। इस विधान सभा का सत्र लगने से पूर्व जब कलराज मिश्र जी आए थे तो यहां पर लगभग 102 करोड़ रुपये की राशि से बनने वाले टूल रूम का शिलान्यास किया था। मुख्य मंत्री महोदय जी ने वहां पर भाषण दिया (---घंटी---) अध्यक्ष महोदय, अभी दस मिनट हुए हैं।

अध्यक्ष : दस मिनट नहीं, आधा घंटा हो गया है।

श्री रविन्द्र सिंह : सर, दस मिनट हुए हैं। आप कहेंगे तो बोलूंगा नहीं, बैठ जाऊंगा। मगर यह ठीक नहीं है। मेरे से पहले वक्ता ने 28 मिनट लिए हैं।

मुख्य मंत्री जी ने वहां पर बोला कि मेरा सपना था। मैं जब केंद्र में मंत्री था तो उस समय किया था। वहां केंद्र के मंत्री की सीट पर बैठकर आपने क्या-क्या सपने लिए, आप वहां पर किन-किन कार्यों को निपटाते रहे; वह सब तो प्रदेश की जनता जानती है उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह टूल रूम तो श्री मोदी जी और कलराज मिश्र की देन है जो यहां पर 102 करोड़ रुपये में बनना है। पेज संख्या 17 और 18 पर पैरा न0 56, 57 और 58 पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं इनमें नहीं जाना चाहता। मगर दुख का विषय यह है कि इस कार्यकाल में आपके बद्दी, परवाणू के इलाके में 63 उद्योग बंद हो गये। परवाणू में एक सेमटैल युनिट बंद हो गई, साई इनफोसिस सिस्टम परवाणू बंद हो गया, त्रिवेणी कास्टिंग बंद हो गया, बी.के. इण्डस्ट्रीज, बद्दी बंद हो गया। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुल मिलाकर सैंकड़ों उद्योग यहां से पलायन करके चले गये हैं।

इसके पीछे कारण
क्या है? (---व्यवधान---) अच्छे दिन नहीं है। इसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि नालागढ़ इलाके में जुलाई, अगस्त और सितम्बर में 108 बार पावर ट्रिपिंग हुई है। मैं यह केवलमात्र नालागढ़ की बात कर रहा हूं। वहां पर 244 बार पावर बंद रही

2.3.2016/1425/av/ag/2

है। बाकी जैसे कहा गया था कि यहां पर इण्डस्ट्री लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया जायेगा; वह नीति आपकी कहां है। यहां उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वहां पर इनवैस्टर मीट भी काम नहीं आई? वहां इनवैस्टर मीट में हिमाचल के बड़े-बड़े लोगों ने कहा था कि हम आने के लिए तैयार है। इनवैस्टर मीट में लगभग 1400 उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में स्थित हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के चिकित्सक दम्पत्ति ने प्रदेश में अस्पताल और मैडिकल कॉलेज खोलने की बात की थी। उन्होंने खुद कहा था कि जगह दो हम खोलेंगे। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेक इन इंडिया के तहत डिफैंस के लिए जो कलपूर्जे बनने है उसके लिए यहां पर एल.जी. चैक इंडिया रिपब्लिग के नाम से कम्पनी आई। मगर उनको यहां पर काम नहीं दिया गया और पूछा नहीं गया। आप उद्योग के क्षेत्र में बिल्कुल फेल हुए हैं।

आज वर्तमान सरकार का पूरा ध्यान खनन की ओर है। लकड़ी के ऊपर जो काम हो रहा है उसके बारे में तो माननीय धूमल जी ने कहा भी है। मगर ऐसे ही काम पूरे प्रदेश में खनन में हो रहे हैं। चाहे हमारा नूरपुर का एरिया है, ऊना, पांवटा साहिब या नालागढ़ का क्षेत्र है। आप वहां जाओ, वहां अवैध खनन माफिया लगा हुआ है मगर वहां पर पूछने वाला कोई नहीं है। उसके लिए छोटे-छोटे ट्रैक्टर वालों को पूछा जा रहा है। उनके चलान हो रहे हैं जो छोटी-मोटी कमाई करके अपने घर की रोजी-रोटी चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है। हमने आरोप

लगाया था कि वनों का कत्लेआम हो रहा है। यह बात हमने कई बार कही। इस पर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट आने पर जीरो टोलरैंस पर कार्रवाई करूंगा। उन बेचारे कर्मचारियों को तो आपने ससपैंड कर दिया। जो बड़े घाक बैठे हुए हैं, जिन पर सरकार का पूरा आशीर्वाद है, उनको आपने फिर से परमिट दे दिए। मैंने यहां पर एक प्रश्न भी

2.3.2016/1425/av/ag/3

लगाया थ। दिनांक 21.8.2015 को प्रश्न संख्या 2195 लगा था। बैजनाथ में किशोरी लाल जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक तिलक नाम के ए0एस0आई0 जो कि डरोह में भर्ती है। वह वहां पर 4-5 लाख रुपये कीमत की नागछत्री लेकर गया और पकड़ा गया। उसका लाइसैंस रद्द कर दिया गया मगर मेरी जानकारी के अनुसार उसको फिर से लाइसैंस दे दिया गया है। यह समझौता क्यों हो रहा है? यही बात यहां पर रखी गई है कि बंदरों की ढुलाई के काम में करोड़ों का घोटाला हुआ है। यहां पर भू-माफिया हावी है, ड्रग माफिया हावी है, खनन माफिया हावी है।

टीसी द्वारा जारी

02.03.2016/1430/TCV/AS/1

श्री रविन्द्र सिंह --- जारी

और ये पूरी सरकार खन्न माफिया के शकंजे़ में फंसी हुई है। ये वन विभाग की टीम पर हमला वन-काटूओं ने किया, गाड़ी तोड़ी। ये सारे का सारा हरोली क्षेत्र में हुआ। उन तस्करों को पकड़ने के लिए रेंजर, डिप्टी रेंजर और सरकारी गाड़ी को बुरी तरह नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त भी, कई कुछ इसमें है। इनके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। ये हमारा इस सरकार के ऊपर आरोप है कि जो भाषण आपने राज्यपाल महोदय से कहलवाया वह बिल्कुल असत्य पर आधारित है। आपने जो चम्बा में एलमी का जंगल काटा और उसकी जांच के लिए जो टीम बनाई थी, उसमें श्री वीर बहादुर,

डी0एस0पी0, हैडक्वार्टरज चम्बा, चेयरमैन बनाया गया। मनीश राम, ए0सी0एफ, फॉरेस्ट डिवीजन, नूरपुर और कमल भारती डिविजनल मैनेजर, फॉरेस्ट डिविजन, फतेहपुर, कांगड़ा को मैंबर बनाया गया। बाद में उन्होंने जो रिपोर्ट सरकार को दी, सरकार ने वह रिपोर्ट ही बदल दी। सरकार को इन रिपोर्टों को बदलने की पता नहीं क्या आवश्यकता पड़ी। ऐसे लोगों को क्यों आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये हमारा इस सरकार के ऊपर आरोप है और अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें इस माननीय सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री तक पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी कहना चाहूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप और कितनी देर बोलेंगे?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, 8-10 मिनट में खत्म कर दूंगा।

अध्यक्षः देखिए 21 मिनट हो गए हैं और यदि आप और 8-10 मिनट बोलेंगे तो आधा घण्टा लग जाएगा। इस तरह से बाकी माननीय सदस्यों के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री रविन्द्र सिंहः नहीं उससे पहले-पहले खत्म कर दूंगा।

Speaker: Be brief within 5 minutes.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। शिक्षण संस्थान खोलना, उसको स्तरोन्नत करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय सारे प्रदेश में हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। जो नॉन टीचिंग स्टॉफ होता है उसके भी हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं । कॉलेज़िज़ आपने खोल दिए। आज हर 12 किलोमीटर के बाद कॉलेज है। कोई बात नहीं कॉलेज़िज होने चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों में वह प्रतिस्पर्द्धा, गुणात्मक शिक्षा,कम्पीटीशन की भावना, जो राष्ट्रीय तथा

02.03.2016/1430/TCV/AS/2

अन्तर्राष्टीय स्तर पर होनी चाहिए, क्या आप उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यह

समय इस बारे में चिन्ता करने का है। कॉलेज़िज खोलना कोई बड़ें मायने नहीं रखते हैं। प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है। इस ओर चिन्ता करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिए में इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं माननीय धूमल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बतौर मुख्य मंत्री इन्होंने बड़े-बड़े प्रोजैक्ट केन्द्र से प्रदेश हित में लाये। केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी। यह प्रदेश की सरकारों का अधिकार होता है कि वे केन्द्र में लड़ाई लड़ कर वहां से प्रदेश हित के लिए प्रोजैक्ट इत्यादि लायें। आखिर धुमल जी ने लड़ाईयां वहां पर लड़ी और बड़े-बड़े प्रोजैक्ट प्रदेश के लिए लाये। मण्डी जिला के नेरचौक में एक रूपये की 99 वर्ष के लिए लीज़ पर जगह देकर ई0एस0आई0सी0 का हॉस्पिटल लिया है। केन्द्र सरकार मानी और आई0आई0टी0 कमांद, मण्डी में दे दिया। अटल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर में दे दिया। हाईड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बिलासपुर को दे दिया। जहां-जहां भी आवश्यकता थी वह वहां-वहां पर दिए हैं। इसी तरह से कांगड़ा के लिए दो इन्स्टीच्यूट आये जिसके के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। बी0एस0एफ0 की बटालियन दी जो इस सरकार ने बन्द कर दी। सारी ज़मीन ट्रांसफर हो गई थी केवल पैसे जमा करवाने थे। डिजास्टर मैंनेजमेंट का आपने पहले ही सत्र में जवाब दिया है। वह नूरपुर के कोपड़ा गांव के लिए आया। आपने कहा केन्द्र से इसके लिए पैसा लेकर आएंगे। लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं। तीसरा हमारा प्रोजैक्ट है फैशन टैक्नोलॉजी का। हिन्दुस्तान में 13वां इन्स्टीच्यूट खोला और कांगड़ा को दिया । जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता और बंगलौर के बच्चे कांगड़ा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सेंट्रल युनिवर्सीटी आई। हमारी प्राथमिकता थी कि यह पालमपुर में खुले । मैंने धूमल जी को कहा था। इन्होंने सर्वे के लिए सारे जिला को भेज दिया। सर्वे करवाया गया और सर्वे की रिपोर्ट मेंरे पास यहां पर है। सर्वे के उपरान्त भारत सरकार नोटिफिकेशन करती है। आप उसको कैसे चैंज कर सकते है? 23 अप्रैल, 2010 को सैंट्रल युनिवर्सीटी की नोटिफिकेशन होती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैंट्रल युनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश ये उन्होंने कहा है: while main campus of University will be located at Dehra the other campus at Dahramsala, will as such. Such of the schools departments which do not require massive infrastructure as recommended by the

Committee.

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ----

02.03.2016/1435/RKS/AS/1

श्री रविन्द्र सिंह ...क्रमागत

यह रिपोर्ट उस कमेटी ने दी है। आर.डी. सहाय. जो उस समय एच.आर.डी. मंत्रालय में डायरैक्टर थे यह उनकी चिट्ठी है। उन्होंने यह नोटिफिकेशन की है। मुख्य मंत्री महोदय बिल्कुल मुखर जाते हैं। लैंड देहरा में ट्रांसफर कर दी। लगभग 3 हजार कनाल भूमि सेंटरल यूनिवर्सिटी के नाम चढ़ चुकी है। मुख्य मंत्री महोदय एक तरफ कहते हैं कि धर्मपुर में बड़ी बाढ़ आई, सारा बस अड्डा बह गया, बहुत नुकसान हो गया। वहां मुख्य मंत्री जी जाते हैं और घोषणा करते हैं कि कोई भी ऐसा संस्थान खड्डों के बीच नहीं बनेगा। लेकिन युनिवर्सिटी को आप खड्डु के बीच में बनाने के लिए तुले हुए हैं। मेरे पास सारी रिपोर्ट है। अभी मैं पढ़ूगा नहीं।(घंटी बजी) हमने तो लैंड नेशनल हाईवे के ऊपर पौंग डैम से पहले धोलाधार की की रेंजिज के बीच में स्लैक्ट की है जिसके के लिए भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है Diversions of Forest Land यह मुख्य मंत्री का अपना व्यक्तिगत पत्र है, जयंती नटराजन समिति, मंत्री महोदय को। उन्होंने लिखा है Diversion of Forest Land for establishment of Central university in Himachal Pradesh में ज्यादा न पढ़ता हुआ जो इसका मूल है मैं उसके ऊपर The State Government has identified land for university which has also been inspected and financed by the Central Site Selection Committee. The Case for forest environment clearances stands sent to your Ministry after due process at the State level. The matter is pending with Ministry of Environment and Forest since November 2011 ये वहां पर पड़ा हुआ है। जिसकी क्लीयरेंस लगभग 87, 81 हैक्टेयर्ज की अभी आई है। दिनांक 1.05.2012 को जो चिट्ठी आई है। जिसमें धर्मशाला के बारे मे भी लिखा है। धर्मशाला के लिए 61 है। और देहरा के

लिए 317हैक्टेयर है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहा है enclosed for your perusal may I clarified that in a hill state like Himachal Pradesh no other government land is available accept forest land. In view of above I hope and trust that an early decision in the case is taken so that the land is transferred to the University without any further delay. I hope that with

02.03.2016/1435/RKS/AS/2

your support and cooperation we shall be able to lay the foundation stone of the two campuses of the University with the next fifty days. आपका यह पत्र 24 जनवरी, 2013 को गया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें देरी करने के बजाय 3,000 कनाल भूमि सरकार के सैंटर यूनिवर्सिटी के नाम चढ़ चुकी हैं जिसकी कॉपी अगर आप चाहेंगे तो मैं यहां ले कर दूंगा। इसके बाद में इस प्रति को ले कर दूंगा। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संस्थान में देरी न करते हुए इसे प्राथमिकता के ऊपर जिसके लिए भारत सरकार भी तैयार है ,केंद्रीय मंत्री भी यहां आई हुई थी। उन्होंने भी चाहा है कि यह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। यह जरूरी नहीं कि ये संस्थान हेड क्वार्टर में ही होना चाहिए। आई.आई.टी. संस्थान जब मण्डी कमांद में बन सकता है, आई.आई.एम. कोलर में बन सकता है। बिलासपुर के कोठी में एम्स बन सकता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में क्यों नहीं बन सकती है। नेशनल हाईवे के ऊपर क्यों नहीं बन सकती है। यह अड़चन किसलिए, क्यो? केवल मात्र देहरा जहां से विधायक मै और मेरे साथी बिक्रम सिंह जी हैं जहां हमेशा बी.जे.पी. का गढ़ रहा है इसलिए। संजय रत्तन और विप्लव ठाकुर जी भी इस मामले में हमारे साथ है। अंत में मैं एक चीज माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं । एक फर्जी डीग्री मामले की जांच फिर शुरू। पिछला शरद कालीन सत्र धर्मशाला में शुरू हुआ था। वहां एक प्राईवेट संस्थान चलता है। फैशन टैक्नोलॉजी का। वहां विद्यार्थी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी मिले थे। जांच के आदेश भी दिए थे। लेकिन जांच हुई नहीं लेकिन जो वहां का प्रबंधक, सी.एम.डी. है वह पैसे लेकर भूमिगत हो गया है। वह मामला आज फिर ऊठा है। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उस मामले की जांच की जाए।

18-20 लड़कियां उनके पैसे का जो वहां पर दरुपयोग हुआ है, वह पैसा उनको वापिस करवाया जाए।

अध्यक्षः आप कितना समय और लेंगे?

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा।

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1440/SLS- DC -1

अध्यक्षः आपके 2 मिनट भी 10-15 मिनट हो जाते हैं। ...(व्यवधान)... ठीक है, आप समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी दौरा करते हैं तो वहां टारिंग हो जाती है लेकिन मुख्य मंत्री का दौरा समाप्त होने पर वह टारिंग भी उखड़ जाती है। पूरे प्रदेश की सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। उस ओर आज के दिन में निश्चित तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आई.पी.एच. विभाग की बात है। माननीय मंत्री महोदया यहां बैठी है, आप ध्यान देंगी।

मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए, अभी कुछ और बोलने को था, लेकिन आपके पद की गरिमा को सामने रखते हुए जो आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री मनसा राम जी चर्चा में भाग लेंगे। ...(व्यवधान)... किशोरी लाल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रविन्द्र सिंह जी ने मेरा नाम लिया। हमने बैजनाथ ब्लॉक में एक एस.सी. महिला को अध्यक्ष बनाया है और उपाध्यक्ष भी सामान्य वर्ग की महिला को बनाया गया है। नगर पंचायत बैजनाथ में कांग्रेस पार्टी के सभी उपाध्यक्ष जीते हैं, उनके नाम आपने नहीं लिए।

02.03.2016/1440/SLS-DC-2

श्री मनसा राम (मुख्य संसदीय सचिव)ः अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। मैं श्री जगजीवन पाल जी द्वारा प्रस्तुत और श्री अजय महाजन द्वारा अनुसमर्थित जो प्रस्ताव माननीय राज्यपाल जी ने यहां रखा है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजनीति में जब हम उस पक्ष में होते हैं तो इस पक्ष की गलतियां निकालते हैं; कमियां होती भी हैं, लेकिन जब इधर होते हैं तो उस पक्ष की गलतियां निकालते हैं। हमें गौरव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3,39,921 व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में पैंशन लगाई। उनमें एक लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जो 80 साल से ऊपर हैं और अपंग हैं। वह सब इनके उज्ज्वल भविष्य की और दीर्घायु की कामना करते हैं। लोग चिढ़ते है। हम बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कितने काम हुए हैं। हर पार्टी और हर व्यक्ति अपनी तारीफ़ करता है। लेकिन हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश में शुरू में 17 वर्षों तक डॉ० यशवन्त सिंह परमार जी ने मुख्य मंत्री के रूप में काम किया और पूर्ण राज्य बना कर प्रदेश का नाम ऊंचा किया। उनको लोग हिमाचल निर्माता के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता वीरभद्र सिंह जी है। हमें गौरव है कि आप श्रीमती इंदिरा गान्धी की कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में रहे। उसके बाद राजीव जी के साथ मंत्रिमंडल में रहे और

तीसरी बार आपने डॉ० मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में रहकर हिमाचल के लिए काम किया। हमें गर्व है कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजघराने में पैदा हुआ है और जिसने सारा जीवन हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए और हिमाचल के निर्माण के लिए न्योछावर किया है, सारे प्रदेश में इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, इसलिए देवताओं तथा गरीबों के आशीर्वाद से हिमाचल निर्माता डॉ० यशवन्त सिंह परमार के बाद आप ही आधुनिक हिमाचल के निर्माता मुख्य मंत्री हैं।

जारी...श्री गर्ग जी

02/03/2016/1445/RG/DC/1

श्री मनसा राम (**मुख्य संसदीय सचिव**)-----**क्रमागत**
और यही कारण है कि बड़े-बड़े दुश्मन आए, लेकिन वे इनका कुछ नहीं कर पाते। वह इसलिए नहीं कर पाते कि इनको हिमाचल प्रदेश के गरीबों का जिनके लिए ये दिन-रात एक करते हैं और हिमाचल प्रदेश के देवी-देवताओं का भी इनको आशीर्वाद प्राप्त है। आप जोर लगाते रहो, यह इस बार छठी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं और आप इन्तजार करने रहना और जितनी मर्जी गालियां उधर से देते रहना, सातवीं बार भी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ही होंगे। यह हिमाचल की जनता चाहती है क्योंकि हिमाचल के लोग इनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।
अध्यक्ष महोदय, यह भाषण बहुत लंबा है। यदि आप भी मुझे आधा घण्टा देंगे, तो मैं भी यह सारा पढ़ दूंगा। आप जानते हैं क्योंकि आपको मुझसे प्यार है क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूं और कभी-कभी बोलता हूं।

अध्यक्ष : आप संक्षेप में बोलें।

श्री मनसा राम (**मुख्य संसदीय सचिव**): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में विकास का कार्य शुरू किया गया है इसमें गरीब व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 75,000/-रुपये और 25,000/- रुपये मकान की मरम्मत के लिए रखा गया है। राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत 1,280 घर और इन्दिरा आवास योजना में 2,128 घर स्वीकृत किए हैं। इसी

प्रकार महिला और बच्चों के कल्याण के लिए 375.52 करोड़ रुपये 'बेटी है अनमोल' योजना के लिए स्वीकृत हैं। 1,00,789 गर्भवती माताओं, 4,45,997 बच्चों तथा 1,37,931 किशोरियों को एकीकृत बाल विकास योजनाओं के दायरे में लाया गया है। इतना बजट गरीबों के लिए रखा गया है, यह गरीबों के हक़ में रखा गया है। बाल/बालिका सुरक्षा योजना के लिए 500/-रुपये से बढ़ाकर 2300/-प्रति बच्चा प्रति माह किया गया है। यह गरीब बच्चों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है।

अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों के लिए 51,000/-रुपये और उनकी पौत्रियों के लिए 21,000/-रुपये का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने देश की रक्षा की है उनका भी ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्वयुद्ध के सैनिकों को वर्ष 2015 से 2000/-रुपये से बढ़ाकर 3,000/-रुपये कर दिए हैं। इसी प्रकार 13 नए आदर्श विद्यालय, एक राज्य विश्वविद्यालय, एक निजी विश्वविद्यालय और 18 निजी महाविद्यालय खोले गए है।

02/03/2016/1445/RG/DC/2

अध्यक्ष महोदय, 8 नए नागरिक अस्पताल, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 56 प्रकार की औषधीय मुफ्त में और 10 उपभोगीय निःशुल्क आबंटन की जा रही हैं। यह सारा तो छपा है, यह कोई झूठा पत्रा नहीं है। माननीय राज्यपाल जी आपकी ही तरफ से हैं। उन्होंने यह सब आपके सामने पढ़ा। यह झूठ नहीं है, यह सच्चाई है। यह हमेशा सच होता है, राज्यपाल झूठ नहीं बोलते, पौलीटिशियन्ज झूठ भी बोल सकते हैं। वे आचार्य हैं और आचार्य विद्वान आदमी हैं, विद्वान आदमी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के लिए निर्धारित दरों पर तीन दालें, दो खाद्यान तेल और एक किलो नमक मिलता है। इसी प्रकार से दिहाड़ी को बढ़ाकर 170/-रुपये से 180/-रुपये कर दिया गया है। जलवाहकों का मानदेय बढ़ाकर 1500/- से 1700/-रुपये किया है। आयुर्वेदिक प्रवक्ताओं की अनुबन्ध राशि को 15,300/-रुपये से बढ़ाकर 19,125/-रुपये किया गया है। ऑऊटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को राज्य के भीतर दैनिक भत्ता 130/-रुपये तथा राज्य के बाहर 200/-रुपये प्रतिदिन की दर से प्रदान किया जा रहा है। गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता भी 260/-रुपये से बढ़ाकर 280/-

रुपये किया गया है। इसी प्रकार से किसानों को इस सरकार ने 1,10,500 क्विंटल बीज, 167 मीट्रिक टन कीटनाशक

एम.एस. द्वारा जारी

02/03/2016/1450/MS/dc/1

श्री मनसा राम(मुख्य संसदीय सचिव)जारी-----------

तथा 1 करोड़ 50 हजार रुपये खाद के लिए प्रबंध किया है। इसके अलावा गौ-सदनों के लिए सरकार ने प्रदेश में अच्छा प्रबंध किया है और संवर्द्धन बोर्ड का गठन किया है। सरकार लैंटाना घास प्रभावित क्षेत्र के सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और प्रत्येक परिवार के लिए 100 दिन का रोजगार भी सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत 147.78 लाख श्रम दिवस सृजित कर 3,76,425 घरों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह से सरकार संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और 14वें वित्तायोग द्वारा हस्तांतरित धनराशि के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से 195.39 करोड़ रुपये की धनराशि पंचायतों में आंबंटित की गई है। हिमाचल प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में बहुत सी सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ है और विकास के कार्य इन तीन सालों में बहुत आगे बढ़े हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

अब मैं अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता क्योंकि फिर आप कहीं ज्यादा नाराज न हो जाए। मुझे तो आप भी ठीक चाहिए क्योंकि अध्यक्ष जी मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं तत्तपानी के बारे में बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, तत्तापानी बहुत प्राचीन काल से है जहां पर जमदग्नि ऋषि जी ने तप किया है। तत्तापानी में माघ और बैशाख की सक्रांति को बहुत लोग स्नान करते थे। हजारों लोकल और बाहरी लोग वहां स्नान करते थे और वे वहां पर मुफ्त में स्नान करते थे। वे सतलुज नदी में जगह-जगह बने कुण्डों में स्नान करते थे। जब से तत्तपानी जलमग्न हुआ है तब से लोग परेशान हैं क्योंकि जो

गरीब लोग हैं जो हरिद्वार अस्थियां प्रवाहित करने नहीं जा सकते थे वे वहां पर अस्थियां प्रवाहित करते थे। वे सब लोग अब मुश्किल में पड़ गए हैं। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी तो यह दिक्कत हो गई है कि लोगों को वहां धार्मिक भावना के कारण स्नान करने की आदत है। अब उसमें राजनीति में कुछ चलता है। वहां कुछ बड़े मगरमच्छ भी हैं जिन्होंने वहां

02/03/2016/1450/MS/dc/2

अपने होटल बना दिए हैं और उन होटलों के अंदर पानी ला दिया है। वहां अंदर पानी बढ़िया है और नाहने का भी बहुत मजा है लेकिन अध्यक्ष जी उसमें ऐसा है कि वहां नाहने का बहुत पैसा लिया जाता है। इसलिए अब गरीब लोगों के लिए नाहना मुश्किल हो गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि कुछ समय पहले हमने इनसे बात की थी और एक डेपुटेशन भी इनसे मिला था। मुख्य मंत्री जी ने सख्ती बरती है और वहां पर बड़ी तेज गति से स्नान के लिए, पुराना तत्तपानी की याद के लिए काम शुरू करवाया है। आप इस बात से हैरान होंगे कि जमदग्नि ऋषि के तप से जहां-जहां तत्तपानी का दरिया चलता है वह गर्म पानी ऊपर आ गया है। वह डैम काफी ऊंचा है लेकिन वह पानी उसके साथ आ गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से वहां पर होटल भी बन रहा है। बड़े पहले वहां टूरिज्म का होटल चलता था और उसके आगे भी चिण्डी नामक स्थान पर टूरिज्म का बहुत बढ़िया होटल बना है। इसलिए अध्यक्ष जी, उस तीर्थस्थान के लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने तेज गति से दुबारा उसका निर्माण करने के लिए कहा है और गरीब लोगों को नाहने के लिए सस्ता प्रबंध करके मदद की है लेकिन मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे अभी इन्होंने कहा है कि काम हो जाएगा तो वह काम अभी तो तेज गति से शुरू होगा लेकिन 5-6 महीने के बाद काम कछुए की चाल से चल पड़ता है।

जारी श्री एस0एस0 द्वारा-----

02.03.2016/1455/SS-AG/1

श्री मनसा राम, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जब कछुए की चाल का पता लग जाए, वैसे हम इसके बारे में आपको बतायेंगे, तो उसी वक्त इसको तेज़ किया जाए। मुझे आशा है कि वे इस काम को करेंगे। अध्यक्ष महोदय, करसोग बहुत सुन्दर जगह है। इमला-बिमला खड्डें चलती हैं। उसमें चेनेलाइजेशन के लिए भी केस बना है। लेकिन वह भी कछुए की चाल से चला हुआ है। कोई तेज़ गति से नहीं चलता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और विद्या स्टोक्स जी से भी प्रार्थना करूंगा कि महाभारत के समय से इमला और बिमला बड़ी पवित्र नदियां हैं। वे छोटी खड्डें हैं, उनके किनारों पर बड़ी उपजाऊ जमीन है। उससे बहुत किसानों को फायदा हो सकता है। वहां पर सब्जियां पैदा की जा सकती हैं। करसोग वैली में बहुत धान होती है। वहां पर और भी बढ़ियां फसलें होती हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप उस क्षेत्र की ओर ध्यान दें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी 11 सड़कें तीन साल से एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस में फंसी हुई हैं। कोई पूछता नहीं है हालांकि हम खूब जोर लगाते हैं। मैं लोक निर्माण के कर्मचारियों की खिलाफत नहीं करता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिये।

श्री मनसा राम(मुख्य संसदीय सचिव)ः आपकी (मुख्य मंत्री) कृपा से मैं डॉक्टर परमार के समय से राजनीति में रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कहूंगा कि आप करसोग में ऐसे कर्मचारियों को पोस्ट करें जोकि इन कामों को पूरा करें। इसमें मदद करें क्योंकि सिर्फ दो ही साल बचे हैं।

नाबार्ड की सड़कों में भी काम लगना चाहिए। डिम लाइट की समस्या सारे हिमाचल प्रदेश में है। यह समस्या करसोग में भी है। इस डिम लाइट में भी सुधार किया जाए। साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से आई0टी0आई0 मिला। उसके लिए जमीन भी मिल गई। उसके लिए पैसा भी आ गया लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हो सका। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा। मैं बहुत पुराने समय से उनका बड़ा भक्त रहा हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए।

02.03.2016/1455/SS-AG/2

इसी तरह से मेरी सीवरेज लाइन जो करसोग के लिए है वह मंजूर है। लेकिन उसमें काम लगाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे युवा मंत्री हैं और इस ओर विशेष ध्यान देंगे। करसोग का दौरा भी करेंगे। करसोग भी मंडी जिला में सबसे बैकवर्ड है। वहां पर कृपा हुई है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पर डिपो दिया है। डिपो सुन्दरनगर से 112 किलोमीटर पर है और शिमला से 122 किलोमीटर पर है और अभी तक वहां सिर्फ नाम का ही डिपो है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बसों का भी प्रबंध किया जाए। वहां पर भवन निर्माण के लिए भी पैसा दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब का बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

02.03.2016/1455/SS-AG/3

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे लिए थोड़ा समय का ध्यान रखना। 25 फरवरी, 2016 को जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां सदन में सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण पढ़ा, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बाहर दूसरी स्टेटों पर नहीं जाऊंगा और खासकर अपने विधान सभा क्षेत्र पर ही प्रकाश डालूंगा। कुछ हमारे सीनियर सदस्य, सी0पी0एस0 बैठे हैं, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बाहर की बातें ज्यादा कहीं और अभिभाषण पर कम बोला। देश पर जो कुठाराघात कर रहे हैं उनका पक्ष लिया। मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देश सेवा की है। यहां पर और भी कर्नल साहब बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हुए हैं और जिन परिवारों ने अपना सदस्य खोया है उनसे पूछिये। हमने भी खोया है। हमारे दादा, पड़दादा, फादर और कईयों ने डिफैंस सर्विसिज़ में सेवा की है। मेरा कहने का मतलब है कि दुख उन्हीं परिवारों को होता है जिन्होंने अपना सदस्य खोया होता है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि आइंदा ऐसे शब्द इस माननीय सदन में न बोले जाएं जिससे उन्हें ठेस पहुंचे।

अध्यक्षः आप किस चीज़ के लिए रैफर कर रहे हो?

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, यहां पर जे0एन0यू0 की बात हुई, अफ़जल की बात हुई, हरियाणा की बात हुई, कश्मीर की बात हुई --(व्यवधान)--

जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1500/av/as/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल क्रमागत

यहां पर महिला आरक्षण की बात हुई कि सरकार ने 58 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। परंतु ये लोग भूल गये कि यह आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में माननीय धूमल जी के कार्यकाल में मिला था। यहां पर पंचायती राज चुनाव के बारे में बोला गया कि बड़ी पारदर्शिता से चुनाव हुए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों केस कोर्ट में गये हैं। हमारे यहां जो बी0डी0सी0 का चुनाव हुआ उसमें चेयरमैन(पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड) ने सामने बैठाकर चुनाव करवाया और उनको बाहर नहीं निकलने दिया। नल के पानी को गड़वी में भरकर उसको गंगाजल मानकर लोगों से कसमें खिलाई फिर चुनाव किए गए; तो इस तरह की पारदर्शिता है। आप अभी भी पता कर सकते हैं। एस.डी.एम. कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में; कई जगह केस न्यायालय में चले गये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बार जाकर आये हैं। परंतु ये वहां पर बाई एयर गये हैं। इनको पता था कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, बहुत धक्के लगेगें इसलिए बाई रोड क्यों जाना, बाई एयर ही जाते हैं। इन्होंने वहां के लिए दो दौरे किए। मैं यहां पर सभी सड़कों का नाम नहीं लेना चाहता परंतु सड़क के नाम पर मैंने बहुत रिक्वैस्ट की है। खड्डों में आप लोग लूप नहीं डाल सकते तो मिट्टी ही भर दो। आगे इलैक्शन के दौरान वायदे किए गये कि चवाड़ी में सिविल कोर्ट खोलेंगे मगर आज तक नहीं खोला गया। चवाड़ी नगर पंचायत में सिवरेज सिस्टम 412.93

लाख रुपये माननीय धूमल जी ने अपने पिछले कार्यकाल में दिया था मगर वह पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। दुर्भाग्य यह रहा कि सरकार बदल गई, तीन वर्ष हो गये मगर वह पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। यहां पर अभी मंत्री जी बैठे नहीं है, अगर सुन रहे होंगे तो इस काम को जल्दी से शुरू करवाएं। चवाड़ी-चम्बा सुरंग की बात करते हैं मगर आज तक नहीं खुली।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2.3.2016/1500/av/as/2

ककीरा में तहसील खोलने की बात करते हैं, उपतहसील सिहुंता को तहसील का दर्जा देने की बात करते हैं। पी.एच.सी. सिमोट को सी.एच.सी. का दर्जा देने की बात करते हैं। पी.एच.सी. सिहुंता को सी.एच.सी. देने की बात करते हैं। कालीधार के समाधान की बात करते हैं। सिहुंता-चम्बा डबल लाइन की बात करते हैं। गवर्नमैंट हाई स्कूल सिहुंता को अपग्रेड करने की बात करते हैं, गवर्नमैंट सीनियर सैंकेंडरी स्कूल सिमोट में साईंस क्लासिज बैठाने की बात करते हैं। गवर्नमैंट मिडिल स्कूल मठोलू का दर्जा बढ़ाने की बात करते हैं। कॉलेज में बस लगाने की बात करते हैं। मगर इनमें से आज तक कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। सारे के सारे वायदे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा क्योंकि आप वहां पर दो बार गये हैं। मगर आपने वहां पर रोड्ज की हालत नहीं देखी। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय शुरू हुए थे वे वहीं अधर में लटके हुए हैं। अगर मैं उनको गिनना चाहूं तो वह बहुत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 27 काम ऐसे हैं जो वहीं के वहीं पड़े हैं।

यहां पर सामाजिक पैंशन की बात भी हुई। यहां पर किसी माननीय सदस्य ने ठीक कहा था कि जो 80 वर्ष से ऊपर के लोग है उनको यही पता नहीं है कि उनको इनकम सर्टिफिकेट लगता है या नहीं। क्या औपचारिकताएं होती है, विभाग ने उस बारे में आज

तक किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने कल बोला था कि सामाजिक पैंशन आपके पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में बंद रही। मैं मानता हूं कि आपने आय सीमा 35 हजार रुपये की है परंतु आज कोई भी पटवारी 35 हजार रुपये लिखकर खुश नहीं है। वे कहते हैं कि हमें नौकरी करनी है। आई.आर.डी.पी. हो या दूसरे हो; कोई भी पटवारी आपको 35 हजार रुपये इनकम लिखकर नहीं देगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम आई.आर.डी.पी. में; जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको

टीसी द्वारा जारी

02.03.2016/1505/TCV/AS/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल --- जारी

यहां पर आवास योजना की बात हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आवास योजना की राशि 75 हजार की है। परन्तु बजट उतना ही रखा। जितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए था उतने लोगों को लाभ नहीं मिला। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी एक चीज़ और है। आपने जो जरनल कैटागिरी के लोग थे, जो बिलो पॉवर्टी लाईने से नीचे थे, आई0आर0डी0 पी0 में थे, उनको आपने वैलफेयर के माध्यम से आवास योजना बिल्कुल बन्द कर दी है। जो ब्लॉक के माध्यम से मिलती थी वह भी दो परसेंट रखी है। क्या जरनल लोग गरीब नहीं होते? जनरल लोग भी गरीब होते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि उनके लिए भी कुछ सोचें। एस0टी0/एस0सी0/ओ0बी0सी के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। मैं भी उस कैटागिरी से हूं। जिला चम्बा में 50 परसेंट एस0टी0 हैं। पिछली बार उनके लिए पूरे जिले को 12 लाख रूपये का बजट गृह निर्माण के लिए दिया गया था। जब मैं वहां गया और वैलफेयर ऑफिसर को पूछा तो उन्होंने बताया कि बजट ही इतना आया है। 50 परसेंट एस0टी0 जिला चम्बा में है। कम से कम परसेंटेज़ देकर बजट दिया करें। यह मेरा अनुरोध रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ पेयजल योजना की बात हुई। इस सदन में इस बारे में बहुत लम्बी चर्चा हुई। मैं उसके बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल टैंक हैं उनके ढकन नहीं हैं, वे खुले हैं। मेरा निवेदन

है कि उन टैंक को कवर किया जाये और समय पर उनकी सफाई की जाये। चाहे स्कीम WSS या WISS हो बैड कहीं भी नहीं बना हुआ है। मैं नगर पंचायत चुवाड़ी की बात करता हूं , वहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं हैं। पुरानी जो पाईपें बिछाई गई है, वह इतनी सड़ चुकी है कि गंदा पानी उसमें जा रहा है। मेरा माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उन पाईपों को बिछाये हुए 40-40 साल हो गये हैं, उनको बदला जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास की बात तो क्या जो विधायक निधि मैंने दी है। उससे अभी तक तीन साल के अन्दर कोई भी काम नहीं हुआ है। जब मैं प्रश्न लगाता हूं तो अधूरी सूचनायें भेज दी जाती है। मैं मानता हूं जो विधायक सत्ता पक्ष में बैठें हैं, उनके काम होते होंगे। परन्तु अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मुख्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि काम करने में भेदभाव किया जा रहा है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, हो सकता है इनके काम होते

02.03.2016/1505/TCV/AS/2

होंगे। परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में एक भी काम नहीं हुआ है। जहां तक सड़कों की बात है, एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में हमने जो सड़कें डाली थी, उनमें से एक भी सड़क की डी0पी0आर0 तैयार नहीं हुई । मैंने फिर प्रश्न लगाया हुआ है और ये जवाब दे देंगे कि कार्य प्रोग्रेस में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सड़कों का काम चला हुआ है और मुख्य मंत्री महोदय ने इनका उदघाटन किया हुआ है। लेकिन ये काम कैसे चला है? इसके लिए मैं स्वयं कोर्ट गया हूं । वह काम बन्द किया हुआ था। हाईकोर्ट का मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने उस काम को शुरू करवाया है। आपने रूबैंणा-कथ्याडी रोड वाया परसयारा का उदघाटन किया था, उस काम को कब खत्म होना था लेकिन आपको बताया ही नहीं होगा कि उस पटिका में क्या लिखा हुआ है। मुझे दुख हुआ कि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को गुमराह किया गया है। यहां पर एक सांझी नाला पुल है। माननीय धूमल जी ने उसका उदघाटन किया था । उसकी पटिका ही वहां से उखाड़ दी गई है। काम होता नहीं है जो हो रहा है, उसको तो मत रोको। माननीय

मुख्य मंत्री जी एक हाथीधार रोड़ का आपने उद्घाटन किया था । वह आज से दो साल पहले किया था, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

02.03.2016/1510/RKS/DC/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल...जारी

मैं कोर्ट में गया हूं तब वह काम शुरू किया गया। आपने 2 साल पहले उसका शिलान्यास किया था। आपको गुमराह किया जाता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में इतना पॉल्यूशन है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप तो फाइनल ईयर में हैं, आप पास आऊट होने वाले हैं। मगर हम फस्ट ईयर में है, अभी हमें ओर स्टडी करनी है। अगर स्वास्थ्य चैक करवाना हो तो पहले पॉल्यूशन वाले से पूछो तब हॉस्पिटल जाओ। बी. एम.ओ को डराया जाता है, सी.एम.ओ. को डराया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी स्लिप के बगैर कोई स्वास्थ्य चैक करवाने आएगा तो उसको सस्पैंड कर दिया जाएगा, उसकी बदली कर दी जाएगी। यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बहुत सी चीजें इस प्रकार की है। अगर बिजली का मीटर लगाना हो, पानी का कनैक्शन लगाना हो तो मेरी स्लीप जाएगी तब लगेग। स्वास्थ्य मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और वन मंत्री जी इस बात के उदाहरण हैं। लोगों को गुमराह किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बिजली के बारे में बताना चाहता हूं। अभी तक कई गांवों में बिजली नहीं है। बिजली की लाइनें पेड़ों के साथ लगी हुई हैं। जो ट्रांसफार्मर आज लगाया जाता है , वह कल जल जाता है। वे कहां से खरीदे जाते हैं, किस क्वालीटी के हैं? जहां से खरीदे जाते हैं वहां मैंने पूछा तो बताया गया कि जब खरीदते हैं तो कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर चाहिए। परन्तु जब पैसा देने

की बारी आती है तो बेचने वाला कहता है कि हमें थरड क्वालिटी के ट्रांसफर देने के लिए भी रोना पड़ता है। इसलिए कृपया आप बिजली विभाग को बता दीजिए की अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर खरीदें ताकि वह लम्बे समय तक चलें। लोगों को अच्छी सुविधा मिले। अभिभाषण में ओर भी बातें कही गई हैं। परन्तु सैनिक व अर्द्ध-सैनिक बलों में जो अवार्ड सर्विस में रहते हुए या एक्सपायर होने के बाद मिलते हैं चाहे वे सी.ओ.एस. अवार्ड है, प्रसंशा पत्र है, एस.एम.मैडल है, कीर्ति चक्र है, शौर चक्र है वीर चक्र है चाहे कोई भी अवार्ड मिलते हैं। इसमें हिमाचल

02.03.2016/1510/RKS/DC2

सरकार इन बलों को क्या देती है?मैंने कहीं भी आज तक इस बारे में नहीं पढ़ा। कृपया आप उनका भी ध्यान रखिए। जो अवार्डी है उनकी प्रशंसा के लिए कुछ-न-कुछ धनराशि उनके परिवारों को दी जाए। कानून व्यवस्था के ऊपर मुझे हंसी आती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नवम्बर माह में रतन चन्द शर्मा जी की मृत्यु हुई थी। पूरे गांव के लोग उस लाश को ढूंढते रहे। लेकिन वह लाश 7 दिन के बाद वहां मिली जहां प्रशासन के अधिकारी उस लाश को 20 बार चैक करके आए थे। वे क्या ढूंढते रहे? 7 दिन के बाद वह डैड बॉडी प्लांट कर दी गई। मैंने फोन किया, एक्सपर्ट गए। लेकिन आज तक उस डैथ का यह पता नहीं चला कि डैथ का क्या कारण है? पुलिस फेल है। उस परिवार ने इस घटना के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा। परिवार वाले आज भी यह चाह रहें हैं कि हमारे सदस्य की मृत्यु कैसे हुई? लेकिन इसे साधारण मृत्यु बताया गया। अगर यह साधारण मृत्यु है तो वह डैड बॉडी घर से 8 किलोमीटर दूर कैसे गई। मुख्य मंत्री महोदय, आपने भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है आपने विभाग को आदेश दिए हों, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी घटना कैंथली के समीप वन विभाग के मरूंडा रेस्ट हाऊस की है। जहां एक चपरासी की मृत्यु रात को हो गई थी। डिप्टी रेंजर और गार्ड वहीं थे। उस कर्मचारी को जलाकर एक

प्लास्टिक की कुर्सी में प्लांट कर दिया जाता है। वह कुर्सी नहीं जली, लेकिन वह आदमी जल गया। उसे साधारण मृत्यु बताया गया। उनका नाम कृष्ण चंद है।...

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1515/SLS- DC -1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल... जारी

और यह कैथली मलुण्डा रैस्ट हाऊस की बात है। उस डिप्टी रेंजर को अवार्ड देकर प्रोमोट करके आर.ओ. बना दिया जाता है, गार्ड को बी.ओ. बना दिया जाता है जो बड़े दुख की बात है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें, सोएं न। चम्बा में रेप, डकैती, गोहत्या हो रही हैं और आप कहते हैं कि अच्छा प्रशासन है। कल मैं एक समाचार पढ़ रहा था। एक बैल का गुप्तांग और पूंछ काट दी गई। यह यहीं नजदीक का समाचार है। माफिया चर्म सीमा पर है। चाहे वह ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो या खनन माफिया हो। उनको आजकल कोई नहीं पूछ रहा। उनका काम धड़ल्ले से चल रहा है। पकड़ा केवल गरीब आदमी को जा रहा है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बातें कहने दें। मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात कह रहा हूं। हमारे पास यह सब बताने का यही समय है। इसलिए उन सबके ऊपर अंकुश लगाया जाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक एस.एच.ओ. ने एक गाड़ी पकड़ी। उसमें शराब की 12 पेटियां थीं। उस एस.एच.ओ. को ट्रांसफर कर दिया गया। जो अच्छे कर्मचारी होते हैं उनको बदल दिया जाता है। मैं सड़कों की बात कर रहा हूं। कल्लर झोलना एक रोड है। उसके ऊपर एक जे.ई. ने किसी विशेष व्यक्ति के क्रशन के लिए विभाग की लेबर और मशीनरी लगा रखी है। वह व्यक्ति पाल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन है। वह उस मशीनरी और लेबर को दूसरी जगह दिखाता रहा। वहां पर एक बृज के लिए धूमल साहब ने पैसे दिए थे। विभाग ने उस जे.ई.

को 22 लाख रुपये की रिकवरी शो की है। वह सीमेंट के 3700 बैग खा गया। अब उस जे.ई. को प्रोमोट करके एस.डी.ओ. बना दिया है। मैंने E-in-C को लिखित में इसकी रिपोर्ट भेजी थी। फिर कहते हैं कि हम कौमा में नहीं हैं, साए नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति पर अंकुश लगाओ। आदरणीय वन मंत्री यहां पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना FRA, FCA or DPR के वह रोड कैसे बना? जब तक उस रोड की क्लीयरैंस नहीं हो जाती तब तक उस रोड पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। हम उस रोड को बंद करेंगे। आप उसको चैक करो। उसमें कई हरे पेड़ काटे

02.03.2016/1515/SLS- DC -2

गए हैं। उसको 10,000 रुपये का जुर्माना डाल दियाऔर उसमें सब लोग मिले हुए हैं। उस जे.ई. को सजा न देकर उलटा प्रोमोट कर दिया, एस.डी.ओ. बना दिया। आपका बहुत अच्छा प्रशासन है। आदर्श विद्यालय की बात हुई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कॉलेज चवाड़ी है। उसमें पूरे लैक्चरर्ज़ नहीं हैं। जब भी हम जाते हैं तो वह कहते हैं फलां लैक्चरर नहीं है। हम सी.एम. साहब को लिखते हैं। सी.एम. साहब को भी लिख कर देने का लाभ नहीं क्योंकि पीछे मैंने एक डी.ओ. लिखकर दिया और ये मुकर गए कि मुझे चिट्ठी नहीं मिली जबकि मैंने डी.ओ. पैड पर लिखकर दिया, उस समय तीन व्यक्ति मेरे साथ और थे। हमने कई बार लिखकर दिया कि वहां प्रोफ़ेसर्ज़ भेजो। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अगर सुन रहे हैं तो आप ही शिक्षा मंत्री हैं। कृपया ध्यान दें। स्कूलों की हालत यह है कि कई स्कूलों में डैपुटेशन पर अध्यापक जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या 150-200 में हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास अध्यापक नहीं हैं। रूसा लागू किया जिससे बच्चे परेशान हैं। रिजल्ट समय पर नहीं आ रहा है और बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। अध्यापक पूरे नहीं हैं। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से गुज़ारिश है कि कृपया इस ओर ध्यान दें। बीजेपी के समय में जिन सड़कों और पुलों के लिए पैसा मिला था आज वह सड़कें और पुल बंद हैं। वहां विकास रोक दिया गया है। ब्लॉक की हालत

हमारी क्या है? मैडम आशा जी बैठी हैं। हमारी एक एल.ओ.सी. है जहां नाला है। वहां एक तरफ डलहौजी और दूसरी ओर भटियात विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर एक नाला है जिसके लिए 4.00 लाख रुपये दिए 3 साल हो गए। मैडम ने भी रिक्वैस्ट की थी लेकिन आज तक वह पुल नहीं बना। इसके अलावा एक पुल को मैंने 4.00 लाख रुपये दिए लेकिन जे.ई. बोलता है कि पैसे कम हैं। मैंने और पैसे देकर 7.50 लाख रुपया किया लेकिन अब वह जे.ई. कहता है कि आपने पैसे ज्यादा दे दिए।

जारी...श्री गर्ग जी

02/03/2016/1520/RG/DC/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल----क्रमागत
और कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बलाड़ा में पुल है और खड्ड का नाम लुलैट है। साढ़े सात-सात लाख रुपये का पुल बना है। एस.डी.एम. बी.डी.ओ. की डियुटी कर रहा है और मेरे ख्याल से उसमें एस.डी.एम. भी जे.ई. से हिस्सा मांगता होगा। अब वह पता नहीं, प्रधान जाने। मैंने तो पैसा पंचायत में दे दिया है। वे करांए या न करांए। परन्तु लोग रोते हैं। बोलते हैं कि यह पुल तो आपने बनाया है। परन्तु हमारी पेमेन्ट्स नहीं हुईं, अरे पेमेन्ट मैंने तो करनी नहीं, मैंने तो लिखकर दे दिया था, पैसा डाल दिया था। एस.डी.एम. बी.डी.ओ. की डियुटी कर रहा है। वह कहता है कि वहां कुछ धांधली है। तो वह धांधली किसने पकड़नी है? मैंने तो काम करवाया नहीं है, मैं कोई टैनीकल हैण्ड नहीं हूं, प्रधान मैं नहीं हूं। जिन्होंने काम करवाया है, आप जाकर उनको पकड़ो। तो कोई नहीं पकड़ता। मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि वह भी उसमें कमीशन मांग रहा है। एक एस.डी.एम. एच.ए.एस. ऑफिसर का यह हाल है, तो बाकीयों का क्या हाल होगा? यह बहुत शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष : आप प्लीज वाइन्ड अप करें।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : सर, बस मैं समाप्त करने जा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

दो-चार सड़कों के नाम बताता हूं। एक धारटा मोड़ से नलोह है बी.जे.पी. के समय में यह नई बनी है। गाहर-फगोट वाया चेली, गरनोटा-भौंट पुखरू, मोतला-गोला वाया कायला भ्योरा, बसोलधा-नाहाणा, जोलना-भटेड, मोरड़ू-जोलना, लाहड़-खुडरू सग्रैहण वाया त्रिठा। इसमें मैडम के समय में काम हुआ था। सुरपड़ा-छत्तराहर वाया ताला, चुवाड़ी-लाहड़ू वाया जनरूहन, भोलग जंगला, सिंहुनता-चुवाड़ी वाया लाहड़ू, चुवाड़ी-चम्बा वाया जोत दो-तीन सड़कों का बहुत बुरा हाल है। चुवाड़ी-तुनूहट्टी वाया ककीरा, समोटा-चुवाड़ी वाया ददरियाड़ा रायपुर, चुवाड़ी-नूरपुर, नैणी खड्ड-खैरी वाया मेल चयूण। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन चीजों पर विशेष ध्यान दें। आंकड़ें यहां बहुत बड़े-बड़े दिखाए, परन्तु वे जाते कहां हैं? वे पैसे जाते कहां हैं? आई.टी.आई. की बात हुई कि आई.टी.आई. देंगे। मैं माननीय धूमल साहब का धन्यवाद करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में घरनोटा में एक आई.टी.आई. दी थी। आज इस समय कोई तीन ट्रेड हैं और वही ट्रेड्ज हैं, मैं कई बार लिख चुका हूं और वे भी आधे हैं। एक साल दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में और एक साल दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है।

02/03/2016/1520/RG/DC/2

उपाध्यक्ष : कृपया अब आप समाप्त करें। आपको 25 मिनट हो गए, अब आप बैठ जाएं। अब बहुत हो गया।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं। उद्योगों की बात की है। उद्योगों पर ध्यान दिया जाए। कृषि पर भी ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

02/03/2016/1520/RG/DC/3

उपाध्यक्ष : अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री इन्द्र दत्त लखनपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जगजीवन पाल जी ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया और श्री अजय महाजन जी ने उसका अनुसमर्थन किया, मैं उसके सन्दर्भ में बोलने खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में इस प्रदेश का रिकॉर्ड विकास किया है। विपक्ष के साथियों को विकास नजर नहीं आता है। लेकिन तीन वर्षों में कभी भी सदन में गंभीरता के साथ आम जनमानस की समस्या उठाने में ये नाकाम रहे और अधिकांश समय ये सदन से बाहर रहे और बहिष्कार करते रहे। आज पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर यहां पर चर्चा हो रही है और विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। मैं इस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि और इसके इतिहास की तरफ भी जाना चाहिए। आज प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से जो विकास हो रहा है वह सारी-की-सारी देन स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की है। जिनका विपक्ष के लोग नाम भी नहीं लेना चाहते। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इस देश में जब पंचायती राज में संशोधन हुआ, तो माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने पूरे देश में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इस पंचायती राज ऐक्ट को लागू किया

एम.एस. द्वारा जारी

02/03/2016/1525/Ms/AG/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी-----

और उस समय महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का कि इन्होंने इसको 50 प्रतिशत तक बढ़ाया। लेकिन जिन्होंने शुरूआत की है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जब यह राज्य अस्तित्व में आया था उस समय इस प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज कहां पहुंच गया है इसको भी समझना चाहिए। आप लोग तो उस समय वर्ष 1977 में "स्टेट हुड को मारो ठूड" का

नारा दिया करते थे। माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ने हर क्षेत्र में बुजुर्गों को आत्म सम्मान दिया, उनके मान-सम्मान को बढ़ाया और एक लाख से अधिक बुजुर्गों को इस प्रदेश के अंदर पैंशन की सुविधा प्रदान की। क्या यह कम है?

पी0डी0एस0 सिस्टम इस प्रदेश में लागू हुआ। इस प्रदेश में महंगाई की मार आम जनता को न पड़े, उनके दुःख-दर्द को समझते हुए माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इस प्रदेश के अंदर पी0डी0एस0 सिस्टम लागू किया और यही कारण है कि जहां आज इस पूरे देश में महंगाई की मार आम जनता झेल रही है वहीं हमारे प्रदेश में इतनी महंगाई देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे यही कारण है कि डिपुओं में सस्ता राशन मिल रहा है।

आज "मनरेगा" की बात की जाती है। जिस समय यू0पी0ए0-1 की सरकार ने इस पूरे देश के अंदर अपने प्रथम कार्यकाल में इस महत्वकांक्षी योजना को चलाया था, उस समय यहां पर विपक्ष के लोग,

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

"मनरेगा" को "मनरेगा" भी नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था और कई जगह "मनरेगा" के काम को न करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अभी हाल ही की बात है, जब इस देश के अंदर माननीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो लोकसभा के अंदर उन्होंने "मनरेगा" को एक निष्क्रिय योजना की संज्ञा दी और "मनरेगा" के जो प्रावधान थे

02/03/2016/1525/Ms/AG/2

उनके अंदर कट लगाया। फिर जब पूरे देश का सर्वे सामने आया तो मजबूरन जो यू0पी0ए0 सरकार की नीति थी, उस पर मोहर लगाते हुए इस वर्ष उन्होंने बजट में राशि को बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

देश के अंदर गरीबों को मकान बनाने की बात की जाती है। जो हमारे प्रदेश में 4000 से

अधिक लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा मिलता था पिछले वर्ष उसको काटकर आधा कर दिया गया। गरीबों के हितैषी कौन हुए? अभी भी जो देश का बजट है उसमें उन मकानों की कोई चर्चा नहीं है। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे केन्द्र में जो बी0जे0पी0 की सरकार है उनसे निवेदन करें कि गरीबों के मकानों को बहाल किया जाए। जो प्रदेश का लगभग 4000 मकानों का कोटा था, वह बहाल किया जाए। मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे गरीब लोग जिसमें अगड़ी जाति के भी पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए भी मकानों का प्रावधान किया और उन मकानों की रिपेयर के लिए भी प्रावधान किया बल्कि एक स्पैशल बजट का प्रावधान किया है।

प्रदेश में 7700 आशा वर्कर्ज की नियुक्ति हुई। पूर्व में आपकी सरकार के समय में इन आशा वर्कर्ज को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। जब प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई और इन आशा वर्कर्ज को बहाल किया।

मेधावी छात्र-छात्राओं को टेबलेट प्रदान किए गए। किसानों/बागवानों को बीज और उपकरण उपलब्ध करवाए गए। इसके अलावा "कौशल विकास भत्ता" के अंतर्गत 60 हजार से अधिक नौजवानों को 26 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ दिए गए।

भवन और अन्य सह निर्माण कल्याण बोर्ड के द्वारा 88 हजार 534 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ और 20 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उनको दिया गया।

जारी श्री एस0एस0 द्वारा-----

02.03.2016/1530/SS-Ag/1

श्री इंद्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

पी0टी0ए0 के जो अध्यापक थे उनके ऊपर आपके समय में क्या-क्या अत्याचार हुए यह किसी से छुपा नहीं है। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने सत्ता सम्भालते ही इन पी0टी0ए0 के टीचरों को बहाल किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि

उस समय जो पी0टी0ए0 पर टीचर लगे हुए थे और जिन्होंने कोर्ट में जाकर अपने हकों की लड़ाई लड़ी, वहां से उन्हें रिलीफ मिला। इस दौरान जब प्रदेश सरकार ने उन पी0टी0ए0 के टीचरों को बहाल किया और कंट्रैक्ट में उनको बदला तो दो वर्ष के कार्यकाल का गैप जो बीच में आया है, कुछ 1500 जो हमारे अध्यापक हैं उनको उसके लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका जो टर्मिनेशन पीरियड है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। ये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। जहां तक मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र की बात है मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में ही सामाजिक सुरक्षा पैंशन के 857 केस पिछले वर्ष में स्वीकृत हुए हैं। कुछ सदस्य कह रहे थे कि पैंशन ही नहीं मिल रही है, लेकिन जिन लोगों ने धरातल पर काम किया, गांव में गये, बुजुर्गों के फार्म भरे तो उनको लाभ मिले हैं। आई0पी0एच0 विभाग में ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़े 12 बोरवैल स्वीकृत हुए। उसमें से 5 बड़े बोरवैल काम करने भी शुरू कर गये हैं। 150 से अधिक हैंडपम्पस इंस्टॉल हुए। लगभग 100 किलोमीटर से अधिक पुरानी जो पाइपें थीं उनको बदला गया। 9 करोड़ रुपये की लागत से नगर पंचायत भोटा में सीवरेज सिस्टम का अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शिलान्यास किया। उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 बड़े ब्रिज बनाये जा रहे हैं। 4 सड़कों के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें 35-40 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। बिजली विभाग में सैंकड़ों के हिसाब से पुराने पड़े पोलों को बदला गया। जो लोगों की मांग थी, उसके अनुसार थ्री फेस की तारें बिछाई गईं। नये ट्रांसफार्मर्ज़ लगाये गये। 33-33 के0वी0 के दो ट्रांसमिशन सैंटर्ज़ मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए। इंडस्ट्रीयल एरिया एक करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। उसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। बिझड़ी में जो हमारा घटवाल क्षेत्र है वहां पर सब-तहसील को तहसील बनाया गया। हमारे बड़सर विधान सभा क्षेत्र में जो सी0एच0सी0 है उसके लिए अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब दौरे पर थे तो उसमें 20 बिस्तर अतिरिक्त देने की घोषणा की। बिझड़ी का जो हमारा

02.03.2016/1530/SS-Ag/2

पी0एच0सी0 है उसको सी0एच0सी0 का दर्जा देने की घोषणा की। दो नये आयुर्वेदिक

संस्थान खोलने की स्वीकृति मिली। पुलिस चौकी, बिझड़ी को स्थाई करने का दर्जा मिला। इसलिए यह कहना कि प्रदेश सरकार कोमा में है और कुछ नहीं हो रहा है, सही नहीं है। यह बात अलग है कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वे विकास के बारे में कितने गम्भीर हैं वह पिछले तीन वर्षों से हम यहां पर देख रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी ने कभी भी भेदभाव करने की राजनीति नहीं की है। पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। हर क्षेत्र में जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनकी मांग के अनुसार जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए थे, वे दिये। सीमित साधनों के बावजूद जो भी चुने हुए प्रतिनिधियों ने मांगा, आम जनता ने मांगा, उन्हें माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने दिया है। माननीय वीरभद्र सिंह जी की लोकप्रियता की वजह से ही आज विपक्ष के लोग सकते में हैं। वे अपने वजूद की तलाश में हैं। उनको लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी सातवीं बार इस प्रदेश की बागडोर सम्भालेंगे। तो क्यों न अब जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। जनता को बरगलाया जाए और यह कोशिश की जाए कि प्रदेश सरकार काम नहीं कर रही है। जबकि यह तथ्यों के विपरीत है

जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1535/av/as/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल क्रमागत

प्रदेश के लोगों को करोड़ों के लाभ मिल रहे हैं। हर क्षेत्र में; जहां भी माननीय वीरभद्र सिंह जी जाते हैं उस क्षेत्र को करोड़ों की सौगात मिलती है। यह अपने आप में एक मिसाल है। इस प्रदेश ने विकास के नये आयाम छूये हैं। जहां डॉ.वाई0एस0परमार ने इस प्रदेश की भूमिका बनाई वहीं पर इस प्रदेश को माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने अपनी दूरदृर्ष्टि और मेहनत से सींचा। इस प्रदेश को एक मोडल के रूप में अन्य प्रदेशों से आगे ले जाने का अगर किसी ने काम किया है तो केवल माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किया है। इसका पूरा श्रेय माननीय वीरभद्र सिंह जी को जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं ज्यादा बात न करते हुए यहां पर मुख्य संसदीय सचिव श्री जगजीवन पाल जी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया है, मैं उस पर बोलता हुआ अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं, जय हिन्द।

2.3.2016/1535/av/as/2

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण को पढ़कर सदन को सुनाया। मैं उस अभिभाषण के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने यहां पर जे0एन0यू0 की बात की, हरियाणा की बात की, पंजाब की बात की। मैं इधर-उधर के प्रांतों की बात न करता हुआ सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश तथा अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा। यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार के द्वारा प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के बड़े-बड़े वायदे किए गए। इन लोगों ने यहां पर सरकार की बहुत प्रशंसा की है। परंतु प्रदेश की जनता सबकुछ जानती है। यहां पर स्वास्थ्य सुविधा देने की बड़ी-बड़ी बातें की गई। मैं इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करूंगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर के कितनी चिन्तित है। मैं नाचन विधान सभा क्षेत्र के अपने गोहर सिविल अस्पताल की बात जरूर करना चाहूंगा। वहां उसको अपग्रेड हुए डेढ़ वर्ष का समय हो गया है। हमने एक बार नहीं, बार-बार सरकार से निवेदन किया तथा सरकार ने हमारा निवेदन स्वीकार भी किया और उसको अपग्रेड किया। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मगर जिस दिन उस अस्पताल का उद्‌घाटन हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी सिविल अस्पताल गोहर का उद्‌घाटन करने आए थे और वहां की जनता ने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था। जनता ने कहा था कि सी.एच.सी. गोहर को आपने सिविल अस्पताल का दर्जा दे दिया है। उसको 35 बैड से बढ़ाकर 50

बैडिड कर दिया। मगर मैंने और वहां की जनता ने मंत्री जी से निवेदन किया था कि आपने इस अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा दे दिया है। इसलिए इस अस्पताल के लिए डॉक्टर्ज के कुछ नये पद सृजित किए जाएं। वहां हमने मांग की थी कि यहां पर गायनोकोलोजिस्ट और चाइल्ड

2.3.2016/1535/av/as/3

स्पैशेलिस्ट होना चाहिए। उस अस्पताल के अंदर 8 डॉक्टर्ज के पद सृजित है लेकिन आठ पद सृजित होने के बावजूद

टीसी द्वारा जारी

02.03.2016/1540/TCV/AS/1

श्री विनोद कुमार --- जारी

उस समय भी वहां पर तीन डॉक्टर होते थे और 5 डॉक्टरों के पद रिक्त उस समय भी थे और आज भी चल रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारी सी0एच0सी0 छम्यार का भवन बनकर तैयार हुआ और उसका उद्‌घाटन भी माननीय मंत्री जी ने किया था। वहां पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह सी0एच0सी0 भी तीन-चार पंचायतों को फीड करती है। पूरी जनता ने और हमने भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि आज इस सी0एच0सी0 के भवन का उद्‌घाटन करने के लिए आप यहां पर आये हैं। जिस दिन इस सी0एच0सी0 का उद्‌घाटन हुआ था, उस दिन उसके अन्दर पूरा स्टॉफ उपलब्ध था। डॉक्टर, फार्मासिस्ट और स्टॉफ नर्स भी उस सी0एच0सी0 के अन्दर थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा उस पंचायत के अन्दर जाना हुआ और उस प्रवास के दौरान मैं उस सी0एच0सी0 में गया तो वहां पर कोई भी स्टॉफ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉफ नर्स वहां पर बैठी हुई थी। मैंने उनको पूछा कि बाकी स्टॉफ, डॉक्टर, फार्मासिस्ट कहां है? उस स्टॉफ नर्स ने कहा कि जैसे ही आपका कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके अगले दिन से न डॉक्टर है और न फार्मासिस्ट है। इस घटना को घटे हुए लगभग छः महीने का समय हो चुका है। आपके हॉस्पिटल में डाक्टर नहीं

है,आपके हॉस्पिटल में फॉर्मासिस्ट नहीं हैं और बात हम करते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की । यह कैसे हो पाएगा। इसके अलावा अनेकों प्रमाण मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के हैं। पी0एच0सी0, बग्गी में डॉक्टर डैपूटैशन पर आते हैं, कभी एक डॉक्टर बैठता है और कभी दूसरा डॉक्टर बैठता है। एक से दूसरी बार जब मरीज चैक करवाने आता है, तो डॉक्टर पूछता है कि पिछली बार डॉक्टर ने क्या कहा था? उसको खुद भी पता ही नहीं होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां पर डॉक्टर नहीं हैं, उन जगहों पर डॉक्टर भेजे जायें, फॉर्मासिस्ट भेजे जाये। यहां पर बातें तो बड़ी-बड़ी की गई । लेकिन बातें बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम धरातल पर काम करेंगे तो उसका ही कुछ लाभ होने वाला है। अन्यथा कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष जी, यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा बड़े-बड़े और खोखले दावे किए गए। सरकार की सिफारिश की गई। मैं तो इसे सरकार की सिफारिश नहीं, बल्कि सरकार की चमचागिरी कहूंगा। लेकिन झूठी सिफारिश करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। उस ज़मीनी

02.03.2016/1540/TCV/AS/2

हकीकत को जनता भी जानती है और शायद ये लोग भी जानते होंगे। आज भी हिमाचल प्रदेश के अन्दर न जाने ऐसे कितने स्कूल हैं, जहां पर एक भी अध्यापक नहीं हैं। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि जो सरकारी स्कूल सरकार ने खोले हैं, उन सरकारी स्कूलों में आज भी अधिकतर बच्चें उन गरीब लोगों के पढ़ते हैं, जो अपने दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। आज उन सरकार स्कूलों में, उन किसानों के बच्चे पढ़ते हैं जो किसान कभी सूखे की मार झेल रहा है, कभी भारी बारिश की मार झेल रहा है और कभी ओलावृष्टि की मार झेल रहा है। न जाने कैसे-कैसे वह अपना गुजारा करता है। उन किसानों और मज़दूरों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि न जाने हिमाचल प्रदेश में कितने ही स्कूल ऐसे हैं, जहां आज भी अध्यापक नहीं हैं। मैं हिमाचल की बात नहीं करूंगा लेकिन नाचन विधान सभा क्षेत्र में भी आज भी कुछ ऐसे प्राईमरी स्कूल है, जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। अगर है तो डैपूटेशन पर आते हैं।

श्री आ0के0एस0 द्वारा जारी ------

02.03.2016/1545/RKS/DC/1

श्री विनोद कुमार ...जारी

सर, नोट करेंगे हमारा प्राइमरी स्कूल खुम्भा, पलोता मिडल स्कुल कूट जिसमें एक ही शारीरिक अध्यापक है।

अध्यक्षः आप एक लिस्ट लिखकर के दे दीजिए।

श्री विनोद कुमारः सर, मैं लिखकर के भी दे दूंगा। नाचन विधान सभा क्षेत्र में बहुत स्कूल खुले हैं या खोले गए हैं। उन स्कूलो को खोले हुए चार समय से भी अधिक समय हो गया है। कुछ हमारी सरकार के समय में भी खुले हैं। लेकिन आज दिन तक बच्चों को बैठने के लिए सरकार ने वहां कमरों की व्यवस्था नहीं की है। हमने अनेकों बार अध्यापकों का विषय सरकार के समक्ष रखा। लेकिन आज तक अध्यापकों की वयवस्था नहीं हो सकी। कमरों की व्यवस्था नहीं हो सकी। मैं उन स्कूलों के नाम भी लेना चाहूंगा। प्राइमरी स्कूल नालू, पलोता, ओडी में एक भी कमरा बच्चों को बैठने के लिए नहीं है। यह उन मजदूरों व किसानों के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार बेहतर शिक्षा देने की बात करती है। जब तक हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, बैठाने के लिए कमरे नहीं हैं तो यह कैसे संभव हो पाएगा। यहां पर बात की गई बेहतर सड़क सुविधा देन की। तीन बार हम भी अपनी विधायक प्राथमिकता दे चुके हैं। इससे पूर्व भी हमारे विधान सभा क्षेत्रों से जो विधायक रहे या जो हमारे साथ बैठे हैं, न जाने कितनी स्कीमें विधायक प्राथमिकता की उनके चुनाव क्षेत्रों की पड़ी हैं। मेरे निवाचन क्षेत्र में 20-30 सड़कें ऐसी हैं जिन्हें हमने विधायक प्राथमिकता में डाला है। लेकिन एक भी सड़क की डी.पी.आर. इन तीन सालों में सरकार ने तैयार नहीं की। सरकार बात करती है, बेहतर सड़क सुविधा देने की। मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र में सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं। मुख्य मंत्री जी के आदेश पर कुछ सड़कों में टारिंग भी हुई थी। परन्तु एक

हफ्ते के अंदर वह टारिंग उखड़ गई। जितने गड्ढे पहले थे, उससे ज्यादा गड्ढे आज उन सड़कों में हैं। मैंने प्लानिंग की बैठक में भी और पिछले सत्र में भी सरकार से निवेदन किया था कि जिन ठेकेदारों ने वह टारिंग की है , उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए । और सड़क को फिर से टारिंग

02.03.2016/1545/RKS/DC/2

करने के आदेश दिए जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बग्गी से चैलचौक, चैलचौक से जहल, चैलचौक से पंडोह, चैलचौक से मौवीसेरी, चैलचौक से रोहांडा, धनोटू से करसोगा, पाली से कीलिंग, जुघान से छात्रा, स्यां से सलवाहण आदि सड़कों की दशा बहुत ही खराब है। मुख्य मंत्री जी जब आप पिछली साल जिला मण्डी के प्रवास में आए थे तो आपने स्वयं सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग को आदेश दिया था। नाचन विधान सभा क्षेत्र के खेओड़ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक जनसभा की थी। उस जनसभा में जब आप करसोग से गोहर तक गाड़ी में आए थे, तो उस जनसभा में आपने विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को कहा था कि एक महीने के अंदर इन सड़कों की टारिंग करनी होगी नहीं तो एस.ई. को एक्स.ईएन., एक्स.इएन., को एस.डी.ओ. और एस.डी.ओ. को जे.ई. बना दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। न उन सड़कों की टारिंग की गई और न ही उन अधिकारियों की डिमोशन की गई।

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1550/SLS-AG-1

श्री विनोद कुमार... जारी

यह हमारी सड़कों की हालत है।

अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, यहां पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की बात आई। मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा क्योंकि जनता जानती है कि उन्हें किस तरह का पानी मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण शिमला है जहां पर पीलिया के न जाने

कितने केस आए; कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अध्यक्ष जी, मैं अपने नाचन विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मैंने दो दिन पहले एक प्रश्न लगाया था जिसका उत्तर मुझे माननीय मंत्री जी से मिला है। उस उत्तर में लिखा है कि नाचन विधान सभा क्षेत्र में कुल 86 पेयजल योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं और उनमें केवल 40 स्कीमें ऐसी हैं जिनमें फिल्टर बैड बनें हैं जबकि 46 में फिल्टर बैड काम नहीं कर रहे हैं। यह विभाग द्वारा दी गई जानकारी है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह गलत जानकारी है। मैं आज इस बात को दावे के साथ कहना चाहूंगा कि जो 86 पेयजल योजनाएं नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंदर हैं वहां पर 90% स्कीमें ऐसी हैं जिनमें फिल्टर बैड काम ही नहीं कर रहे हैं जबकि आप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की बात करते हैं। यह पता नहीं कैसे संभव होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

02.03.2016/1550/SLS-AG-2

श्री बलबीर वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, 25 फरवरी को जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है जिस पर माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और श्री अजय महाजन जी ने उसका अनुसमर्थन किया, आप ने मुझे उस पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने समाज के सभी वर्गो के लिए, सभी धर्मों के लिए और राज्य के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

शिक्षा का क्षेत्र मुख्य मंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्य मंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के अंदर 21 प्राथमिक विद्यालय खोले, 49 प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला, 92 प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च पाठशाला,

58 उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत किया और 7 नए महा विद्यालय भी खोले। शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के भी बहुत सारे पद सृजित किए। शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण पर 67.50 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की और 6 नए आई.टी.आई. भी खोले गए।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना भी कार्यन्वित करवाई है।

ऊर्जा बचत के लिए प्रदेश के लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को 17 जनवरी, 2016 तक 4,11,274 LED bulb वितरित किए गए हैं।

प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में भी 8.9% की वृद्धि दर्ज़ की गई है।

02.03.2016/1550/SLS-AG-3

माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार प्रत्येक स्तर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए दृढ़ संकल्प है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है।

जारी...श्री गर्ग जी

02/03/2016/1555/RG/AG/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-----क्रमागत

शहरी क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 4,748 बसें 2,289 मार्गों पर चल रही हैं और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक नई पहल करते हुए राज्य में 25 इलैक्ट्रिक बसें आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। कौशल विकास भत्ता योजना जोकि वर्ष 2013 के अन्तर्गत 30 दिसम्बर, 2015 तक 60,879

लाभार्थियों को 26.27 करोड़ रुपये आबंटित किए गए और भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड ने क्षेत्र में 88,534 श्रमिकों का पंजीकरण किया है तथा 65,738 लाभार्थियों को विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 20,25 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया है। माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किसानों द्वारा दस लाख रुपये तक के कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी है। स्वच्छ पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष 1332 बस्तियों को पेयजल योजना की सुविधा प्रदान की गई है और 16,881 हैण्ड पम्प्ज स्थापित किए हैं। बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 45 करोड़, लघु सिंचाई योजना के लिए 152.81 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1984 में महिला ग्राम सभा के गठन का भी प्रावधान किया है जो बहुत ही काबिलेतारीफ है। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत 147.78 लाख श्रम दिवस सृजित कर 3,76,245 घरों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक नई पहल की है जिसमें प्रदेश में गौसदनों की स्थापना और उसकी कार्यपद्धति के लिए प्रदेश गौवंश संवर्धन बोर्ड का गठन किया है और इस उद्देश्य के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार ने 25% प्रीमियम अनुदान के तौर पर 9.22 करोड़ रुपये अंशदान दिया है जिसमें किसानों को 34.5 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है। मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत 23.22 करोड़ रुपये मूल्य का 36,033 मीट्रिक टन सी ग्रेड सेब खरीदा गया है। बागवानी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए 7,54,198 वर्ग मीटर क्षेत्र को एन्टीहेल नेट के अन्तर्गत लाया गया है। 600 हैक्टेयर क्षेत्र को सेब

02/03/2016/1555/RG/AG/3

पुनर्जीवन परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस वर्ष 16,135 किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीकी के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। किसानों

को लाभान्वित करने के लिए मुख्य मंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना उत्तम चारा उत्पादन योजना, दो नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को 80% अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित करने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है जो बहुत काबिलेतारीफ है। पॉली हॉऊस के निर्माण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत 111.19 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 1250 पॉली हॉऊस का निर्माण किया गया है।

एम.एस. द्वारा जारी

02/3/2016/1600/MS/AS/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी---------

इस योजना के अंतर्गत किसानों को 85 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है यह बहुत ही काबिले तारीफ है। इसी तरह से "अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना" के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 1220.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। "मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना" के अंतर्गत 12.60 करोड़ रुपये व्यय तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले दो गांवों के एकीकृत विकास के लिए 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए आठ नये नागरिक अस्पताल,16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और चार उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल के लिए 266 नये चिकित्सक, 15 विशेषज्ञ और 25 दंत चिकित्सक भी लिए गए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञों सहित 47 पद और पैरा मेडिकल स्टाफ के 39 पद भरे गए हैं।

माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रथम अप्रैल, 2015 से 2000/- रुपये से बढ़ाकर

3000/-रुपये की है यह भी काबिले तारीफ है।

विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए "राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना" के अंतर्गत 67,619 विद्यार्थियों को 13.64 करोड़ रुपये धनराशि आबंटित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प-संख्यक, विकलांग और समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 450/-रुपये से 600/-रुपये किया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। 70 प्रतिशत अपंगता वाले व्यक्तियों की और 80 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को 1100 रुपये प्रतिमाह पैंशन की है यह भी काबिले तारीफ है।

प्रदेश के आवासहीन लोगों को "इंदिरा आवास योजना" के तहत 2128 और "राजीव आवास योजना" के अंतर्गत 1280 आवास स्वीकृत किए गए हैं यह भी काबिले तारीफ है। लाभार्थियों को नये आवास निर्माण के लिए 75000 रुपये

02/3/2016/1600/MS/AS/2

तथा आवास के रख-रखाव के लिए 25000/-रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्ष 3080 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य है। "इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना" के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है और एक कन्या पर 25000/-रुपये से बढ़ाकर 35000/-रुपये और दो कन्या पर 20000/-रुपये से बढ़ाकर 25000/-रुपये की है यह भी काबिले तारीफ है।

वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न सड़क योजनाओं के लिए आबंटित कुल 826.82 करोड़ रुपये पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 3318 बस्तियों को सड़क सुविधा प्रदान की जा रही है। सड़क और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड के तहत 543.43 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई है। नाबार्ड में 92 सड़कों और 15 पुलों के लिए 385.62 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास चारों दिशाओं में हो रहा है जिससे मेरा चौपाल चुनाव क्षेत्र भी वंचित नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आशीर्वाद से मेरे क्षेत्र में बहुत सारे अस्पताल खुले हैं। चौपाल का अस्पताल अपग्रेड हुआ, नेरवा का अस्पताल अपग्रेड हुआ और गुम्मा में

पी0एच0सी0 खुली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पी0एच0सीज0 दीं गई और बहुत सारे स्कूल भी खुले। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सड़कों के लिए पैसे भी दिए गए और बहुत सारे नये संस्थान ऐसे खुले जिनमें हमें ट्रांसपोर्ट डिपो नेरवा में दिया। होमगार्ड की कम्पनी भी दी गई।

अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र बहुत ही दूर-दराज का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने पूरा आशीर्वाद रखा है। मैं इनसे यही आग्रह करूंगा कि जैसा आशीर्वाद अभी तक आपने मेरे क्षेत्र में रखा है ऐसे ही हमेशा रखें। आपके आशीर्वाद से जो 66 के0वी0ए0 लाहसाधार में कार्य चल रहा है उसमें और प्रगति हो और 33 के0वी0ए0 कुपवी में जो कार्य चल रहा है उसमें भी और प्रगति हो। इसके अलावा सिविल अस्पताल नेरवा और चौपाल में बिल्डिंग बनें, उसमें अभी कार्य चल रहा है। कम्युनिटी हैल्थ सेंटर जो आपने पी0एच0सी0 से स्तरोन्नत किया था उसकी बिल्डिंग के लिए भी प्रावधान करें क्योंकि कुपवी एक दूर-दराज वाला क्षेत्र है।

जारी एस0एस0 द्वारा-----

02.03.2016/1605/SS-AS/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा क्रमागतः

उसमें 14 पंचायतें हैं और 10 बैकवर्ड पंचायतें शामिल हैं। उसमें विकास के लिए स्पैशली हैल्थ की दृष्टि से वहां पर हॉस्पिटल का होना बहुत ही जरूरी है। पी0एच0सी0, जिन्हा, बम्टा, गुमा, लोरा-बोरा, देवत, साहन, बासाधार, पुलवाल, दलवार बलसल और पी0एच0सी0, टिक्करी में हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण जल्दी-से-जल्दी हो। हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपो माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मिला है उसके बस अड्डे के निर्माण के लिए जल्दी-से-जल्दी पैसे का प्रावधान किया जाए। हमारे क्षेत्र में जो स्कूल की बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा है, कुछ बिल्डिंगों में पैसे की कमी है उस कमी को दूर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा। जल्दी-से-जल्दी उन स्कूल बिल्डिंगों के लिए पैसे का प्रावधान किया जाए। हमारे क्षेत्र में उठाऊ पेयजल योजनाओं और उठाऊ सिंचाई योजनाओं का कार्य चल रहा है। बहुत सारी स्कीमें अभी अधूरी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो

आई0पी0एच0 विभाग है उनको ये आदेश दिए जाएं कि जो स्कीमें बहुत पुरानी हैं, 2003 से लेकर 2006 तक की हैं, उन स्कीमों को जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाए। कुछ हमारी स्कीमें ग्रेविटी की ऐसी हैं जोकि वर्ष 2007-08 से चली हैं, वे भी अधूरी हैं उनको भी पूरा किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में पहले भी लाया है और अब भी लाना चाहता हूं कि हमारी दो पंचायतें टीलर और किरण ऐसी हैं जोकि सड़क से वंचित हैं और उत्तरांचल में बसी हुई हैं। उसके निर्माण के लिए आप जल्दी-से-जल्दी पी0डब्ल्यू0डी0 और फॉरैस्ट विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरीज़ को आदेश दें। वहां के स्थानीय लोगों ने पूरी गिफ्ट डीडें विभाग को दे दी हैं और उसमें विभाग की तरफ से भी साइड विजिट हो चुकी है। उसमें जो भी कमी रही है उसको एक या दो महीने के अंदर दुरूस्त करके काम कम्लीट किया जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो कुपवी का हमारा दूर-दराज का क्षेत्र है वहां से हमारे को हैडक्वार्टर पहुंचने के लिए 8-9 घंटे लगते हैं जो हमारा ब्लॉक डिवैल्पमैंट ऑफिस चौपाल में है। अगर आप कुपवी में नया ब्लॉक डिवैल्पमैंट ऑफिस दें तो उससे हमारे पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों को सुविधा मिलेगी। जिनको दो-तीन दिन चौपाल में गंवाने पड़ते हैं उनको अपने क्षेत्र में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। नेरवा में जो उप-तहसील है उसको तहसील का दर्जा दें।

02.03.2016/1605/SS-AS/2

चौपाल में डिग्री कॉलेज खोलें। देहा में एक पुलिस थाना बहुत ही जरूरी है और एक पी0एच0सी0 हमारे बलघार में बहुत जरूरी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो हमारा दूर-दराज का क्षेत्र है और भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बिखरा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के विकास के लिए जैसे आपने आशीर्वाद दिया है वैसा ही रखें। साथ-ही-साथ जो माननीय सदस्य, श्री जगजीवन पाल जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

02.03.2016/1605/SS-AS/3

अध्यक्षः अब डॉ0 राजीव बिंदल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ है और उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

हमारी ओर से आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने जो विषय रखे अगर सरकार केवल उनके प्रति ही गम्भीरता से चिन्तन कर ले तो तीन वर्ष का और एक वर्ष का आईना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। परन्तु यदि विपक्ष की या विपक्ष के लीडर की बात को केवल और केवल आलोचना मान करके सरकार चलती है तो उससे प्रदेश का भी नुकसान होता है और किसी भी प्रकार का हित किसी का साधन नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अभिभाषण है इसके अंदर सारे विभागों के बारे में चर्चा की है। मैं एक दो विभागों के बारे में विशेष रूप से बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के संबंध में पैरा-18, 19, 20 और 21 के अंदर महामहिम महोदय से जो सरकार ने पढ़वाया है वह वास्तविकता से बहुत परे है।

जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1610/av/dc/1

डॉ.राजीव बिन्दल क्रमागत

कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र वर्ष 2012 का जिसको नीतिगत दस्तावेज के साथ दूसरे पैरा में कहा कि हमने इसके वायदे पूरे कर दिए, उसका पृष्ठ 14 की तरफ दृष्टि दौड़ाएं तो इसमें कहा गया है कि हम टांडा मैडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया लैवल पर खड़ा करेंगे। इसमें इन्होंने लिखा है कि वर्षों से जो डॉक्टर्ज और पैरा मैडिकल स्टाफ के पद खाली है जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है वह सारे-के-सारे भर दिए जायेंगे। फिर आपने सुपर स्पैशेलिटी सर्विसिज को जिला स्तर तक पहुंचाने की बात की है। मगर हालात क्या है, जो महामहिम से पढ़वाया गया तथा जो घोषणा पत्र है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विधान सभा के अंदर इस बात को स्वयं कहा है कि डॉक्टर्ज के 600 पद रिक्त है। पैरा मैडिकल के भी रिक्त हैं तथा विशेषज्ञों की भी कमी

है। अब आपने कौन सा वायदा पूरा कर दिया, यहां कुछ दिखाई नहीं देता। विधान सभा के अंदर प्रश्न संख्या 1314 लगा। इसमें आपने सारे पदों की रिक्तियों को स्वीकारा है। आज भी अनेक प्राइमरी हैल्थ सैंटर बिना डॉक्टर के हैं। आज एक सवाल श्री राम कुमार का लगा है जिसमें इन्होंने कैंसर के बारे में पूछा है। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अखबार की कटिंग भी रखी है। इन्होंने सब जगह घोषणा की कि कैंसर के रोगियों का मुफ्त इलाज किया जायेगा। हम कैंसर के रोगियों को लेकर सी0एम0ओ0 के पास गये, उनसे बोलते हैं कि इनका इलाज करो तो उन्होंने बताया कि केवल बी0पी0एल0 वालों का होगा। हमने हवाला दिया कि मंत्री जी मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं। मैं इसके लिए लगातार लड़ता रहा और इस बारे में मुझे आपके विभाग ने जो लिखित चिट्ठी दी है वह मैं यहां पढ़ना चाहूंगा। Guidelines of Health Minister, cancer patient funds इसके अंदर इन्होंने क्लीयर कट लिखा है कि हम केवल आई.जी.एम.सी. के अंदर और टांडा में कैंसर के मरीज का मुफ्त इलाज करेंगे बाकी कोई सुविधा हम नहीं दे सकते। यहां तक पी0जी0आई0 में भी कैंसर का इलाज करवाने वालों को स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त नहीं मिल रही है यानि वास्तविक स्थिति कुछ और है। हम मीडिया वालों के बहुत धन्यवादी हैं क्योंकि इन्होंने पिछले

2.3.2016/1610/av/dc/2

दिनों ऐक्सपायर्ड दवाइयों का बहुत बड़ा जखीरा निकाला है। अखबारों में खबरें छपी कि अस्पताल के टैंक में दवाइयों का जखीरा। स्टोर में ऐक्सपायर्ड लाखों की दवाइयां। अब इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, इस बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मीडिया वाले आपकी वास्तविक स्थिति को दर्शा रहे हैं। 'महिला को अस्पताल से ऐन मौके पर रैफर किया', 'अस्पताल के गेट पर महिला की डिलीवरी', 'डॉक्टर नहीं तो अस्पताल बंद कर दो', 'सिरमौर में डॉक्टर्ज के 33 पद खाली', 'पी0एच0सी0 का किया घेराव', 'हरिपुरधार

में पी0एच0सी0 में डॉक्टर 20 दिन से गायब', 'डॉक्टर छुट्टी पर वार्ड ब्वाय कर रहा है इलाज'। मैं इसको भी बंद करता हूं।

हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि हम हर जिले में सुपर स्पैशेलिटी सर्विसिज उपलब्ध करवायेंगे। मगर इस वक्त हमारी हालत क्या है? टांडा मैडिकल कॉलेज के सुपर स्पैशेलिटी विंग का उद्‌घाटन हुए दो वर्ष का समय हो गया है मगर वह विंग अभी शुरू ही नहीं हुआ।

टीसी द्वारा जारी

02.03.2016/1615/TCV/DC/1
डॉ0 राजीव बिंदल--- जारी

और जब सुपर स्पैशिलिटी विंग शुरू ही नहीं हुआ तो उद्‌घाटन किस चीज का हुआ, यह आज तक समझ में नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रो0 प्रेम कुमार जी की सरकार थी। हिमाचल प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की 115 सीटें थी। इन्होंने दोनों मैडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाकर 200 की। वर्तमान सरकार ने प्रयास किया लेकिन सीटें 200 की 200 हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 49 थी। धूमल जी की सरकार में वे सीटें 149 की गई। लेकिन वे सीटें आज भी 149 हैं। जितनी बार एस0सी0आई0 आती है, उतनी बार ऑब्जैक्शन लगाती है। सीटें बढ़ाने की जितनी एप्लीकेशन्ज़ आती है, वे सारी टर्नडाउन हो जाती है। क्योंकि उसके अन्दर एम0सी0आई0 जो कंडीशन्ज़ मांगती है, उनको पूरा करने में हम विफल हैं। इतना ही नहीं, सुपर स्पैशिलिटी की 8 सीटें केवल पिछली सरकार के समय में शुरू हुई, वे केवल आठ ही चल रही है, 8 की 9 नहीं हो सकी । 200 एम0बी0बी0एस0 की सीटें, 149 पी0जी0 की सीटें, 8 सुपर स्पैशिलिटी की सीटें हम एक भी सीट तीन, सवा तीन साल में नहीं बढ़ा पाये। हमने 19,20,21 पैराज़ के

ऊपर बहुत प्रशंसा की। कहा गया कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हररोज़ तीन मैडिकल की चर्चा होती है। पार्लियामैंट का चुनाव आया । पार्लियामैंट के चुनाव में जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए तीन नोटिस निकाले गये। सरकार बनी नहीं। एक पैसा भी पिछली केन्द्र की सरकार ने तीनों मैडिकल कॉलेजों को नहीं दिया। इसी विधान सभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने माना कि तीनों मैडिकल कॉलेजों के लिए सारे-के सारे पैसे वर्तमान सरकार ने दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में माना है। मेरे पास लिखित उत्तर है कि पिछली सरकार में कोई पैसा इसका नहीं आया। और जो ठीक हो, वह मान लेना चाहिए । अच्छी बात है, तीनों मैडिकल कॉलेज शुरू करिए। हम आपके धन्यवादी होंगे। परन्तु अध्यक्ष जी जो फीस स्ट्रक्च्चर आपने डिसाईड किया या डिसाईड कर रहे हैं, वह आप पेड-मैडिकल चलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साढ़े पांच लाख रूपया और साढ़े नौ लाख रूपया की फीस स्ट्रक्च्चर डिसाईड करके यदि गवर्नमैंट का मैडिकल आप चलाना चाहते हैं, तो सच में यह उचित नहीं होगा। ये आपका बयान है और कटिंग मेरे पास है। माननीय अध्यक्ष जी एक मेरा सुझाव कि जो तीनों मैडिकल कॉलेज हैं, उन

02.03.2016/1615/TCV/DC/2

मैडिकल कॉलेजों के लिए प्रोफैसरों,एसीस्टेंट प्रोफैसर और एसोसिएट प्रोफैसरों की कृपया सीधी भर्ती करें। यदि हम ट्रांसफर के माध्यम से उनको दूसरे कॉलेज़िज में भेजेंगे तो एक ज़गह से टोपी घूमाने का काम होगा। वे जाएंगे नहीं लेकिन जो मैडिकल कालेज़िज़ में लोग बाहर से आएंगे उनको अट्रेक्टिव पैमेंट मिलनी चाहिए। ये मेरा इसमें सुझाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पैरा-11,12,13,14 में शिक्षा का जिक्र है। शिक्षा क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए। आपने लिखा शिक्षा में गुणवत्ता है। लेकिन विधान सभा का प्रश्न-'752'

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

02.03.2016/1620/RKS/AG/1

डा0 राजीव बिन्दल ... जारी

1,161 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें एक भी कमरा यानी भवन नहीं है। आपके विभाग द्वारा दिनांक 12.03.2015 को यह प्रश्न का उत्तर आया है। 725 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें 6-10 विद्यार्थी हैं। 411 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें 5 से कम विद्यार्थी हैं। 84 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए आपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया है और महामहिम के अभिभाषण में भी इस बात को कहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी प्राकृतिक आपदा का एक मामला मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सिरमौर में नुकसान हो रहा है। प्राकृतिक आपदा के बारे में, मैंन कई बार प्रश्न किए। मैंने अब केवल नाहन का स्पैसिफाइड प्रश्न किया है कि पिछले तीन साल में कितना पैसा नाहन में कैलेमिटी रिलीफ के लिए एन.सी.आर.एफ. में गया। प्रश्न संख्याः 1160 के माध्यम से मुझे उत्तर मिला कि 4,57,04,668 रुपया गया है। अब इसमें से जो जनता को पैसा मिला वह 36,93,350 रुपया मिला। सरकारी भवनों की रिपेयर, मैंटिनेंश पर 2 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च हुआ।

अध्यक्ष महोदय, साढ़े 4 करोड़ में से 2 करोड़ 60 लाख रुपये सरकारी भवनों की मरम्मत पर खर्च हुए। जो आपका 52 पेज का उत्तर है, इसमें जिलाधीश कार्यालय और जिलाधीश भवन के रिपेयर के ऊपर लगभग-लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुआ है । इस तरह हम उस गरीब और ग्रामीण के साथ मजाक कर रहे हैं। मेरे पास जो उत्तर है उसमें आप देखिए फसल के नुकसान के लिए 750 रुपया, फसल के नुकसान के लिए 750 रुपया, यह 50 आदमियों की सूची है, जिन्हें 750 रुपया मिला है। मकान के नुकसान के लिए 1250 रुपया, 1250 रूपया, 1250 रूपया यह पूरी सूची 1250 रुपये की है (घण्टी बजी) । उसके बाद फसल के नुकसान के लिए 250 रुपया और 250 रूपये की लिस्टें हैं। भवन के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुयये खर्च हुए। हम कितने संवेदनशील हैं, यह हम अच्छी तरह देख सकते हैं। विधान सभा प्रश्न 2426 कानून व्यवस्था की स्थिति । विधान सभा प्रश्न 2546 एन.डी.पी.एस. के 772 मामले । प्रदेश के मंदिरों में 157 चोरियां, सिरमौर में 9 माह में 28 रेप। माननीय

02.03.2016/1620/RKS/AG/2

अध्यक्ष महोदय, मैं इन सबको भी छोड़ देता हूं कहीं ऐसा न हो की आपकी घण्टी फिर

से बज जाए। आज बंदरों के ऊपर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। आधा घंटा लग गया। आपने महामहिम से भी कहलवाया, घोषणा पत्र में भी कहा। परन्तु इससे भी आगे आपने लैण्टाना को उन्मूलन करने की बात महामहिम से कहलवाई और अपने घोषणा पत्र में भी कही। मैं चुनौती से कहता हूं एक भी हैक्टेयर लैण्टाना का उन्नमूलन नहीं हुआ। रादर लैण्टाना प्रदेश में बढ़ा हुआ है। यह जांच का मामला है। लैण्टाना उन्मूलन पर कहीं धांधली तो नहीं हुई है, जिस तरह बंदरों की नसबंदी के नाम पर दिखाई दे रहा है। आपने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के पृष्ठ 23 के ऊपर बड़ी जोर से कहा और

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1625/SLS-AG-1

डॉ० राजीव बिन्दल... जारी

मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि आज अगर यह सरकार सामने बैठी है तो केवल इस वायदे के आधार पर बैठी है जो आपने पृष्ठ 23 पर कहा है कि 'हम बेरोज़गारों को 1000 रुपया और 1500 रुपया बेरोज़गारी भत्ता देंगे।' आपने उन बेरोज़गारों के साथ धोखा किया। फिर आप कह रहे हैं कि हमने अपने वायदे पूरे कर दिए हैं? आपने लिखा है कि 'राज्य के ऐसे बेरोज़गार जो 10+2, स्नातक और जिनकी आय दो लाख रुपये तक है, ऐसे लोगों को 1000 रुपया प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता देंगे।' परंतु आपने महामहिम से भी गलत बुलवाया; वास्तव में यह नहीं दिया।

जो बंदरों की बात आपने अब कही, वही चुनाव घोषणा-पत्र में 3 साल पहले कही थी। 'हम अभ्यारण्य बनाएंगे' और आज फिर आप अपने उत्तर में कह रहे हैं कि हम अभ्यारण्य बनाएंगे। वह कब बनेंगे और कैसे बनेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव घोषणा-पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया गया और फिर कहा गया कि हमने इसमें किए वायदे पूरे कर दिए, आज ही नहीं बल्कि योजना की बैठक में लिखित रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है।

Speaker : Please wind up.

डॉO राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि केवल सरकार का समय राजनीतिक भाषणों के साथ चल रहा है। समाज की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता नहीं है। नाहन विधान सभा क्षेत्र में एक भी ईंच सड़क का निर्माण पिछले सवा तीन सालों में नहीं हुआ है। आप प्राथमिकता के दायरे से बाहर चले गए हैं। आज प्रदेश में पीलिया का जबरदस्त प्रकोप हुआ। माननीय अर्बन डवलपमैंट मीनिस्टर ने पहले साल के बजट के बाद प्रश्न के उत्तर में कहा था कि नाहन में सीवरेज के लिए 19 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। वह राशि आज तक नज़र नहीं आई है। आज हमने दोबारा उसको अपनी प्राथमिकता में डाला है।

02.03.2016/1625/SLS-AG-2

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम से जो बुलवाया गया वह असत्य पर आधारित है और पूरी तरह से यह सरकार हर मामले में विफल हुई है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन की बात जो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने की थी। हमारे साथियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने योजनाओं में कटौती कर दी है। केंद्र सरकार ने तो पैसा 32%से बढ़ाकर 42 % कर दिया। वर्षों से केंद्र हमारा पैसा काट रहा था। 90:10 की रेशो में जो मिलना चाहिए था। पहली बार आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 90:10 की रेशो को बरकरार करके हिमाचल प्रदेश को उसका अधिकार दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सही ढंग से अपना केस प्लीड करके केंद्र सरकार से और पैसा लें। न हम यू.सी. भेज रहे हैं और न केंद्र सरकार की योजनाओं का उपयोग कर पा रहे हैं। केवल आलोचना करके हम प्रदेश का भी अहित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सच में ऐसा प्रतीत होता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय से जो इन्होंने अभिभाषण करवाया, वह एक संवैधानिक मज़बूरी के नाते उन्होंने अवश्य किया पर अंतर्मात्मा से उनको भी यह महसूस हो रहा होगा कि जिस प्रदेश के अंदर

लगातार ड्रग्ज की और ऐसी चीजों की बढ़ोतरी हो रही है, उसके उन्मूलन की कोई चर्चा जिसमें न हो, जिस अभिभाषण के अंदर युवाओं के लिए सही दिशा की चर्चा न हो, शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा न हो, सच में इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आप लेकर आए हैं, उसका समर्थन करने में हम असमर्थ हैं।

आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आप बोलिए।

जारी...श्री गर्ग जी

02/03/2016/1630/RG/AS/1

Health Minister: Speaker, Sir, Hon'ble Member, Dr. Rajeev Bindal has misquoted the facts in this Hon'ble House. So, I would like to clarify. For the last three years, we have posted 600 MBBS Doctors and 65 Specialists. It is absolutely wrong to say that no Doctor is posted. We have opened and also upgraded many institutions. Of course, there are posts which are lying vacant. We are filling the posts in phased manner.

He said that cancer patients are not treated free of cost. In IGMC and RPGMC, Tanda all cancer patients are treated free of cost. The cancer patients are getting chemotherapy free of cost. They are getting medicines free of cost. These are the two premier institutions where the cancer patients can be treated. You have also talked about expired medicines. Of course, when it came to our notice that Chief Pharmacist of Chintpurni Hospital is throwing the expired medicines, I immediately asked the CMO to go to the spot and inspect it. That Chief Pharmacist has been placed under suspension and the explanation of Doctor is being called for.

Similarly, Sir, I would also like to mention here that 23 Primary Health

Centers were opened during your regime, but no post of Doctor, Pharmacist and Class-IV was created. For these institutions, we are also taking steps and going to the Finance Department for creation of those posts. These posts will be filled up through internalization.

You mentioned about RPGMC, Tanda, we never said that in every district hospital, there will be super specialty. Ofcourse, I am thankful to the UPA Government they had provided us Rs. 150 crore under Pradhan Mantri Swasthya Surksha Yojna, for RPGMC Tanda and infrastructure was created and it was inaugurated by Shri Gulam Nabi Azad. Thereafter, with the change of government, the present NDA Government has failed to provide equipments and machinery for that Medical College

02/03/2016/1630/RG/AS/2

that is why the Super Specialty has not been started as yet. I met three times with the Hon'ble Union Health Minister and he called a meeting of Secretary, Additional Secretary and Joint Secretary and I am happy that Shri. J.P. Nadda, Hon'ble Union Health Minister directed them to provide equipments. But I am sorry to say that not even single equipment has been sent by the Government of India. So I request you, I request Shri Dhumal Ji to use your good offices and ask the Government of India to supply the equipments so that the Super Specialty Hospital can be started at the earliest.

I am happy to say that three medical colleges were sanctioned by the UPA Government. Total 58 Medical Colleges throughout the country have been sanctioned and Himachal has got 3 medical colleges, with an amount of Rs. 190 crore each and now we are getting funds and we have decided to make those medical colleges operational, you should be highly thankful to the UPA

Government. Yes, it is a continuous process. These medical colleges were sanctioned by the UPA Government. You cannot refuse it. Now the funds are being given by the NDA Government, we are thankful to the NDA Government. I request that more funds should be given to Himachal Pradesh immediately so that the construction of these three medical colleges can be started at the earliest. I don't know from where he got this figure that 9 lakh per month and 5 lakh and 50 thousand per month is being charged; I never said it. I said that keeping in view our financial condition; we may start these three medical colleges on self financing basis. There are only 3 NRI seats, we can have 15 NRI seats in every medical college and can get 10.00 lakh Rupees and we can raise the fees also. But we have not decided as yet. Former Health Minister should know that during your period as Health Minister, in my Constituency at Chuhar Ghati there was no doctor, no pharmacist only a Class-IV was running the Primary Health Centre. I raised this issue and you had admitted it, you should also keep these things in mind while making statement. You are misquoting the facts in this House. Thank you, Sir.

Shri Rajeev Bindal in Hindi continued by MS

02/3/2016/1635/MS/AS/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं, यह मेरे हाथ में आपका पत्र है। मेरा यह कहना है कि कैंसर के मरीजों को मिलने वाला ईलाज उनको नहीं मिल रहा है। जो मरीज यहां पर आई0जी0एम0सी0 में आकर ईलाज करवाते हैं केवल उनको ही ईलाज मिलता है। यह पूरा प्रदेश बहुत बड़ा है। उसके बाद उनको दवाइयां अपने अस्पताल में लेनी पड़ती है। आपके पास कैंसर का फण्ड है लेकिन उसकी डायरैक्शन्ज आपके सी0एम0ओ0 को नहीं जा रही हैं। मैं यह लैटर यहां पर ले डाउन कर रहा हूं, आप कृपया इसकी व्यवस्था करे। दूसरा, आपने कहा कि हमने

कभी नहीं कहा कि--, आप अपना पृष्ठ संख्या 15 पढ़ें, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस सरकार स्पैशलिटी सर्विसिज को राज्य के जिला स्तर पर मुहैया करवाएगी। मैंने बातों को उसी प्रकार से कहा है। केवल सुझाव इतना है कि यह जो कैंसर पेशेंट्स का विषय राम कुमार जी ने रखा था और अपने उत्तर में आपने कहा कि एक भी कैंसर का मरीज नहीं है जबकि कैंसर के मरीज नियमित आ रहे हैं। केवल उन्हीं का ध्यान रखते हुए इसको कर दीजिएगा परन्तु कैंसर के मरीजों को ईलाज मिलना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः मैंने यही कहा कि दो मेडिकल कॉलेजिज में कीमोथेरेपी की सुविधा है। दूसरे जिला अस्पतालों में यह सुविधा नहीं है। दोनों मेडिकल कॉलेजों में कीमोथेरेपी फ्री की जाती है। दूसरे, जहां तक कैंसर की बात है, श्री राम कुमार जी ने इस बात को मेरे ध्यान में लाया है। हमने इसके लिए टीम भी गठित कर दी है और यह बात मैंने अपने जवाब में कही है। आई0जी0एम0सी0 से तीन डॉक्टर्ज की टीम गठित की गई है। वे इस क्षेत्र का दौरा करके देखेंगे कि किन वजहों से उस पर्टिकुलर एरिया में यह कैंसर हो रहा है। हमने इसके लिए पहले ही कदम उठा दिए हैं। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप जरा धीरज रखिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः आप कैंसर के पेशेंट्स के लिए फ्री ईलाज कर दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उसके लिए विचार करेंगे।

02/3/2016/1635/MS/AS/2

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री राम कुमार जी भाग लेंगे।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल जी द्वारा लाया गया और अजय महाजन जी द्वारा अनुसमर्थित किया गया, इसमें हो रही चर्चा में भाग लेने हेतु आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन तीन सालों के कार्यकाल में प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों का अथाह विकास किया है और यह माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुभव का प्रमाण है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करे तो अनेक स्कूलों को स्तरोन्नत किया गया है। अनेकों नये कॉलेजिज जहां जरूरत थी, वहां मुख्य मंत्री जी द्वारा खोले गए हैं। सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं में काफी विकास इन तीन सालों के कार्यकाल में हुआ है। स्वास्थ्य संस्थानों के भवन निर्माण में भी बहुत बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हर विधान सभा क्षेत्र में आई0टी0आई0 देने के सरकार के निर्णय के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में दो आई0टी0आइज0 माननीय मुख्य मंत्री महोदय और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री बाली जी ने दी हैं। उनमें से एक के भवन निर्माण के लिए पैसा भी मुहैया करवाया गया है। जो डिग्री कॉलेज मेरे चुनाव क्षेत्र में दिया गया है, उसके निर्माण हेतु भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि नालागढ़ मण्डल में आई0पी0एच0 विभाग में जो स्कीमें हमारी प्रायोरिटी में दी गई थी, उनमें चण्डी क्षेत्र की पेयजल स्कीम लगभग 25 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा गोयला-पन्नर स्कीम, कैथा-चढियार स्कीम,

जारी एस0एस0 द्वारा-----

02.03.2016/1640/SS-DC/1

श्री राम कुमार क्रमागतः

जोड़जी पट्टा स्कीम, झाड़माजरी स्कीम, हरिपुर संधोली स्कीम, दसोरा माज़रा पेयजल स्कीम, रायपुर जखोली स्कीम, इन सब स्कीमों में बजट पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। उलटा जो बजट बुक में प्रिंटिड बजट था, उसमें से विभाग ने कुछ पैसा डाईवर्ट किया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी, सिंचाई मंत्री, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह पैसा अगले बजट सत्र में हमारे डिवीजन को मिलना चाहिए ताकि जिन स्कीमों के लिए पैसा सैंक्शन हुआ उनका कार्य सुचारू रूप से हो सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना

चाहूंगा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के लिए जिस प्राधिकरण का गठन किया था, पिछली सरकार के समय उसके लिए केवल 5 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे आग्रह पर 13 करोड़ रुपये की वह धनराशि जो बी0बी0एन0डी0ए0 के माध्यम से लोगों के नक्शे पास करके कॉलैक्ट की गई थी, उसके अलावा 20 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया। कुल मिलाकर इस चालू वर्ष में 45 करोड़ रुपये के कार्य बी0बी0एन0डी0ए0 के माध्यम से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में हो रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, सैंकड़ों किलोमीटर सड़कें बी0बी0एन0 में हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ से प्राप्त होता है। लगभग 5 हजार ट्रकों की आवाजाही रोज़ वहां होती है। छोटी-छोटी सड़कें जो गांव के लिंक रोड थे उन पर हैवी व्हिकल्ज़ चल रहे हैं। उनके रख-रखाव के लिए ज्यादा धनराशि की ज़रूरत है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह माननीय मुख्य मंत्री जी से रहेगा कि अगला जो वित्त वर्ष है उसमें लगभग 40 करोड़ के फंड का प्रावधान बी0बी0एन0डी0ए0 को करने की कृपा करें ताकि वहां की सड़कों की दशा सुधर सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चार बड़े पुलों के लिए स्वीकृति दी है जिनका काम चल रहा है। कुछ सड़कें जो पुरानी हैं जोकि वन विभाग की वजह से फंसी हुई हैं उसमें छोटे-छोटे

02.03.2016/1640/SS-DC/2

पैच हैं। उनके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वन विभाग की एन0ओ0सीज़0 शीघ्र उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

दूसरा, एक वॉल्टेज की समस्या को देखते हुए 220 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बरोटीवाला के कुल्हाड़ीवाला गांव में बन कर तैयार है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो स्कूल माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13 अप्रैल, 2015 को घोषित किये थे और एक कॉलेज घोषित किया था, उनके फंक्शनिंग आदेश हो गये हैं। दो

स्कूलों को छोड़ कर एक नया स्कूल जामनदाडोरा और एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला, समकली जोकि 1954 से खोला है, उसमें शायद बच्चों की संख्या कम है इसलिए उसकी अपग्रेडेशन की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई। लेकिन बाकी सभी स्कूलों के फंक्शनिंग आदेश माननीय मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से हो गये हैं। डिग्री कॉलेज, जिसमें लगभग 287 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा बद्दी क्षेत्र के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9 करोड़ रुपये की लागत से नये ट्रांसफार्मर्ज़ की स्वीकृति दी है। कई क्षेत्रों में हमारे यहां लो वॉल्टेज की समस्या है। यहां पर हमारे पावर मिनिस्टर, श्री सुजान सिंह पठानिया जी बैठे हैं मैं इनका भी धन्यवादी हूं कि इन्होंने स्पैशल फंड का प्रावधान करके 9 करोड़ रुपये की स्वीकृति बद्दी क्षेत्र के लिए दी है। इसके लिए सरकार का धन्यवाद।

हमारे स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री, श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने बद्दी तहसील भवन के लिए राशि मुहैया करवाई है। सी0एच0सी0 बद्दी भवन के लिए धन स्वीकृत किया है। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि पी0डब्ल्यू0डी0 इनके पास है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में किया। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध रहेगा कि पुरानी सड़कें जो मैटल्ड हैं।

जारी श्रीमती ए0वी0

2.3.2016/1645/av/dc/1

श्री राम कुमार क्रमागत

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध रहेगा कि पुरानी मैटल्ड सड़कों के रख-रखाव के लिए जो राशि जाती है वह डिविजन वाइज जानी चाहिए। बल्कि उसमें यह होना चाहिए कि किस डिविजन में कितनी किलोमीटर सड़कें पक्की है। सरकार उस हिसाब से डिविजन वाइज धनराशि प्रोवाइड करवाए। इसके अतिरिक्त जो पंचायत द्वारा निर्मित रोड है, मैंने इस बारे में पीछे प्लानिंग की बैठक में भी यह बात रखी थी कि

पंचायत द्वारा निर्मित रोड के रख-रखाव के लिए स्पैशल फंड मुहैया करवाया जाना चाहिए और उस पैसे का डिस्ट्रिब्यूशन विधान सभा सदस्य के माध्यम से किया जाए। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश के गरीब लोगों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई है। मैं यहां पर सभी योजनाओं का विवरण नहीं दूंगा क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में काफी कुछ कह दिया है। इसमें एक विशेष योजना, जो 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग के लिए बुढ़ापा पैंशन है उनके लिए 1100 रुपये मासिक पैंशन योजना शुरू की है। मेरा इसके लिए विशेष अनुरोध रहेगा कि इसके लिए आयु घटाकर 70 वर्ष की जाए। उसमें पैंशन चाहे 500 रुपये से ही क्यों न शुरू की जाए क्योंकि 80 वर्ष तक बहुत कम बुजुर्ग पहुंच पाते हैं। इसलिए यह आयु घटाकर 70 वर्ष करने की कृपा करें ताकि हमारे ज्यादा गरीब बुजुर्गों को इस पैंशन का फायदा मिल सकें। इसके अतिरिक्त विधवा पैंशन में भी इनकम क्राइटीरिया को हटाकर सरकार की तरफ से सभी विधवाओं को पैंशन की सुविधा दी जानी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बद्दी नगर परिषद के लिए सिवरेज की एक बहुत बड़ी स्कीम दी है। उसके लिए 33 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान भी हो चुका है। वर्ष 2014 में उसका टैंडर भी हो चुका था मगर किसी कारण उसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैंने कल ही मान्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री को लिखित में भी दिया है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि टैंडर करवाकर इसका कार्य शीघ्र शुरू करने की कृपा करें। मुख्य मंत्री जी, जो कि लवाणा वैलफैयर बोर्ड

2.3.2016/1645/av/dc/2

के चेयरमैन है। मुझे अखबार के माध्यम से पीछे यह जानकारी मिली कि लवाणा वैलफेयर बोर्ड की पिछली मीटिंग में मुख्य मंत्री जी ने लवाणा समुदाय के लोगों को नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, मैं इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा।

इसके अतिरिक्त, माननीय मुख्य मंत्री जी और पठानिया जी ने दून के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोयला में 33के0वी0 का सबस्टेशन सैंक्शन किया है। अभी यहां पर वन मंत्री जी नहीं बैठे हैं। उसमें शायद अभी फॉरैस्ट डिपार्टमैंट की एन.ओ.सी. आनी बाकी है जिसकी वजह से पिछले दो वर्ष से इसका कार्य लटका हुआ है। उसको शीघ्र पूरा करवाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी आदेश करें कि इसकी एन.ओ.सी. आए। इसके अतिरिक्त दो छोटी-छोटी सड़कें जिसमें एक केवल 900 मीटर बाकी रहती है तथा एक 500 मीटर शेष रहती है। जो 500 मीटर शेष रहती है वह जौड़जी-धर्मपुर-कंडा रोड है। उसमें 500 मीटर के लिए फॉरैस्ट की एन.ओ.सी. नहीं है जिसकी वजह से वह सड़क थ्रू नहीं हो रही है। इसी तरीके से दूसरी बेयरघट-बुनाई सड़क भी अभी 900 मीटर बनने को है। 15 किलोमीटर रोड बनकर तैयार है केवल 900 मीटर शेष रहती है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इन छोटे-छोटे कार्यों के लिए डी0एफ0ओ0 को पावर दे दी जाएं। एक एकड़ से नीचे के एरिया के लिए एन0ओ0सी0 से सम्बंधित पावर डी0एफ0ओ0 को दें। इसी तरीके से बुरावालां-बटेर मार्ग पर एक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में केवल 300 मीटर रोड है और यह 6-7 वर्षों से फॉरैस्ट डिपार्टमैंट की एन0ओ0सी0 की वजह से लटका हुआ है। मेरा निवेदन रहेगा कि इसके लिए एन0ओ0सी0 देने की कृपा करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में पी0टी0ए0 पॉलिसी बनाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया था। उस पॉलिसी के तहत इन्होंने हमारे बहुत सारे पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को अध्यापक लगाया था।

टीसी द्वारा जारी

02.03.2016/1650/TCV/Dc/1

श्री राम कुमार ---- जारी

लेकिन 2008-09 में उनको हटा दिया गया। ये कोर्ट में गये और कोर्ट ने इनको बहाल

कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी टर्मीनेशन पिरियड उनका कांट्रेक्ट के लिए नहीं जोड़ा गया। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि उनका जो दो वर्ष की सेवा का नुकसान हो रहा है, उसके कारण ये कांट्रेक्ट से वचिंत रह रहे हैं। इसमें टर्मीनेशन पिरियड इनका कांट्रेक्ट में एड किया जाये। ताकि इनको इसका फायदा मिल सके। तीसरा माननीय बिंदल ने जो 90:10 की बात यहां पर की उसके लिए हम मोदी सरकार के धन्यवादी है कि उन्होंने इसको पुनः शुरू किया। लेकिन 90:10 की स्कीम यू0पी0ए0 गर्वनमैंट की थी, इसे आपकी सरकार ने बन्द कर दिया था। दोबारा अनुरोध करने पर इसे पुनः आरम्भ किया। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः श्री गोविन्द राम शर्मा, माननीय सदस्य संक्षिप्त बोलिए।

श्री गोविन्द राम शर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल को अभिभाषण की कॉपी दी गई जो उन्होंने पढ़कर सुनाई। मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, वे अपनी उपलब्धियों को गिनाकर महामहिम राज्यपाल को देते हैं और बजट जब शुरू होता है तो महामहिम राज्यपाल के माध्यम से उसमें रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो भी इस किताब के आदरणीय राज्यपाल के माध्यम से बुलाया गया, वह सच्चाई से बहुत दूर है। सरकार ने जो वायदे भी किए और जिसको सरकार ने दस्तावेज़ भी माना वह भी पूरे नहीं किए। मैं अभी देख रहा था, सत्तापक्ष के लोग अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। एक छोटी सी बात जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन अपंग इत्यादि की बातें कर रहे थे और सरकार की वाहवाही कर रहे थे। लेकिन इनको यह पता नहीं कि ये पेंशन किसने शुरू की, कब शुरू की? ये पेंशन 1977 में शुरू हुई।

02.03.2016/1650/TCV/Dc/2

इसको आदरणीय शान्ता कुमार जी ने शुरू किया और 50 से 100 रुपया किया था।

उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आदरणीय धूमल जी ने इसे 100 से 200 रुपये किया। उसके बाद जब फिर धूमल जी मुख्यमंत्री बने तो इसे 550 रुपये तक बढाया गया। 1977 से लेकर 2008 तक आपकी सरकार कई दफा बनी परन्तु आपने एक पैसा नहीं बढ़ाया। जो अभी बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद। जिसका हम स्वागत करते हैं। एल.ई.डी. बल्ब

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी

02.03.2016/1655/RKS/AG/1

श्री गोविन्द राम शर्मा ....क्रमागत

उसे आप 110 रुपये में दे रहे हैं। लोअर बाजार का दुकानदार 65 रुपये में दे रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भी इसको 65 रुपये में दे रही है। इसमें क्या घोटाला है? क्या एक बल्ब को बाहर से लाने में इतना किराया लग जाता है। इसमें जो आप 45 रुपये ज्यादा ले रहे हैं, वे कैसे ले रहे हैं? इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कोई अलोचना नहीं है। यह बात मैं सरकार के ध्यान में ला रहा हूं कि इसमें इतना फर्क कैसे आया? कहीं-न-कहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ है। आपने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। यह सब जानते हैं, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। महिलाओं को जो 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय धूमल जी की सरकार ने दिया था। महिलाओं का अगर विशेष ध्यान रखा तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा। अनुसूचित जाती मोर्चा का अगर विशेष ध्यान रखा तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा। अपंग, बजुर्गों व विधवा बहनों का ध्यान रखा तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा। आप अपने नेता को खुश करने के लिए बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहां एनक्रोचमेंट के ऊपर चर्चा चली थी। उसमें जो सेब वैली के लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि एनक्रोचमेंट कर दिया गया। कहीं 50 बिघा, कहीं 100 बीघा, कहीं150 बीघा एनक्रोचमेंट कर दिया गया है। सरकार ने

कहा था कि हम 10 बीघा तक की एनक्रोचमेंट पर विचार करेंगे। लेकिन निचले क्षेत्र में मेंरे जिला सोलन, बिलासपुर या कांगड़ा की बात आप लें तो वहां कई केसिज ऐसे हैं जहां लोगों ने 2, 3, 4 या 5 विस्वा में मकान बनाए हैं। उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। यह मकान इसलिए बनाए गए कि पटवारी ने कहा कि इस खसरा नम्बर के तहत यह आपकी जगह बनती है। उन लोगो को वहां मकान बनाए हुए 40-40, 50-50 साल हो गए। मकान बना दिया, सारी पूंजी लगा दी गई। अब उनको गिराने के ऑर्डर आ गए। उनका बिजली, पानी काट दिया गया। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। शालाघाट में श्री अमर देव जी का बिजली पानी काट दिया गया। मकान तोड़ने की कोशिश की गई। एक कसलोग में सड़क बननी थी, वहां पर भी मकान को तोड़ दिया गया। ऐसे सोलन

02.03.2016/1655/RKS/AG/2

जिला में बहुत से केसिज हैं। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो ऐप्पल वैली में गरीब लोग हैं, उनके बारे में आप चिंता करें। लेकिन जो निचले क्षेत्र के लोग हैं, जिनके पास 2, 3, 4 या 5 विस्वा जमीन 40-50 वर्षों से हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। उनको कुछ न कुछ राहत मिलें। सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही थी। सर्व शिक्षा अभियान किसने लाया। यह भी एन.डी.ए. सरकार ने लाया है। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जब केंद्र में मंत्री होते थे, उन्होंने इसकी शरुआत की थी। लेकिन आपकी सरकार ने तो लगभग इसे बंद ही कर दिया है। जहां आपने ऐप्पल के लिए, गलगल के लिए या अन्य चिजों के लिए किसानों को सब्सिडी दी, वह अच्छी बात है। हमारे सोलन जिला में टमाटर की बहुत बड़ी फसल होती है। उसमें करोड़ों रुपये का बिजनैस किसान के लिए होता है। उसमें भी अगर सब्सिडी मिलें तो मैं सरकार का आभारी रहूंगा। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अभी प्रदेश के अंदर जो एम.एल.ए. प्रायोरटी एम.एल.एज ने दी है। इन तीन वर्षों में कोई भी एम.एल.ए. प्रायोरटीज नाबार्ड से अप्रूव नहीं हुई है। खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। केवल प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ही काम हुए हैं। यह योजना भी एन.डी.ए. सरकार के समय में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी

और उसके माध्यम से फेस-1, फेस-2 का कार्य शुरू हुआ।

श्री एस.एल.एस. द्वारा .....जारी

02.03.2016/1700/SLS-AG-1

श्री गोविन्द राम शर्मा... जारी

वह पैसे सैंट्रल गवर्नमैंट से आए और यह करोड़ों रुपया मोदी सरकार ने दिया। उनको धन्यवाद करना चाहिए था। पहले तो आपके बहुत से मंत्री केंद्र में थे। आपके उन मंत्रियों ने क्या दिया? मंत्री आदरणीय शांता कुमार जी और धूमल जी हमारे मुख्य रहे। इन्होंने विकास में कोई कमी नहीं रखी। केंद्र में अभी नड्डा जी मंत्री बने। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के बारे में स्वयं कहा कि पैसा दिया गया है। फिर बिलासपुर में AIIMS की बात हुई। यहां जो 10-10 NH की सैंक्शन मिली, यह किसने दी? यह मोदी सरकार ने दी, NDA Government ने दी। हमारे समय में जो केंद्र को योजनाएं सैंक्शन के लिए भेजी गई थी, आपने उनको रुकवा कर रखा लेकिन हमारी सरकार ने आपकी योजनाओं को किया। हम सबको मिलकर विकास की चिंता करनी चाहिए, उसमें इस तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए कि यहां भाजपा का विधायक है, इसलिए यहां बंदर छोड़ दो; यहां कांग्रेस का है, इसलिए यहां बंदर न छोड़ो। महेन्द्र सिंह जी अभी इसके बारे में बता रहे थे। हम सबको मिलकर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए कि प्रदेश हित में कार्य हों। आलोचना को आलोचना के तौर पर ही नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इधर से अच्छे विचार दे रहा है तो उनको भी आपको देखना चाहिए और उसमें निर्णय लेना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

अभी सदन का निर्धारित समय समाप्त हो चुका है जबकि बोलने वाले 3-4 सदस्य और हैं। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन के समय को बढ़ा दिया जाए? अगर आप चाहें तो मैं एक घंटे तक बढ़ा सकता हूं।

(अनुमति दी गई।)

अभी इस माननीय सदन की बैठक केवल आधे घंटे के लिए बढ़ाई जाती है। गोविन्द राम जी, आप बोलिए। आपके बाद फिर कल माननीय दूसरे सदस्य चर्चा में भाग लेंगे।

02.03.2016/1700/SLS-AG-2

श्री गोविन्द राम शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं उनमें जो शिलान्यास तीन, साढ़े तीन साल पहले आदरणीय धूमल जी के माध्यम से हुए थे, माननीय मंत्रियों के माध्यम से हुए थे या कुछ मैंने किए थे, उनमें सी.एच.सी. दाड़लाघाट में एक भी ईंट तक नहीं लगी। ऐसे ही पेयजल योजना नेरी-प्लाटा है जो लगभग दो करोड़ की थी जिसका शिलान्यास हो चुका था। लेकिन अभी तक सवा तीन वर्ष इस सरकार को हो गए लेकिन उसमें एक पत्थर तक नहीं लगा। ऐसे ही बड़ोग पंचायत है जिसमें कुछ हिस्सा मलेरा क्षेत्र का भी आता है, वहां कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया। ऐसे ही जो सड़कें एम.एल.ए. प्रायरिटी में डाली गई थीं, जैसे पंजली से चमधार के लिए, उसमें अभी तक सर्वे तक नहीं किया गया। ऐसे ही PMGSY में बहुत-सी सड़कें हैं जिनके लिए जो डिपार्टमैंट्स की ज्वायंट मीटिंग होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। एम.एल.ए. प्रायरिटी में हमने जो सड़कें डालीं, जहां ज़रूरत है वहां उनकी DPR नहीं बनाई गई। जो लोग अपनी मरज़ी के अनुसार चाहते हैं उनकी DPR बना देते हैं लेकिन अप्रूव एक भी नहीं हो पाई।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत से स्कूल आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने खोले जैसे कि सत्तापक्ष के विधायक बता रहे थे। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज ही पेपर में था कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां कोई विद्यार्थी ही नहीं है और वह बंद भी हुए है। मेरा उसमें एक निवेदन है कि जहां-जहां स्कूलों की आवश्यकता है, वहां विधायक चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनसे सुझाव लिए जाएं। मैंने उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि जो हमारा घड़याच हाई स्कूल है उसमें लगभग 25 किलोमीटर दूर से एक साईड से और लगभग 14 किलोमीटर दूर दूसरी साईड से बच्चे आते हैं।

मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में कहा भी था कि आप लिखकर दो।

जारी...श्री गर्ग जी

02/03/2016/1705/RG/AS/1

श्री गोविन्द राम शर्मा-----क्रमागत
और मैंने लिखकर भी दिया। एक लगदाघाट हाई स्कूल है, वह प्लस टू के लिए दो स्कूलों के लिए इन्होंने उस दिन कहा था। इसी तरह बहुत से हमारे प्राथमिक स्कूल हैं जहां से 6-7 किलोमीटर हमारे मिडिल स्कूल को जाना पड़ता है। जैसे साही का, ऐसे ही हमारे पास एक मिडिल स्कूल, भियुखरी है वहां से 12 किलोमीटर बच्चों को दसवीं क्लास में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें पक्षपात या राजनीति न की जाए। उसमें वास्तविक स्थिति विभाग से मंगवा लें। अगर वह सही है, तो उनको अपग्रेड करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे यहां सड़कों की बहुत दुर्दशा है। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था कि जो रामशहर से जाबल तक कुनिहार को जो रोड आया, उसकी स्थिति बहुत खराब है और वहां छोटी गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है। सरकार उस तरफ भी ध्यान दे, तो ज्यादा अच्छा होगा। एक जब पक्षपात की बात आती है, तो मैं सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। हो सकता है कि ऊपर से कोई आदेश न हों। लेकिन शंका तो होती है। हमारे यहां पंचायत चुनाव हुए। नगर पंचायत के चुनाव हुए। हमारे दिग्गल में पंचायत प्रधान भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बन गया। लेकिन दूसरा कार्यकर्ता हार गया। उसने 12-14 आदमियों के ट्रांसफर की लिस्ट दे दी और उसमें से तीन ट्रांसफर्ज तो हो गईं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इन छोटी-छोटी बातों को लेकर कर्मचारियों को पीड़ित न करें। दूसरी बात यह कि नगर पंचायत अर्की में हमारी सात सीटें हैं। सात नगर पंचायत के पार्षद बनते हैं। उसमें से तीन पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बन गए, दो कांग्रेस पार्टी के आ गए, दो इन्डिपैडेंट आ गए। एक इन्डिपैटेंट ने स्वयं कहा कि विधायक जी या तो आप मेरे पास आओ या मैं आपके पास आऊं, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। हमने उसको

भारतीय जनता पार्टी ज्वाईन करा दी, सदस्यता ग्रहण भी हो गई। फिर उसने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, हम लोग साथ बैठे और तीसरे दिन उसको उठाकर ले गए, जबरदस्ती ले गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार सत्ता का दुरूपयोग न करे। जो अधिकारी इस प्रकार की गड़बड़ करे, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह चलता रहता है, आज आप उस तरफ हैं, कल हम उधर आएंगे, आज आपके मुख्य मंत्री हैं, कल हमारे मुख्य मंत्री वहां होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हमारे समय में भी ऐसा कोई पक्षपात

02/03/2016/1705/RG/AS/2

नहीं होता था और न ही आप करें, तो अच्छा होगा। हम सबको कम-से-कम ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कैसा है और अगर ऐसा गड़बड़ करेंगे, तो उसका लाभ आपको नहीं होगा, आपको नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात बहुत सोचने और विचार करने की है। वह नशे और ड्रग्ज के बारे में है उसमें भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं कई स्थानों पर अपने चुनाव क्षेत्रों में जाता हूं और जगह भी जाता हूं। आम दुकानों में शराब,अफीम और चरस बेची जा रही है और पुलिस विभाग या दूसरे विभाग इस बारे में कोई चिन्ता नहीं कर रहे हैं। वहां रात के 12.00-1.00 बजे तक लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने हमसे इस बारे में शिकायतें कीं कि हमारे परिवार यहां रहते हैं, हमारी बेटी-बहुएं यहां रहती हैं। उनको दिक्कत आती है। इस पर सरकार को कोई-न-कोई समिति गठित करके ऐसा उड़नदस्ता बनाए जो वहां जाकर चैक करे और जहां-जहां इस प्रकार की कोई गड़बड़ हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। उसको सजा मिलनी चाहिए और गलत काम को बंद कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने कहा कि यू.पी.ए. की सरकार ने सब कुछ दिया, लेकिन एन.डी.ए. की सरकार ने जो कुछ दिया उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। किसानों को जो दिया, उस बारे में कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, जनजाति की महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं आदि को जो दिया, उसके बारे में मेरे ख्याल से किसी ने पढ़ा नहीं। वृद्धों के लिए जो दिया, वह

मेरे ख्याल से किसी ने पढ़ा नहीं। केवल यू.पी.ए. के बारे में ही पढ़ा। जो यू.पी.ए. की सरकार ने अच्छे काम किए, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने काम किया, जो गरीब किसानों के लिए किया, जो वृद्धों के लिए किया, अनुसूचित जाति की महिलाओं, युवाओं के लिए जो काम किया, गरीब महिलाओं के लिए किया उसके लिए हम सबको मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। अभी माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने स्वयं कहा

एम.एस. द्वारा जारी

02/3/2016/1710/MS/AS/1

श्री गोविन्द राम शर्मा जारी---------

कि जो तीन मेडिकल कॉलेज यहां के लिए दिए उसकी नोटिफिकेशन यू0पी0ए0 सरकार ने की लेकिन उसके लिए धन हमारी मोदी सरकार ने भी दिया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं उनके लिए पैसा कौन दे रहा है? उन सड़कों का ही तो प्रदेश में काम हो रहा है बाकी काम तो ठप्प है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम एक-दूसरे पर आरोप न लगाते हुए इस विधान सभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास और उत्थान के लिए यदि मिलकर काम करेंगे तो उसका लाभ होगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः आज जो माननीय सदस्यगण बोलने से रह गए हैं वे कल बोलेंगे।

अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार 03 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 02 मार्च, 2016 **सचिव।**